राष्ट्रीय
सहारा
नई दिल्ली • बृहस्पतिवार • 26 जून • 2025
www.rashtriyasahara.com

खतरे की घंटी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस्राइल-ईरान के दरम्यान अस्थाई युद्धविराम के राजी होने के ऐलान के कुछ देर बाद ही हमले पुनः चालू हो गए। ईरानी सेना का आरोप है कि ऐलान के कुछ देर बाद ही इस्राइल की तरफ से हवाई हमलों की बौछार शुरू हो गई जिसमें चार की जान गई जबकि इस्राइल का कहना है कि ईरान की तरफ से दो मिसाइलें दागी गईं जिन्हें उसने निष्क्रिय कर दिया। हालांकि ट्रंप ने कहा था कि इस्राइल अपने लड़ाकू विमान वापस बुलाएगा और वह ईरान में शासन परिवर्तन की उम्मीद नहीं कर रहे हैं। परंतु हमलों के जारी रहने के बाद देर शाम अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय पेंटागन की खुफिया रिपोर्ट से पता चला कि परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमलों से ईरान का कार्यक्रम नष्ट नहीं हुआ है जबकि व्हाइट हाउस ने खंडन करते हुए

इसे पूरी तरह गलत कहते हुए इसे ट्रंप को नीचा दिखाने का प्रयास बताया। रिपोर्ट के अनुसार कुछ ढांचे नष्ट या क्षतिग्रस्त हुए हैं। मगर ज्यादातर सेंट्रीफ्यूज सुरक्षित हैं। शीर्ष अधिकारी पहले ही दावा कर रहे थे कि ईरान ने संवर्धित यूरेनियम का कुछ हिस्सा अन्य सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया था। ट्रंप इसे फेक न्यूज बता रहे हैं। अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने एक न्यूज चैनल से कहा, यह देशद्रोह है, इसकी जांच होनी चाहिए। हमलों के बावजूद इस्राइल और ईरान के मीडिया अपने-अपने देशों की विजय का दावा कर रहे हैं। ईरान पहले ही अमेरिका को चेता चुका था। तनाव की स्थिति में कहना जल्दबाजी होगी कि खतरा टल गया है। इराक, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब, जॉर्डन, सीरिया, कतर जैसे देशों में अपने सैन्य अड्डे ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों की रेंज में आने के कारण अमेरिका के लिए चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। वास्तव में यदि दोनों पक्ष युद्धविराम का उल्लंघन करने पर तुले हैं तो यह योजनाबद्ध प्रतिशोध वैश्विक चेतावनी का सूचक है। ट्रंप के ट्रुथ सोशल पर लिखने, कि इस्राइल बम मत गिराओ इसे उल्लघंन माना जाएगा, को इतिहास में अमेरिका की तरफ से सबसे कड़ी फटकार मानी जा रही है। परंतु इस सारे मसले में अमेरिका को स्वार्थ त्याग कर स्पष्ट रूप से विश्व शांति के प्रयास करने चाहिए। अगर वह महाशक्ति है तो चीन/रूस भी अपने कदम पीछे लौटाने की बजाए संघर्ष को प्राथमिकता देंगे। ट्रंप के आलोचक उनके इस कदम को न सिर्फ जोखिम भरा कह रहे हैं, बल्कि युद्ध शक्ति अधिनियम का उल्लंघन भी ठहरा रहे हैं। बेशक, खतरा टला नहीं है।

भू-राजनीति और अर्थव्यवस्था

मौजूदा भू-राजनीतिक तनाव से रुपये या मुद्रास्फीति पर 'काफी दबाव' पड़ने के आसार नहीं हैं। ईरान-इस्राइली के बीच युद्ध शुरू होने के बाद से ही आशंका जताई जाने लगी थीं कि तेल एवं गैस की आपूर्ति डगमगाने से वैश्विक बाजार में तेल के दाम भड़क सकते हैं, जिससे भारत जैसे तमाम विकासशील देशों में महंगाई में उछाल आ सकता है। लेकिन ग्लोबल रेटिंग एजेंसी एसएंडपी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा कीमतें बीते साल के मुकाबले अभी भी कम हैं, जिससे भारत में चालू खाता निकासी और घरेलू ऊर्जा मूल्य पर दबाव सीमित रहेगा। एसएंडपी के अर्थशास्त्री विश्रुत राणा का कहना है कि ऊर्जा की कीमतों में मामूली वृद्धि हो सकती है, लेकिन खाद्य कीमतों के बढ़ने मुद्रास्फीति पर अधिक प्रभाव पड़ेगा। भारत अपनी 85 प्रतिशत से ज्यादा कच्चे तेल की जरूरत और लगभग आधी प्राकृतिक गैस की आवश्यकता की पूर्ति आयात से करता है। इसमें भी तेल का 40 प्रतिशत से ज्यादा और गैस का आधा

आयात पश्चिम एशिया से किया जाता है। आयात पर इतनी ज्यादा निर्भरता से भू-राजनीतिक तनाव से चिंतित होना स्वाभाविक है। लेकिन एक नया अनुमान राहतकारी है। अनुमान है कि 2025 में मुद्रास्फीति औसतन 4 प्रतिशत रहेगी जो 2024 में रही 4.6 प्रतिशत से कम है। इसी प्रकार अनुमान लगाया गया है कि 2025 के अंत तक रुपया 87.5 प्रति डॉलर कमजोर हो सकता है, जो 2024 के अंत तक 86.6 प्रति डॉलर था। मौजूदा भू-राजनीतिक तनाव के कारण वैश्विक वित्तीय बाजारों में जोखिम से बचने की प्रवृत्ति बढ़ने से रुपये में अस्थिरता आने की आशंका के मद्देनजर एसएंडपी के अनुमान पुरसुकून हैं। बेशक, भारत वैश्विक अस्थिरता से अछूता नहीं रहेगा। तेल की ऊंची कीमतें भारत के चालू खाता निकासी बढ़ा सकती हैं, और भारतीय मुद्रा कमजोर हो सकती है। लेकिन अर्थव्यवस्था के बुनियादी कारक मजबूत होने तथा कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के लिए वैकल्पिक रणनीति की तैयारी से भारत को ज्यादा असर नहीं झेलने पड़ेंगे। इस बीच, सोना टूटा है, और चांदी कमजोर हुई है। शेयर बाजार भी उत्साहजनक हैं। दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पूर्ण युद्ध विराम की घोषणा के बाद बाजारों में नई उम्मीद जगी है। अफरा-तफरी मचने की स्थितियां कमजोर पड़ना तमाम अर्थव्यवस्थाओं के लिए राहत की बात है।

कटाक्ष/ सहीराम

खाने का न्योता

देखो जी, ब्याह-शादी के सीजन में न्योते का इंतजार तो रहता ही है। फिर मोदी जी को तो बिना शादी-ब्याह के भी न्योते का बड़ा इंतजार रहता है। कुछ दिन पहले ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह के न्योते का इंतजार था तो इधर जी-सेवन के सम्मेलन के न्योते का इंतजार था। ऐसे में मुसीबत हो जाती है बेचारे जयशंकर जी की, जिनका मजाक उड़ाने के लिए सुब्रहमण्यम स्वामी तो जैसे तैयार ही बैठे रहते हैं कि लो, फिर भेज दिया अपने वेटर को न्योता लाने को।

पता नहीं विदेश यात्रा के लिए न्योता जरूरी होता है या नहीं। खैर, ट्रंप साहब ने इस बार वैसे इंतजार नहीं कराया, जैसे शपथ ग्रहण पर कराया था और मोदी जी को फटाफट खाने का न्योता दे दिया। लेकिन मोदी जी नहीं गए। नहीं-नहीं रूठे नहीं थे। फिर ट्रंप साहब से रूठना तो वैसे ही बड़े जोखिम का काम है जी। खैर, मोदी जी खाने पर नहीं गए। नहीं ऐसा नहीं है कि वे हिचकते हैं। वैसे भी वह बात तो अब बहुत पुरानी हो गई जब नीतीश जी ने जीमने बैठे तो उनके सामने से भरी थाली उठा ली थी। अब तो नीतीश जी उनके पांव-वांव भी छूने लगे हैं। फिर भी मोदी जी, ट्रंप के बुलावे पर खाने पर नहीं गए। इसलिए नहीं कि आसिम मुनीर वहां पहले से ही खाने की मेज पर बैठा हुआ था। उन्होंने इस बात की शिकायत भी नहीं कि वह पहले से वहां बैठा बिरयानी खा रहा है। अगर यह शिकायत करते तो ट्रंप साहब कह सकते थे कि चिंता क्यों करते हो काजू की रोटी और लाख रुपये वाली मशरूम की सब्जी वाली आपकी पसंदीदा डिश बनवा देता हूं। कहो तो खिचड़ी, खाखरा और ढोकला मंगवा दूं। पर वह खाने पर गए नहीं। इसलिए नहीं कि ट्रंप फिर वॉर रुकवाने की तरह कह देता कि देखो, मैंने इन दोनों में दोस्ती करा दी। वैसे भी पाकिस्तान से दुश्मनी में जो मजा है, वह दोस्ती में कहां। वे तो इसलिए नहीं गए क्योंकि भगवान जगन्नाथ ने उन्हें पहले ही बुलावा भेज दिया था। भगवान जगन्नाथ ने उन्हें वैसे ही बुलाया था, जैसे मां गंगा ने उन्हें चुनाव लड़ने के लिए बनारस बुलाया था। हां, अलबत्ता चुनाव-वनाव के बाद तपस्या करने वे बिना बुलाए भी चले जाते हैं जैसे कभी केदारनाथ पंहुच जाते हैं, और कभी विवेकानंद रॉक पर पंहुच जाते हैं। वे तो बस मणिपुर ही नहीं जाते। जलकुकड़े कहते हैं कि मणिपुर अगर विदेश में होता तो वे वहां भी अवश्य ही जाते। हां?

अनमोल वचन

अतीत पे ध्यान मत दो, भविष्य के बारे में मत सोचो, अपने मन को वर्तमान क्षण पे केंद्रित करो।

-भगवान गौतम बुद्ध

आपातकाल का काला अध्याय

त्रासद स्मृति

अर्जुन राम मेघवाल

25 जून, 1975 का दिन भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण दिन था जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तानाशाह सरकार ने आंतरिक अशांति का बहाना बना कर देश में आपातकाल की घोषणा की। इसके बाद आपातकाल के 21 महीनों ने भारतवासियों की संवैधानिक विरासत की समझ को झकझोर कर रख दिया गया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने श्रीमती गांधी को 1971 के लोक सभा चुनाव में गड़बड़ी करने का दोषी ठहराते हुए उनका लोक सभा के लिए निर्वाचन अमान्य घोषित कर दिया था। इसके बाद श्रीमती गांधी के इस्तीफे की मांग बढ़ती गई और इसी बीच इंदिरा गांधी ने 25 जून, 1975 की रात तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को सादे कागज पर (बिना कैबिनेट की सहमति और आधिकारिक लेटरहेड के) अनुच्छेद 352 के तहत 'आंतरिक अशांति' के आधार पर देश में आपातकाल लागू करने की सिफारिश कर दी। यह देश की संवैधानिक शासन व्यवस्था पर सीधा प्रहार था। अगले दिन 26 जून, 1975 को सुबह 6 बजे कैबिनेट की बैठक में यह विषय औपचारिक रूप से प्रस्तुत किया गया।

इस कदम से जनता को संविधानप्रदत्त आजादी रातों-रात समाप्त कर दी गई। अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संगठन बनाने और देश के भीतर आने-जाने की स्वतंत्रता झटके में खत्म कर दी गई। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देने वाला अनुच्छेद 21 निरर्थक हो गया। सबसे दुखद यह था कि बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर ने संविधान के जिस अनुच्छेद 32-जो नागरिकों को न्यायालय जाने का अधिकार देता है-को संविधान की 'आत्मा' कहा था, उसे भी निरस्त कर दिया गया। आपातकाल के दमनचक्र के पहले शिकार वे विपक्षी नेता बने जिन्होंने सरकार की नीतियों का विरोध किया था। हजारों लोगों को कठोर मीसा (मेंटिनेंस ऑफ इंटरनल सेक्युरिटी एक्ट) और भारत रक्षा अधिनियम (डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट) के तहत जेल में डाला गया।

मेरे 90 वर्षीय दादा जी को उसी दौर में अपने रोजमर्रा के काम के दौरान गायों की देखभाल करते हुए उंगली में गहरी चोट लग गई थी जिसके इलाज के लिए उन्हें बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया लेकिन अस्पताल में उन्हें पता चला कि नसबंदी लक्ष्यों को पूरा करने के सरकारी दबाव के चलते डॉक्टर उन्हें जबरदस्ती नसबंदी के लिए तैयार कर रहे हैं। इस अमानवीय स्थिति को भांपते हुए मेरे दादा जी अस्पताल से भाग निकले। हालांकि वे बच गए लेकिन उस भयावह अनुभव ने पूरे समुदाय को गहरे डर और सदमे से भर दिया था।

दुर्भाग्यवश 1975-1977 के बीच एक करोड़ से अधिक लोगों की जबरन नसबंदी करा दी गई।

उस काले दौर में प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग केवल एक परिवार के हित में किस हद तक किया गया इसका सबसे बड़ा उदाहरण 24 मार्च, 1976 को संजय गांधी की बीकानेर यात्रा थी। न तो उनके पास कोई संवैधानिक पद था, न ही वे राजकीय अतिथि थे, फिर भी उनके स्वागत में सरकारी संसाधनों की खुल कर बर्बादी की गई। उस समय मैं डाक एवं तार विभाग में टेलीफोन ऑपरेटर था। मुझे जानकर आश्चर्य हुआ कि रैली में विशिष्ट लोगों के लिए बनाए गए मंच के नीचे अस्थायी टेलीफोन कनेक्शन लगाने के आदेश दिए गए। जबकि ऐसी व्यवस्था केवल प्रधानमंत्री के लिए की जाती है।

आपातकाल के दौरान संविधान में 38वां संशोधन करके आपातकाल की घोषणा की समीक्षा करने में न्यायालय की भूमिका समाप्त कर दी गई। अध्यादेश जारी करने के मामले में राष्ट्रपति व राज्यपाल के अधिकार बढ़ा दिए गए। इसके तुरंत बाद 10 अगस्त, 1975 को लागू किए गए 39वें संविधान संशोधन द्वारा से न्यायालयों को प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं लोक सभा अध्यक्ष जैसे उच्च पदों से जुड़े चुनावी मामलों की न्यायिक समीक्षा करने से रोक दिया गया। इस संविधान संशोधन के बाद 'एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला' के मामले की काफी चर्चा हुई थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित करने के निर्णय को सही ठहराया था। उस मामले में न्यायमूर्ति एचआर खन्ना ही अकेले न्यायाधीश थे जिन्होंने उस निर्णय से अपनी असहमति जताई थी और नागरिक स्वतंत्रता का समर्थन किया था। बाद में श्री खन्ना को वरिष्ठतम होने के बावजूद भारत का मुख्य न्यायाधीश नहीं बनाया गया।

आपातकाल के दौरान श्रीमती गांधी की सत्तालोलुपता का एक दूसरा उदाहरण 42वें संविधान संशोधन करना था जिसके माध्यम से लोक सभा का कार्यकाल पांच वर्ष से बढ़ाकर छह वर्ष कर दिया गया। ऐसा करके लोकतंत्र में जनादेश की गरिमा को और अधिक कम किया गया और आम चुनाव कराए बिना सरकार के कार्यकाल को बढ़ा दिया गया। इस संशोधन के द्वारा संविधान की उद्देशिका में तीन नये शब्द सामाजिक, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए और ऐसा करके मूल संविधान से छेड़छाड़ की गई। आपातकाल के दौरान सरकार द्वारा 48 अध्यादेश जारी किए गए और इन्हें पारित करने में संसद में चर्चा और संशोधन करने की प्रक्रिया की अनदेखी की गई।

हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी उस समय मात्र 25 वर्ष के थे, लेकिन उन्होंने साहसपूर्वक तानाशाही शासन का विरोध किया। अपनी पहचान छिपाकर अलग-अलग नामों से भूमिगत रहकर गुप्त बैठकों का आयोजन किया और आपातकाल विरोधी साहित्य व पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशन एवं वितरण में यत्न से जुटे रहे। जब आरएसएस को प्रतिबंधित कर दिए जाने के कारण इसे भूमिगत होना पड़ा तब मोदी जी ने गुजरात लोक संघर्ष समिति के महासचिव के रूप में लोकतंत्र की रक्षा हेतु अहम भूमिका निभाई। मोदी सरकार ने 11 जुलाई, 2024 को गजट अधिसूचना के माध्यम से 25 जून का दिन 'संविधान हत्या दिवस' के रूप में मनाने की घोषणा की। यह दिन उस विश्वासघात की याद दिलाता है जो आपातकाल के दौरान संविधान के मूल सिद्धांतों के साथ किया गया था। देश में आपातकाल का काला अध्याय 50 वर्ष पहले समाप्त हो गया है लेकिन वह भयावह दौर हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमें सजग प्रहरी बने रहने की आवश्यकता है।

(अर्जुन राम मेघवाल केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री हैं)

आपातकाल के 21 महीनों ने भारतवासियों की संवैधानिक विरासत की समझ को झकझोर कर रख दिया था। इंदिरा गांधी ने 25 जून, 1975 की रात तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को सादे कागज पर (बिना कैबिनेट की सहमति और आधिकारिक लेटरहेड के) अनुच्छेद 352 के तहत 'आंतरिक अशांति' के आधार पर देश में आपातकाल लागू करने की सिफारिश कर दी। यह देश की संवैधानिक शासन व्यवस्था पर सीधा प्रहार था

फिटकरी

शरीर की परेशानी करती है दूर,

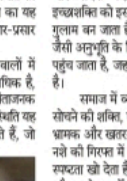

- फिटकरी पानी साफ करने या शेव के बाद लगाने तक सीमित नहीं है। चरक संहिता में फिटकरी को स्फटिक के नाम से जाना जाता है, और इसे त्रिदोषनाशक माना गया है, जिसका अर्थ है कि यह वात, पित और कफ, तीनों दोषों को शांत करती है
- नकारात्मक शक्तियों को दूर करने के लिए भी फिटकरी का टोटका आजमाया जाता है। विशेषज्ञ ही नहीं, बड़े-बुजुर्ग भी इसकी सलाह देते हैं। मान्यता है कि फिटकरी घर में रखने से 'नजर दोष' दूर होता है: माना जाता है कि इसे तकिए के नीचे रखने, जलाने या पानी में डाल कर प्रयोग करने से नकारात्मकता दूर होती है

(मीडिया इनपुट्स)

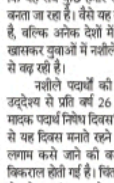

ईरानी बम से चिंतित अमेरिका ने ही काफी पहले पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम में सहयोग किया था। अब पाकिस्तान सीमा-पार आतंकवाद के लिए अपने परमाणु जखीरे को ढाल बनाए हुए है। ईरान के बम की तो महज कयासबाजी है, लेकिन तात्कालिक खतरा तो पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम है।

ब्रह्म चेलानी, सामरिक चिंतक
@Chellaney

समाज की तबाही और हमारी चुप्पी

नशा निषेध दिवस योगेश कुमार गोयल

मादक पदार्थों का सेवन केवल व्यक्ति की निजी कमजोरी नहीं, बल्कि मानवता के विरुद्ध सबसे बड़ा अपराध है। यह प्रवृत्ति शहरों के क्लबों, पार्टियों और रेव-संस्कृति तक सीमित नहीं रही, बल्कि दूरस्थ गांवों और कस्बों तक पांव पसार चुकी है। सबसे चिंता की बात यह है कि यह सब कुछ हमारे सामाजिक ढांचे का अभिन्न अंग बनता जा रहा है। वैसे यह समस्या भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अनेक देशों में भी नशीली दवाओं की तस्करी खासकर युवाओं में नशीले पदार्थों के सेवन की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है।

नशीले पदार्थों की तस्करी पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से प्रति वर्ष 26 जून को 'अंतरराष्ट्रीय नशा एवं मादक पदार्थ निषेध दिवस' मनाया जाता है, लेकिन 36 वर्षों से यह दिवस मनाते रहने के बावजूद नशे की तस्करी पर लगाम कसे जाने की बजाय यह समस्या दुनिया भर में विकराल होती गई है। चिंताजनक स्थिति यह है कि भारत में तो नशे का धंधा अब देश के नामी-गिरामी शिक्षण संस्थानों तक फैल चुका है। बड़े शहरों की रेव पार्टियां, जहां महंगे होटल और फार्म हाउसों में धुआं, शराब और कोकीन की गंध में आधुनिक युवा वर्ग डूबा होता है, इस विघटन की बीभत्स तस्वीरें पेश करती हैं। राजनीतिक संरक्षण और प्रशासनिक शिथिलता ने इन पार्टियों को लगभग 'छूट प्राप्त अड्डों' में बदल दिया है, जहां पुलिस की कार्रवाई महज दिखावा बन कर रह जाती है। रईसजादों के लिए नशे की संस्कृति 'स्टेटस सिंबल' और 'मॉडर्निटी' का पर्याय बन गई है। कोकीन जैसे पदार्थ, जिनमें गंध तक नहीं होती, उनके लिए नया फैशन स्टेटमेंट हैं, बिना यह समझे कि ये पदार्थ तंत्रिका तंत्र पर सीधा प्रहार करते हैं, और धीरे-धीरे शरीर और आत्मा को खोखला कर देते हैं। इस भयावह स्थिति को बढ़ावा देने वाला माध्यम है इंटरनेट। सूचना क्रांति का यह माध्यम नशीली दवाओं की उपलब्धता और प्रचार-प्रसार का प्लेटफॉर्म बन गया है।

भारत में नशीले पदार्थों का सेवन करने वालों में कॉलेज छात्रों की भागीदारी चालीस प्रतिशत से अधिक है, और इस आंकड़े में लड़कियों की संख्या भी चिंताजनक स्तर तक बढ़ चुकी है। अनेक कॉलेज परिसरों में स्थिति यह है कि छात्र अपने ही परिसर में नशा खरीद सकते हैं, जो

किसी संगठित गिरोह की गतिविधि से कम नहीं। छात्रों का नशे की ओर झुकाव कई कारणों से होता है-साथियों के दबाव, मॉडर्न दिखने की चाह, रोमांच की तलाश या फिर अवसाद, चिंता और मानसिक अकेलेपन की स्थिति में। चौंकाने वाली बात यह है कि वे दवाएं, जिन्हें मानव जीवन की रक्षा के लिए बनाया गया था, अब नशे के औजार के रूप में इस्तेमाल की जा रही हैं। नशीली दवाओं के सेवन से शरीर पर अनेक घातक प्रभाव होते हैं-भूख मर जाना, वजन कम होना, आंखों में लाली और सूजन, कंपकंपी, नींद न आना, चिड़चिड़ापन, अवसाद, ध्यान केंद्रित करने में असमर्थता और यहां तक कि एड्स जैसे संक्रमणों का खतरा भी। मादक पदार्थों का सेवन धीरे-धीरे व्यक्ति की इच्छाशक्ति को इस हद तक खत्म कर देता है कि वह इनका गुलाम बन जाता है। प्रारंभिक प्रयोग के बाद व्यक्ति पहले जैसी अनुभूति के लिए मात्रा बढ़ाता है और ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है, जहां उसका अस्तित्व इन पर निर्भर हो जाता है।

समाज में व्याप्त यह भ्रांति कि नशे से सृजनात्मकता, सोचने की शक्ति, एकाग्रता और यौन शक्ति में वृद्धि होती है, भ्रामक और खतरनाक मिथक है। असलियत तो यह है कि नशे की गिरफ्त में व्यक्ति धीरे-धीरे अपनी सोच-विचार की स्पष्टता खो देता है, उसकी निर्णय-क्षमता खत्म हो जाती है और उसके कार्यों में तालमेल टूट जाता है। कोई भी रसायन, जो व्यक्ति की शारीरिक या मानसिक क्रिया-प्रणाली में बदलाव लाए, मादक पदार्थ कहलाता है।

देश में नशे का सबसे गंभीर पहलू यह है कि भारत नशे का उपभोक्ता नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय तस्करी के नक्शे पर प्रमुख 'ट्रांजिट रूट' भी बन चुका है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार, ईरान और चीन जैसे देशों से होते हुए भारत के रास्ते मादक पदार्थ पश्चिमी बाजारों तक पहुंचते हैं। इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड की एक रिपोर्ट भी इस बात की पुष्टि करती है कि भारत की भौगोलिक स्थिति तस्करों के लिए सबसे सुगम मार्ग है। यह व्यापार अब वैश्विक अर्थव्यवस्था का 15 प्रतिशत हिस्सा बन चुका है। भारत में इस पर लगाम लगाने के लिए नारकोटिक्स एक्ट जैसे कठोर कानून मौजूद हैं, लेकिन अपराधी अक्सर इन कानूनों की कमियों का लाभ उठा कर बच निकलते हैं। हमें स्वीकार करना होगा कि नशा अब व्यक्तिगत समस्या नहीं, बल्कि राष्ट्रीय आपदा है। इस आपदा से लड़ने का एक ही रास्ता है जनचेतना, सहयोग और सामूहिक संकल्प। यही वह क्षण है, जब हमें यह प्रण लेना होगा कि हम नशे के हर रूप, हर स्रोत और हर समर्थन के खिलाफ खड़े होंगे, बिना डरे, बिना रुके।

कर्ता डॉ. ज्ञानानंददास स्वामी

मनुष्य की मूलभूत स्वाभाविक प्रवृत्तियां प्रायः दो रूपों में प्रकट होती हैं-एक, विनम्रता, और दूसरी, अहंकार। विनम्र व्यक्ति जानता है कि जो कुछ भी हो रहा है, उसमें उसकी भूमिका तो है, किंतु वह अकेला कर्ता नहीं है; जबकि अहंकारी सोचता है कि सब कुछ उसी के पुरुषार्थ, बुद्धि और योजना से हो रहा है। गीता में भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति गुणों के प्रभाव से प्रेरित होकर कार्य करता है, किंतु अपने को कर्ता मान बैठता है, वह मोहग्रस्त मूर्ख है। वास्तव में, संपूर्ण सृष्टि का संचालन परम शक्ति परमेश्वर द्वारा हो रहा है। मानव मात्र निमित्त है-एक यंत्र, जिसके माध्यम से कार्य संपन्न होता है। अहंकारी को यह स्वीकार करना कठिन होता है कि वह सीमित सत्ता है। वह अपनी सफलता में गुरु, मित्र, परिवार व समाज की भूमिका को नगण्य समझता है किंतु जब परिस्थितियां उसके वश से बाहर निकलने लगती हैं, तब उसे अपने 'कर्ता भाव' की सीमा का भान होने लगता है। यह बोध समय रहते हो जाए तो जीवन में गहराई आ सकती है; अन्यथा यह अक्सर किसी आघात या अपमानजनक पराजय के बाद ही आता है। विपरीत इसके, स्वयं को केवल निमित्त मानने वाला व्यक्ति संसार में रहते हुए भी भीतर से निर्लिप्त रहता है। उसके कर्मों में एक स्वाभाविकता होती है, क्योंकि उसमें प्रदर्शन की आकांक्षा नहीं होती। वह जानता है कि यदि कुछ अच्छा हुआ है तो उसके पीछे परमात्मा की कृपा है; और यदि कुछ अघटित हो गया, तो उसमें भी कोई गूढ़ तात्पर्य निहित है। ऐसे व्यक्ति की दृष्टि समत्व की ओर जाती है, जहां कर्म करते हुए भी वह कर्म के फलों से बंधता नहीं। महंत स्वामी महाराज कहते हैं-'भगवान ही सर्व कर्ता हैं, हम तो उनके हाथों की कठपुतलियां हैं।' इस विचार से जीवन में सहजता आती है, तनाव घटता है, और व्यक्ति की ऊर्जा कृपा, समर्पण और साधना में लगती है, न कि अहंकार के पोषण में। याद रहे, इसका अर्थ यह नहीं कि मनुष्य को अकर्मण्य हो जाना चाहिए। बल्कि यह समझ होनी चाहिए कि कर्म का आधार और कर्म का फल एक परमेश्वर के अधीन है। प्रभु की प्रसन्नता के लिए किया गया कर्म बंधन नहीं करता।

रीडर्स मेल

तेल राजस्व पर निर्भरता

अगले 30 से 50 वर्षों के भीतर खाड़ी के तेल संपदा से भरपूर देशों की आर्थिक गतिविधियां एकदम से बदलने वाली हैं। यूएई एवं सऊदी अरब ने इसके लिए नक्शा तैयार करना शुरू कर भी दिया है क्योंकि जीवाश्म ईंधन से छुटकारा पाने के लिए खाड़ी के तमाम देशों ने अगले 25 से 40 वर्षों के भीतर कच्चे तेल के अपने उत्पादन को शून्य करने पर हामी भर दी है। सऊदी अरब ने वास्तव में तेल राजस्व पर अपनी निर्भरता कम करने और अपनी अर्थव्यवस्था में विविधता लाने के लिए रणनीतिक बदलाव की शुरुआत की है, जैसा कि इसके विजन-2030 योजना में बताया गया है। ओमान ने सल्तनत की अर्थव्यवस्था को हाइड्रोकार्बन पर निर्भरता से दूर ले जाने के व्यापक प्रयास के तहत व्यक्तिगत आयकर लगाने की योजना बनाई है। यह कर छह सदस्यीय तेल-समृद्ध खाड़ी सहयोग परिषद में पहला होगा। 5% कर 2028 में शुरू होगा और केवल उन लोगों पर लागू होगा जो सालाना .109,000 से अधिक कमाते हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि यह क्षेत्र के अन्य देशों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा या नहीं। हालांकि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भविष्यवाणी की है कि खाड़ी देशों को सरकारी राजस्व में विविधता लाने के लिए आने वाले वर्षों में नये कर लगाने की आवश्यकता हो सकती है। आहिस्ता-आहिस्ता जीवाश्म ईंधन से हम नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे में खाड़ी के तमाम देशों के पास आय के स्रोत को बनाए रखने के लिए इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है।

जंग बहादुर सिंह, जमशेदपुर

लव जिहाद से सतर्कता जरूरी

लव जिहाद के माध्यम से हमारी सनातन संस्कृति के संस्कारों को नष्ट भ्रष्ट करने का कुचक्र वर्षों से चला आ रहा है। हिन्दू समाज को सतर्क-जागरूक और एक रहने की आवश्यकता है। हमारी बच्चियों की सही समझ एवं संस्कार विकसित होने पर ही वे इस घिनोने षड्यंत्र से बच सकती हैं। समाज स्तर पर इस संबंध में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। लव जिहाद के संबंध में फंडिंग का मामला चौंकाने वाला है। इसे सरकार द्वारा गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए। एक हिन्दू बहुल देश में उनकी बहू-बेटियों को गलत इरादे से शोषण करने वालों के विरुद्ध सरकार को ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए जो हिन्दू समाज के लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा कर सके।

ललित महालकरी, इंदौर

लोकतंत्र की खामी

व्यक्ति खाए किसी का, गुण गाए किसी का। यह बात शशि थरूर पर लागू होती है जो नरेन्द्र मोदी की तारीफ में कहते हैं कि मोदी की संवाद तत्परता भारत के लिए अहम पूंजी है। आज ऐसे ही हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तारीफ कई एसपी विधायक करते हैं। सरल भाषा में कहें तो ऐसे लोग बेपेंदी के लोटे कहे जाते हैं, जो कहीं भी नहीं ठहरते। लोकतंत्र में यही खामी है। कुछ लोग जनता द्वारा चुने जाने पर भी न अपने नेता और न उन लोगों के सगे होते हैं, जिनने उन्हें चुना है। लोकतंत्र में विपक्ष का भी अपना जनाधार होता है। इसलिए ऐसे लोगों को प्रभावपूर्ण तरीके से सदन में अपनी भूमिका निभानी चाहिए।

दिलीप कुमार गुप्ता, ई मेल से

letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा
वर्ष-34, अंक 308
सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया कादरी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3, 4 सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा 1209-1210, बारहवां तल, नरूंग हाउस, 21 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित।
। स्थानीय संपादक - रत्नेश मिश्र* ।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 011-23352369, 011-23352372, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750
आर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2024-2026
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कानूनी मामलों के लिए उत्तरदायी

विचार

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । गुरुवार, 26 जून 2025

सबसे बड़ा अधिकार

उत्तराखंड हाई कोर्ट का फैसला - कि अतिक्रमित भूमि पर रहने की वजह से किसी को मताधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता - भारतीय लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों को दोहराता है। वोटिंग का अधिकार संविधान की ओर से दिया गया है और इसका आधार जमीन का टुकड़ा नहीं हो सकता। न यह अधिकार इतना कमजोर है कि इसे किसी सरकारी फरमान से छीना जा सके।

आदेश को चुनौती । उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के कुछ लोगों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर राज्य सरकार के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें कहा गया था कि सरकारी, जंगल या किसी और जमीन पर अतिक्रमण करके रहने वालों को पंचायत चुनावों में मतदान करने या इलेक्शन लड़ने से वंचित किया जाएगा। हाई कोर्ट ने इस पर साफ किया कि संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत मताधिकार सुरक्षित है और न्यायपालिका या सरकार - कोई भी इसे वापस नहीं ले सकता।

उत्तराखंड HC का फैसला

खतरनाक मिसाल । राज्य सरकार का यह आदेश अगर लागू हो जाता, तो एक खतरनाक मिसाल बन सकता था। देश के कई हिस्सों में आज भी लाखों लोग ऐसी जमीनों पर रह रहे हैं, जिनका स्वामित्व स्पष्ट नहीं है, खासतौर पर शहरों के बीच बसी झुग्गियों, गांवों और आदिवासी क्षेत्रों में। देश में वैसे भी जमीन से जुड़े मुकदमे बरसों तक चलने के लिए बदनाम हैं। कई मामलों में पीढ़ियां बदल गईं और फैसला नहीं आया। लेकिन, इसका यह मतलब नहीं है कि इन्हें अतिक्रमणकारी बताकर इनके संवैधानिक अधिकार से वंचित कर दिया जाए।

हर अंदेशा दूर हुआ । लोकतंत्र में मताधिकार केवल चुनावी प्रक्रिया का एक अंग नहीं है। इसी से भागीदारी और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है। संविधान ने देश के लोगों को यह अधिकार दिया है। जब अनुच्छेद 326 के ड्राफ्ट आर्टिकल को शामिल किया जा रहा था, तब भी इस पर आपत्ति उठाई गई थी। एक सदस्य ने वयस्क मताधिकार का विरोध करते हुए अंदेशा जताया था कि अगर मतदाता जागरूक और शिक्षित न हुआ, तो संसदीय लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती। हालांकि वक्त ने इस अंदेशे को हवा में उड़ा दिया।

मजबूत भरोसा । हर नागरिक, जो निर्धारित आयु पूरी कर चुका हो और कुछ विशेष आधारों पर अयोग्य न हो, उसे मतदाता बनने का अधिकार है। शुरुआत में यह आयु 21 वर्ष थी, जिसे 61वें संविधान संशोधन के जरिये घटाकर 18 वर्ष किया गया। इसका मतलब कि देश का अपने लोगों पर यकीन और पक्का हुआ। जमीन से जुड़े विवाद को लेकर इस यकीन को तोड़ा नहीं जा सकता। हां, अतिक्रमण बड़ी समस्या है, पर उससे निपटने का तरीका वह नहीं, जो उत्तराखंड सरकार ने खोजा।

साड्डी दिल्ली

ओपन आर्ट गैलरी

विवेक शुक्ला

किस दिल्ली वाले ने लोधी कॉलोनी की दीवारों पर बनी खूबसूरत वॉल पेटिंग्स नहीं देखी होंगी। जो इधर से गुजरे होंगे, उन्होंने इन्हें उकेरने वाले चित्रकारों को सराहा भी होगा। उनमें से एक विलक्षण चित्रकार बीते दिनों करीब छह साल बाद फिर से लोधी कॉलोनी में अपना काम देखने आए थे। उनका नाम है यिप येव चोंग (Yip Yew Chong)। 56 साल के यिप सिंगापुर के प्रसिद्ध वॉल पेंटर हैं। वह मूल रूप से एकाउंटेंट रहे हैं।

यिप 2019 के बाद पहली बार लोधी कॉलोनी आए थे। साथ में उनकी पत्नी भी थीं। वह यहां लोधी कॉलोनी में रहने वाले अनिल नेगी के फ्लैट पर पहुंचे। जब यिप लोधी कॉलोनी की दीवारों को अपने रंगों से जिंदा कर रहे थे, उनकी अनिल नेगी से दोस्ती हो गई थी। यिप को लोधी कॉलोनी में यह देखकर सुकून हुआ कि उनका काम अभी ठीक हालत में है। उन्हें भारत आना-घूमना पसंद है। उन्होंने अपनी भारत की यात्राओं में जो देखा, उसे लोधी कॉलोनी की दीवारों पर उकेरा। यिप कहते हैं कि उनकी सबसे अधिक पहचानी जाने वाली पेंटिंग्स में से एक लोधी कॉलोनी के 7 ब्लॉक में है। इसमें पालतू जानवरों की दुकान का दृश्य है, जिसमें पिंजरे, पक्षी, दुकानदार और ग्राहक हैं। यिप अक्सर लोगों के परिवेश को चित्रित करते हैं। वह कहानी कहने के लिए दीवारों का उपयोग करते हैं।

लोधी कॉलोनी की दीवारों को रंगने की परियोजना St+art India फाउंडेशन ने शुरू की थी। इस पहल ने लोधी कॉलोनी को एक ओपन-एयर आर्ट गैलरी में बदल दिया। लोधी कॉलोनी की दीवारों पर 50 से अधिक वॉल पेंटिंग्स हैं। इन्हें देखने के लिए राजधानी और बाहर से लोग आते रहते हैं। यह कॉलोनी 1945 में सरकारी मुलाजिमों के लिए ब्रिटिश राज में बनाई गई थी। इसके बाद शायद ही अंग्रेजों ने भारत में कोई और चीज बनाई हो। यिप के साथ कुछ और चित्रकारों ने भी लोधी कॉलोनी की दीवारों पर चित्र बनाए थे। उनमें रंजीत दहिया और अनपू वर्के भी थे। अनपू ने ही आई.पी. एस्टेट में दिल्ली पुलिस के पुराने हेडक्वॉर्टर पर बनी गांधी जी की 150 फीट लंबी ब्लैक एंड वाइट पेंटिंग जर्मन चित्रकार हैंड्रिक बेकरिच के साथ मिलकर बनाई थी।

एकदा

कोई ऊंच-नीच नहीं

एक बार ईश्वरचंद्र विद्यासागर कुछ दलितों के बीच बड़े ही आत्मीय भाव से चर्चा करने में मग्न थे। तभी उनके पास नवद्वीप का एक ब्राह्मण पहुंचा। ईश्वरचंद्र को दलितों के पास बैठा देखकर वह नाक-भौंह सिकोड़ने लगा। उसका गुस्सा तब और बढ़ गया, जब दलितों ने उस पर ध्यान नहीं दिया, प्रणाम नहीं किया और ईश्वरचंद्र की बातें सुनते रहे। वह तिलमिला उठा और ऊंच-नीच का भेद समझाने लगा। यह सुनकर ईश्वरचंद्र को बुरा लगा, क्योंकि उनकी दृष्टि में इंसानों के बीच का भेद उचित नहीं था। उन्होंने कहा, 'पंडितजी, मालूम होता है कि आपको ऊंची जाति के होने का बड़ा गर्व है। लेकिन, आप यह तो जानते ही होंगे कि भगवान विष्णु ने दशावतार में एक वराह का भी अवतार है। तब क्या हमें उन बस्तियों में नहीं जाना चाहिए जहां सुअर दिखाई दें? क्या सुअरों को पालने वालों के प्रति हमें श्रद्धा और भक्तिभाव नहीं दिखाना चाहिए? मैं छुआछूत नहीं मानता। यदि ईश्वर का कोई अवतार भी आकर छुआछूत का समर्थन करे, तो भी मैं इसे मानने को तैयार नहीं हो सकता।' उच्चता और हीनता के मानदंडों को प्रकट करने वाली उनकी ये पंक्तियां बड़ी सटीक थीं। नवद्वीप के उस ब्राह्मण को भी बात जंच गई।

Subrata Dhar

संकलन : ललित गर्ग

पश्चिम एशिया में इस्राइल के प्रभाव को नियंत्रित रखने में खामेनेई के देश की अहम भूमिका

ईरान पर भारत से क्या भूल हुई है

आशीष शुक्ला

इस्राइल-ईरान युद्ध को भारत ने शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की मांग की। वहीं, पाकिस्तान ने खुलकर ईरान का समर्थन किया और अपने न्यूक्लियर बमों की भी सेवा का सुझाव दिया। पहलगाम पर इस्राइल भारत के समर्थन में खड़ा हुआ था और ईरान नहीं। शायद इसने भी इस्राइल-ईरान युद्ध में भारत और पाकिस्तान का रुख तय करने में भूमिका निभाई। लेकिन क्या भारत का इस्राइल का समर्थन करना सही है? इसके क्या परिणाम हो सकते हैं?

भारत की चाह । ईरान के जरिये रूस और भारत इंटरनैशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर (INSTC) के निर्माण में जुटे हुए हैं। इससे भारत के लिए पूरे यूरोप और एशिया में व्यापार का मार्ग खुलेगा। सेंट्रल एशिया के देशों तक भी पहुंच बनेगी। मगर यह मसला फिर भी मामूली है। अगर ईरान की मौजूदा सरकार गई, तो रूस के लिए भारत के बजाय पाकिस्तान का आकर्षण बढ़ जाएगा। रूस और चीन में अभिन्न दोस्ती है पर रूस, चीन का पिट्ठू बनने को तैयार नहीं। इसलिए वह भारत के और भी करीब आया है। भारत भी अमेरिकी खेमे में पूरी तरह से जाना नहीं चाहता। रूस और भारत की सोच यह है कि अमेरिका और चीन के बीच के द्विध्रुवीय विभाजन की स्थिति में भारत और रूस का एक तीसरा कोण होना चाहिए, जिससे ग्लोबल साउथ के नेतृत्व में उनका साझा रहे। मगर ये समीकरण बिखर जाएंगे अगर ईरान में इस्राइल और अमेरिका के मन की सरकार बनी।

File Photo

ईरान की अहमियत । आज विश्व की एक धुरी ईरान भी है। चीन और रूस के लिए ईरान का महत्व क्या है, इसे यूं समझिए कि चीन ने ईरान से ईंधन सप्लाई के लिए 25 सालों में 400 बिलियन डॉलर का करार किया है। विश्व के मैप पर एक निगाह ही आपको बता देगी कि अगर ईरान गया तो यहां से आतंकवादियों की एक फौज रूस के नीचे के हिस्से में Caucasus के जरिये घुसपैठ करके तबाही मचाएगी। यही हाल चीन का होगा, जहां उसके शिनच्यांग प्रांत से आतंकवादी घुसपैठ करेंगे।

अंतरराष्ट्रीय कानून । ऐसे में ब्रिक्स का क्या होगा और क्या होगा बहुध्रुवीयता का। पर उसूल छोड़िए, अंतरराष्ट्रीय कानून के हिसाब से भी भारत की इस्राइल-ईरान मसले में तटस्थता हजम नहीं हो रही है। अंतरराष्ट्रीय कानून की निगाह में इस्राइल का 13 जून का आक्रमण अवैध है। संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर का आर्टिकल 2 (4) इसे गलत मानता है। आर्टिकल 51 कहता है कि आप तभी आक्रमण कर सकते है जब आपके ऊपर खुद उस देश की तरफ से आक्रमण हुआ हो। इस कानून के अनुसार ईरान का आक्रमण तो सही साबित किया जा सकता है, इस्राइल का अतिक्रमण नहीं।

परमाणु कार्यक्रम । इस्राइल का कहना है कि अगर वह ईरान पर आक्रमण नहीं करता तो ईरान न्यूक्लियर बम बनाने के इतने करीब था कि वह उस पर जल्द ही आक्रमण कर देता। मगर इसका कोई प्रमाण उसने विश्व के सामने नहीं रखा है। ध्यान रहे, अमेरिका और ईरान के बीच इस विषय में बातचीत चल रही थी। मार्च में ट्रंप प्रशासन की नैशनल इंटेलिजेंस की मुखिया तुलसी गबार्ड ने कहा था कि ईरान न्यूक्लियर बम नहीं बना रहा है। फिर जब जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन (JCPOA) का करार होना था तब 2018 में अमेरिका खुद मेज से उठ कर चला गया था। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ही थे।

NPT का दायरा । फिर nuclear proliferation treaty (NPT) को ईरान ने स्वीकारा है, इस्राइल ने नहीं। इस अनुबंध के अनुसार अंतरराष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कभी भी आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम की जांच-पड़ताल कर सकती है। माना जाता है कि इस्राइल के पास कई न्यूक्लियर बम हैं पर उसने अपने को इस जांच से मुक्त रखा है। एक बात और- इस्राइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू 1992 से कहते आए हैं कि ईरान का अब न्यूक्लियर बम बना ही समझिए। यह दावा वे औपचारिक रूप से 1992, 1995, 2002, 2009, 2012 और 2015 में कर चुके हैं। भूलना नहीं चाहिए कि बीच में इसी तरह का दावा उन्होंने इराक को लेकर भी किया था। इराक की बर्बादी के बाद यह मालूम हुआ कि वहां कोई खतरनाक हथियार नहीं थे।

राह का कांटा । अगर ईरान में सत्ता बदली तो मिडल ईस्ट में इस्राइल का वर्चस्व हो जाएगा। सुन्नी राष्ट्र वैसे ही इस्राइल से डरते हैं। सारे तेल और गैस पर उसका कब्जा हो जाएगा। विश्व के सबसे बहुमूल्य समुद्री रास्तों पर भी उसका नियंत्रण होगा। सिर्फ ईरान ही इस्राइल के रास्ते का कांटा है। उसी ने इस्राइल की नाक में दम करके रखा था।

बदलती हवा का रुख । भारत को चाहिए कि बदलती हवा के रुख को समझे। ईरान से वह तेल भले ही ना लेता हो, पर उसके महत्व को जरूर समझे। विदेश नीति ही क्या, हमारे भविष्य के लिए भी हमें ईरान और इस्राइल में कौन सा फायदे का सौदा है, यह समझने में गलती नहीं करनी चाहिए।

(लेखक भू-राजनीतिक मामलों के जानकार हैं)

क्या है अहमियत

- ईरान मध्यपूर्व में शक्ति संतुलन बनाए हुए है
- इस्राइली वर्चस्व भारत के विकल्प कम करेगा
- दुनिया में तीसरे ध्रुव की गुंजाइश कम होगी

यूं क़लम हुआ 'इलाहाबाद के कसाई' का सिर

कृष्ण प्रताप सिंह

1857 के गदर में अवध से ईस्ट इंडिया कंपनी के पांव उखाड़ने के बाद बागी ठीक से राहत की सांस भी नहीं ले पाए थे कि उनका कंपनी के सेनानायकों के जवाबी हमलों से सामना होने लगा। ये हमले योजनाबद्ध तो थे ही, अस्त्र-शस्त्रों के मामले में भी उन्हें बागियों की फौज पर बढ़त हासिल थी। इसके बावजूद कंपनी के सेनानायक खासे परेशान थे क्योंकि न सिर्फ लखनऊ बल्कि इलाहाबाद व कानपुर के पेचीदा हालात भी उनके लिए सिरदर्द बने हुए थे। उन्होंने सबसे पहले इलाहाबाद पर खोई अपनी पकड़ फिर बनाने की सोची और अपने सबसे दुस्साहसी कर्नल जेम्स जार्ज स्मिथ नील को बनारस से वहां भेजा।

जून की चिलचिलाती धूप में नील वहां पहुंचा तो उसने न सिर्फ इलाहाबाद को आजाद घोषित कर अपनी सरकार चला रहे बागियों बल्कि आम लोगों पर भी इतना कहर बरपाया कि लोग उसको 'इलाहाबाद का कसाई' कहने लगे। उसने गंगा के तट पर स्थित राजा टोडरमल के आलीशान मोतीमहल के सातों फाटक तोपों से उड़ा दिए, फिर अंदर घुसकर खूब लूट-पाट की। समदाबाद नामक गांव में बागियों के हमदर्द मेवातियों को साम-दाम-दंड-भेद सब बरतकर अपनी ओर मिलाने की कोशिश की और वे नहीं माने तो भीषण मार-काट के बाद गांव को तहस-नहस करके वहां 'कंपनीबाग' बना दिया।

इसी बीच जुलाई में कानपुर में नानासाहब की फौज को खदेड़कर कंपनी ने फिर अपनी सत्ता स्थापित कर ली तो वहां अपनी हनक बनाने के लिए नील को बुलाया। वहां नानासाहब के सैनिकों पर ऐतिहासिक बीवीघर (अब नानाराव पार्क) में सौ से ज्यादा अंग्रेज औरतों व बच्चों को बेरहमी से मार डालने के आरोप थे। नील ने बीवीघर के अहाते में ही बरगद के पेड़ पर 133 निर्दोष भारतीयों को फांसी पर लटका दिया। जो भी पकड़ में आता, पहले उससे बीवीघर में जमे हुए खून को जीभ से चाटने को कहा जाता। हुक्म मानने के बाद भी उसे बख्शा नहीं जाता।

अवधनामा

लेकिन सितंबर में जब रेजिडेंसी में कैद अंग्रेजों को मुक्त कराने के लिए जनरल हैवलॉक और नील बड़े लाव-लश्कर के साथ लखनऊ गए तो लगता है कि नील के पाप का घड़ा भर चुका था। 25 सितंबर को घोड़े पर सवार वह लखनऊ में घुसा तो कैसरबाग के शेर दरवाजे के पास बागी सेना का एक तलवारबाज उसके खून से अपनी तलवार की प्यास बुझाने को बेकरार घात लगाए बैठा था। इस तलवारबाज का नाम था महमूद मिर्जा। वह नवाबी फौज में कमांडेंट हुआ करता था। उसका बेटा भी नवाबी फौज में था। कंपनी ने 1856 में नवाब वाजिद अली शाह को अपदस्थ कर उनका राज हड़प लिया तो बेटा आगा मिर्जा ने बागी होकर गुरिल्ला युद्ध शुरू कर दिया था। ऐशबाग में हुई एक भिड़ंत के बाद उसे पकड़ लिया गया और कुछ ही दिनों बाद मच्छी भवन के गेट पर फांसी दे दी गई। बेटे को खोने के बाद महमूद मिर्जा बदले की आग से भर गया और मरते दम तक अंग्रेजों से दो-दो हाथ करने का अरमान रखता था।

जैसे ही नील कैसरबाग के उत्तरी छोर की ऊंची मेहराबदार छत से होकर शेर दरवाजे के पास पहुंचा गुजरा, महमूद ने उसकी गरदन पर तलवार का ऐसा वार किया कि उसका सिर धड़ से अलग होकर दूर जा गिरा। कुछ इतिहासकारों के अनुसार महमूद ने नील को तलवार से नहीं, बंदूक से गोली चलाकर मारा था, लेकिन उसकी तलवारबाजी की शोहरत के मद्देनजर यह बात सही नहीं लगती। बहरहाल, नील के मरते ही कंपनी की सेना में हाहाकार मच गया। लेकिन इस सबके बीच भी उसके कुछ सैनिक महमूद पर टूट पड़े और उसे भी मौत के घाट उतार दिया।

पर्सिया से ईरान तक, ऐसा रहा सफ़र

साल 1935 में ईरान की सरकार ने औपचारिक रूप से आग्रह किया कि उनके देश को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ईरान नाम से पुकारा जाए। हालांकि इतिहासकारों के लिए यह आज भी पर्सिया ही है। पिछले 3000 बरसों में ईरान की राजनीतिक व्यवस्थाएं, धर्म, समाज और संस्कृति कई बार बदली।

पहली सभ्यता । ईरान के दक्षिण-पश्चिमी क्षेत्र में Elamite Civilization का विकास लगभग 3000 ईसा पूर्व में हुआ। फिर लगभग दो हजार ईसा पूर्व में आर्य-ईरानी जनजातियां इस इलाके में आईं और Median Kingdom स्थापित किया। मीड पहले शासक थे, जिन्होंने ईरान को एकजुट किया। लेकिन, 550 ईसा पूर्व में साइरस द्वितीय (Cyrus II) के नेतृत्व में पारसी सत्ता ने मीड शासन को समाप्त कर दिया। साइरस ने Achaemenid Empire खड़ा किया।

टाइम मशीन

सिकंदर का हमला । साइरस के उत्तराधिकारी थे Darius the Great। इनके शासनकाल में यह साम्राज्य सिंधु घाटी और मध्य एशिया से लेकर मिस्र और यूरोप के थ्रेस तक फैला हुआ था। इसी दौरान प्राचीन ईरान का प्रमुख धर्म जरथुस्त्र भी बढ़ रहा था। फिर आया सिकंदर का तूफान, जिसने 330 ईसा पूर्व में आखिरी Achaemenid शासक को हरा दिया। हालांकि सिकंदर की अचानक मौत के बाद उसके सेनापतियों ने जीती हुई जमीन को आपस में बांट लिया। ईरान पर यूनानी सेल्यूकिड साम्राज्य का नियंत्रण हो गया।

अरब आक्रमण । ग्रीक शासन ज्यादा दिन नहीं चला। 247 ईसा पूर्व से 224 ईस्वी तक पार्थियन सत्ता में रहे और 224 से 651 ईस्वी तक सासानियन वंश ने शासन संभाला। सासानियन ने जरथुस्त्र को राज्य धर्म घोषित कर दिया। 651 ईस्वी में अरब की मुस्लिम सेनाओं ने ईरान पर आक्रमण किया और वहां राशिदुन व उमय्यद खिलाफतों का शासन शुरू हुआ। 8वीं-9वीं शताब्दी तक अधिकांश ईरानियों ने इस्लाम अपना लिया था।

शिया बना राजधर्म । 12वीं सदी में मंगोलों और 14वीं शताब्दी में अमीर तैमूर ने ईरान को बहुत नुकसान पहुंचाया। हालांकि ईरानी संस्कृति का लचीलापन था कि आक्रमणकारी भी फारसी संस्कृति में घुलमिल गए। 1501 में जब Shah Ismail I के नेतृत्व में सफवी वंश आया, तो सबसे बड़ा बदलाव हुआ - उन्होंने शिया इस्लाम को राजधर्म घोषित कर दिया। उस वक्त तक अधिकांश ईरानी सुन्नी थे। यह साम्राज्य 17वीं सदी के आखिर तक खत्म हुआ। बीच में एक अरसा अफगान जनजातियों और फिर नादिर शाह अफ्शार का राज रहा। नादिर की मौत से ईरान बिखर गया था, जिसे करीम खान जंद ने फिर एकजुट किया। जंद के बाद काजार वंश (1796–1925) आया, जिसने 1794 में तेहरान को अपनी राजधानी बना लिया।

संवैधानिक क्रांति । 1905-1907 में फारसी संवैधानिक क्रांति हुई और शाह ने संविधान को मानने की सहमति दी। 1925 में पहलवी वंश की स्थापना हुई। 1978 ईरानी क्रांति ने राजशाही व्यवस्था का अंत कर दिया, निर्वासन में रह रहे शिया धर्मगुरु अयातुल्ला रुहोल्लाह खोमैनी देश लौटे और इस्लामी गणराज्य की स्थापना की।

कर सकती हैं कायापलट

प्रणव प्रियदर्शी

खुद अपने अनुभव ने भी रिद्धिमा सावंत को यह बताया है कि किसी लड़की का स्वतंत्र ढंग से मनचाहा करियर चुनना जितना मुश्किल है, वहां निरंतर आगे बढ़ते रहना भी उतना ही चुनौतीपूर्ण है। वह बताती हैं कि इंजीनियरिंग कॉलेजों से हर साल उत्साह और ऊर्जा से भरी हुई लड़कियां वर्कफोर्स का हिस्सा बनती हैं। लेकिन पहला जॉब लेने के बाद पांच साल की अवधि पूरी होते-होते इनका एक बड़ा हिस्सा चुपचाप वर्कफोर्स से निकल जाता है। वर्कप्लेस के नियमों में लचीलेपन की कमी और मन की गहराइयों में छुपे पूर्वाग्रहों के जब-तब दिखने वाले असर से लेकर समाज व परिवार की अलग अपेक्षाओं और तमाम मुश्किलात से लड़ते हुए भी चमक बिखेरती रोल मॉडल्स का अभाव तक- कई तरह की वजहें इसके पीछे होती हैं। रिद्धिमा कहती हैं कि लड़कियों को वर्कफोर्स का हिस्सा बनाना और उन्हें साथ बनाए रखना एक ऐसी चीज है जिसके लिए कंपनियों को फ्रेमवर्क तैयार करने की जरूरत है। उन्होंने इंजीनियर के तौर पर अपना करियर शुरू किया और आज देश की लीडिंग आईटी सॉल्यूशंस कंपनी ओरिएंट टेक्नॉलजीज लिमिटेड में चीफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफिसर की भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने अपने यहां ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करने पर जोर दिया जो विमिन इंजीनियर्स को ताकत दे, सक्षम बनाए और उनके साथ विकसित होता चले। हालांकि इसी बिंदु पर रिद्धिमा यह भी कहती हैं कि कंपनियों पर ही सारी जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती। समाज और परिवार को भी अपनी भूमिका पर गौर करना होगा। लेकिन फिर भी सही अवसर और उपयुक्त माहौल मुहैया कराते और उनमें भरोसा जगाते हुए चला जाए तो ये विमिन इंजीनियर्स न केवल अपने करियर को ऊंचाई दे सकती हैं बल्कि टेक्नॉलजी की दुनिया का कायापलट करने में भी अहम भूमिका निभा सकती हैं।

रिद्धिमा सावंत

आधी दुनिया

रीडर्स मेल

www.edit.nbt.in

■ भरोसा नहीं होता

25 जून का संपादकीय 'स्थायी शांति चाहिए' पढ़ा। इसमें कोई दो राय नहीं कि पूरा विश्व इस युद्धविराम को स्थायी रूप लेते देखना चाहता है। फिर भी, इसे लेकर मन में संदेह बना हुआ है। उदाहरण के तौर पर देखें तो इस्राइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध में भी ऐसा ही हुआ कि सीजफायर की घोषणा हुई और उसके बाद फिर से युद्ध चालू हो गया। आज जब दुनिया में युद्ध के कई फ्रंट खुले हुए हैं तो ईरान और इस्राइल के बीच शांति होना ही सबके लिए लाभकारी है। लेकिन यह कहने में जितना आसान लगता है, उतना है नहीं। जमीनी तौर पर इसका फलीभूत होना इस बात पर निर्भर करता है कि ईरान का परमाणु हथियार के प्रति रवैया क्या रहता है और अमेरिका और कतर जैसे देश कैसे दोनों पक्षों को विश्वास में लेकर बातचीत के माध्यम से समझौता कराते हैं।

बाल गोविंद, नोएडा

■ सचाई क्या है

ट्रंप ने ईरान-इस्राइल के बीच युद्ध विराम करा कर दुनिया में अमन-चैन स्थापित करने में बहुमूल्य योगदान दिया है। अब अगर ट्रंप किसी तरह यूक्रेन और रूस के बीच भी युद्ध विराम करा देते हैं तो हिंसा के जरिए शांति स्थापित कराने का अपना दावा ज्यादा जोरदार अंदाज में दोहरा पाएंगे। ट्रंप का शांति स्थापित कराने का तरीका काफी हद तक अंडरवर्ल्ड जैसा है। ताकत के जोर पर, अपनी शर्तों पर और धमकी के अंदाज में वह संबंधित देशों के ऊपर शांति लादने की कोशिश करते हैं। हालांकि अक्सर उनके आदेश निष्प्रभावी साबित हुए हैं और उनके दावे भी खोखले निकले हैं।

बृजेश माथुर, गाजियाबाद

nbtedit@timesofindia.com पर अपनी राय नाम-पते के साथ मेल करें।

अंतिम पत्र

गुजरात से महाराष्ट्र तक दिखा बारिश का कहर - एक खबर

- मॉनसून गर्मी से राहत देने आया है या हमें और सताने!

विपुल रावत

THE SPEAKING TREE

और पढ़ने के लिए देखें www.speakingtree.nbt.in

सच्चा लीडर ख़ुद को कंडक्टर मानता है, हीरो नहीं

देवेंद्रराज सुथार

जब हमें कोई बड़ी सफलता मिलती है, तो पहले कुछ दिन बहुत अच्छा लगता है। फिर धीरे-धीरे कुछ खाली-सा लगने लगता है। सफलता मिलने पर पहले जो खुशी थी, या मन में उमंग था, वह गायब हो गया। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि बड़ा बनना है, सबसे आगे निकलना है। और हम आगे जाने के लिए दौड़ते रहते हैं। कभी सोचा है कि यह दौड़ हमें कहां ले जा रही है? जो लोग बहुत सफल हैं, उनके चेहरे पर कभी-कभी एक अजीब बेचैनी दिखती है। जैसे कुछ मिल गया हो, पर फिर भी कुछ छूट गया हो।

मान लीजिए, आपको कोई बड़ी सफलता मिली। लोग तारीफ कर रहे हैं, बधाइयां आ रही हैं। शुरू में तो लगता है- वाह! मैंने कर दिखाया। और उसके बाद मन के किसी कोने से यह आवाज आने लगती है, 'मैं तो कमाल का हूं, मेरे बिना यह काम हो ही नहीं सकता था, बाकी लोग तो मेरे सामने कुछ भी नहीं।' यहीं से खतरा शुरू होता है। हम भूल जाते हैं कि हमारी सफलता में कितने लोगों का हाथ था - हमारे माता-पिता, शिक्षक, दोस्त, यहां तक कि वे लोग भी जिन्होंने हमारा विरोध किया और हमें और मेहनत करने पर मजबूर कर दिया। शायद हम से कोई सफलता पाने के बाद उन्हें जताना भी चाहते हैं।

कबीर की बात याद करें - 'जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाहिं।' यह 'मैं' ही तो वह चीज है, जो हमें सच को देखने नहीं देती। यही मैं वह अहंकार है जो मन में बैठ जाता है और बाद में वह टूटता है और खुशियां गायब हो जाती हैं। खुश वही हैं, जो अपनी सफलता को बांटते हैं। जो कहते हैं कि 'यह सिर्फ मेरी वजह से नहीं हुआ।' जो अपनी टीम को क्रेडिट देते हैं, अपने परिवार को धन्यवाद देते हैं, वे खुश दिखते हैं। एक बड़ी कंपनी के CEO से जब पूछा गया, 'आपको कभी लगता है कि आप बहुत स्पेशल हैं?' वह हंसे और बोले, 'मैं तो बस एक Conductor हूं।' सच्ची लीडरशिप यही है, खुद को Conductor समझना, Hero नहीं।

सफलता तो सभी पाना चाहते हैं। इसमें गलत क्या है, पर उसे सिर पर चढ़ाना गलत है। कामयाबी मिलने के बाद याद रखना चाहिए कि यह सिर्फ हमारी वजह से नहीं हुआ। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लोग, यहां तक कि समय और परिस्थितियां भी हमारे साथ थीं। और सबसे बड़ी बात - अगर आज हम ऊपर हैं, तो कल नीचे भी हो सकते हैं। जीवन पहिये की तरह है, चलता रहता है। इसी पहिये से कभी चढ़ाव पार करना है, कभी ढलान से भी उतरना है। जब बुरा समय आए, तो हिम्मत न हारिए।

हमारे पास हमारा असली गुण है, विनम्रता। जिसके पास दिखावे के अलावा कुछ नहीं, वह अहंकार के कब्जे में फंस जाता है। सच यही है कि अहंकार और कामयाबी साथ-साथ नहीं चलती। यह प्रकृति का नियम है और प्रकृति के नियम कभी गलत नहीं होते।

नेता वही है, जो सही रास्ता जानता है, उस पर चलता है और लोगों को सही राह दिखाता है। -जॉन मैक्सवेल

संयुक्त राष्ट्र की ताजा एसडीजी रिपोर्ट में भारत का 2024 की तुलना में बड़ी छलांग लगाते हुए शीर्ष सौ देशों में शामिल होना देश की विकास नीतियों और सतत विकास लक्ष्यों के बीच सधते संतुलन को ही दर्शाता है। हालांकि कुछ चुनौतियों से निपटना अभी बाकी है।

संतुलन बना रहे

संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क (यूएन-एसडीएसएन) द्वारा जारी ताजा सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) रिपोर्ट में शीर्ष सौ देशों में शामिल होने की ऐतिहासिक उपलब्धि भारत की प्रगति को तो खैर दर्शाती ही है, इससे यह संकेत भी मिलता है कि देश सतत विकास के वैश्विक लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में सही रास्ते पर है। उल्लेखनीय है कि भारत ने पहली बार सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में कुल 193 देशों में 99 वां स्थान हासिल किया है, जो 2024 के 109वें स्थान से एक बड़ी छलांग है, जो महज आंकड़ों में नहीं, भारत के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय क्षेत्रों में हो रहे गहरे और व्यापक बदलावों में भी दिखती है। दरअसल, 2015 में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों द्वारा अपनाए गए 17 सतत विकास लक्ष्यों का उद्देश्य 2030 तक निर्धनता-उन्मूलन, असमानता में कमी, स्वास्थ्य व शिक्षा में सुधार, पर्यावरण संरक्षण और वैश्विक सहयोग को प्रगाढ़ करना है। भारत की आबादी, विविधता और सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को देखते हुए इन लक्ष्यों की प्राप्ति एक जटिल चुनौती रही है। फिर भी, हालिया एसडीजी रैंकिंग में भारत की छलांग दर्शाती है कि नीति-निर्माण और उनके कार्यान्वयन, दोनों ही मोर्चों पर देश में ठोस प्रगति हो रही है। भारत ने खासकर गरीबी में गिरावट, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, स्वच्छता अभियान, स्वच्छ ऊर्जा को अपनाना और लैंगिक समानता जैसे कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय सुधार किए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चार करोड़ से अधिक घरों के निर्माण हों, उज्ज्वला योजना के तहत दस करोड़ से अधिक परिवारों को एलपीजी कनेक्शन, जल जीवन मिशन के तहत करीब पंद्रह करोड़ घरों तक पाईप से पानी पहुंचाने की व्यवस्था हो, स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्यारह करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण हो या फिर आयुष्मान भारत योजना के तहत करीब 55 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य बीमा इत्यादि कार्यक्रमों ने सीधे तौर पर करोड़ों भारतीयों के जीवन में बदलाव लाया है। इसके अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा

उत्पादन में भारत की बढ़ती हिस्सेदारी ने भी पर्यावरणीय लक्ष्यों को मजबूती दी है। गौरतलब है कि 2015 से 2024 के बीच भारत ने जीडीपी का 4.1 से 4.6 फीसदी शिक्षा के लिए आवंटित किया, जिसकी यूनेस्को तक ने तारीफ तो की ही है, यह 2030 के शिक्षा संबंधी लक्ष्यों के भी अनुरूप है। इसके बावजूद भारत को मोटापा दर, जैव विविधता हानि और लैंगिक समानता जैसे क्षेत्रों में खास ध्यान देने की जरूरत है, जहां भारत का स्कोर काफी कम है। इसके अतिरिक्त, वैश्विक स्तर पर केवल 17 फीसदी लक्ष्यों के 2030 तक पूरे होने की संभावना भी चिंता का विषय है, जो इन मुद्दों को लेकर विभिन्न देशों के अगंभीर रवैये को ही दिखाती है। भारत के लिए जरूरी है कि वह अपनी गति को बनाए रखते हुए 2030 तक शेष लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ता रहे।

क्या युद्ध ही वर्तमान का प्रासंगिक मूल्य है

आतंकवाद और घृणा से घिरते एवं फिर हिंसक होते इस समाज को कोई बर्बाद होने से बचाना क्यों नहीं चाहता? क्यों आखिर युद्ध ही सभी मसलों का हल है? और अगर है, तो फिर ये मसले हल क्यों नहीं होते? इन सबके बीच शांति क्या अप्रचलित मूल्य बन चुकी है?

युद्ध में डूबी दुनिया को क्या याद करना चाहिए? क्लाउड लेवी स्ट्रॉस की चेतावनी कि 'दुनिया इन्सानों के बगैर शुरू हुई थी और इन्सानों के बगैर ही खत्म होगी।' आखिर क्यों नहीं? परमाणु बम और मिसाइलों की रेंज बताती इस दुनिया में कोई ऐसा नेतृत्व है, जिसे यकीन हो कि इस दुनिया को बचाना ही एक नेतृत्व के लिए सब कुछ होता है। और कोई नेतृत्व सिर्फ नोबेल शांति पुरस्कार के लिए ही युद्ध विराम को अपने हिसाब से एक टूल न बना ले, बल्कि शांति का भी नेतृत्व करता नजर आए। क्या विश्व को एक ग्रुप ऑफ गुड लीडर्स जैसी संस्था की आवश्यकता आ पड़ी है, जो दुनिया को शांति और सद्भाव का पाठ पढ़ा सके?

नंदितेश निलय
स्पीकर, लेखक एवं एथिक्स प्रशिक्षक

आतंकवाद और घृणा से घिरते एवं फिर हिंसक होते इस समाज को कोई बर्बाद होने से बचाना क्यों नहीं चाहता? क्यों आखिर युद्ध ही सभी मसलों का हल है? और अगर है, तो फिर ये मसले हल क्यों नहीं होते? इन सबके बीच शांति क्या अप्रचलित मूल्य बन चुकी है? ऐसा लगता है, जैसे धर्म और नस्ल में दिनों-दिन बंटती जा रही इस दुनिया को सिर्फ पैसे और व्यापार से ही युद्ध से दूर किया जा सकता है, शांति के उद्बोधन और सामाजिक आचरण से नहीं। क्या शांति अपने आप में किसी नेतृत्व का 'सेंटर ऑफ ग्रेविटी' नहीं हो सकती?

सर्दियों से पहले शरद ऋतु आती है और आते हैं वे अच्छे लोग, जो लोगों के जीवन में खुशियों के रंग भरते हैं। और उन अच्छे लोगों में से कोई बहुत अच्छा व्यक्ति उनका लीडर बनता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि न तो समाज में एकजुटता के पत्ते भूरे होंगे और न ही आम आदमी की मुस्कान। लेकिन मिसाइलों के धमाकों में वह लीडर कहां है? यह दुनिया चंद्रमा के बाद अब मंगल ग्रह और अंतरिक्ष में मनुष्यों की विशाल छलांग की कहानी गढ़ रही है। लेकिन पृथ्वी पर विकास और जिजीविषा की छलांग सिर्फ युद्ध के संदेश लिए ड्रोन और मिसाइलों से क्यों हो रही है? क्या अब भी हमारी धरती को उन भूले-बिसरे नेताओं के

पदचिह्नों की जरूरत है, जिन्हें दुनिया ने पिछले कुछ दशकों में देखा है?

मुझे तो सबसे ज्यादा महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला याद आ रहे हैं। इधर युद्ध, मिसाइल, ड्रोन हर जगह मंडरा रहे हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, आतंकवाद, निरक्षरता, महंगाई, भुखमरी का संकट भी बढ़ता जा रहा है। फिर यह दुनिया बचेगी कैसे? कौन होगा वह लीडर, जो शांति का नायक बनेगा? और क्या शांति के नेतृत्व के लिए भी आर्थिक और सामरिक शक्ति का विशाल जखीरा रखना एक 'जरूरी योग्यता' बन जाएगी? क्या महान सम्राट अशोक की कहानी इतिहास में हिंसा से अहिंसा के हृदय परिवर्तन की आखिरी कहानी बनकर रह जाएगी? आज हर दूसरा व्यक्ति डिजिटल वर्ल्ड में इन्फ्लुएंसर बना घूम रहा है। तो फिर वह इन्फ्लुएंस शांति और सद्भाव के लिए क्यों नहीं होता?

अगर सब कुछ एक लीडर के हाथ में होता है, तो वह अच्छा नेता कैसा होता है? अरस्तू इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि एक अच्छा नेता कोई और नहीं, बल्कि एक अनुयायी होता है और वह अनुसरण करता है लोगों की जरूरतों और इच्छाओं का, सभी के कल्याण का। आधुनिक दुनिया में 'अनुसरण' शब्द सिर्फ मेटा और ब्लू टिक के इर्द-गिर्द ही दिखाई देता है। अंत में, अरस्तू ने निष्कर्ष निकाला कि एक अच्छा अनुयायी ही एक अच्छा नेता बनने के योग्य होता है।

वर्तमान दुनिया में जहां हर कोई अपने लिए जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहा है, क्या हम ऐसे नेता पा सकते हैं, जो आंसुओं, पराजयों, संघर्षों, गरीबी, भय, अशिक्षा, संघर्ष, भूख, और युद्ध के परिणाम को समझते हुए शांति का अनुसरण करना पसंद करें? भारत ने तो अभी हाल के युद्ध में साहस और धैर्य, दोनों का अनुसरण किया। भारतीय सेना और सरकार ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब भी दिया और सिर्फ आतंकी ठिकानों पर प्रहार किया। भारत ने हमेशा शांति का अनुसरण किया और अगर युद्ध के लिए उकसाया भी गया, तो उसने भारतीय दर्शन का मूल्य नहीं खो गया। युद्ध सिर्फ उन्हीं के साथ हुआ, जो सिर्फ युद्ध की भाषा समझते हैं।

प्रारंभिक यूनानी दार्शनिक हमेशा दो सवालों के जवाब देने में रुचि रखते थे: दुनिया क्या है और एक अच्छा व्यक्ति या नेता क्या है? महान सुकरात का मानना कि अच्छाई सत्य का अंतिम रूप है और न्याय या साहस जैसे अन्य सभी मूल्य तब प्रासंगिक हैं, जब वे अच्छाई या भलाई से संबंधित हों। अंत में, वे निष्कर्ष निकालते हैं कि केवल वे ही राज्य का नेतृत्व करने के हकदार हैं, जो आम लोगों की भलाई के लिए कार्य करने की नैतिक शक्ति रखते हैं। यानी एक अच्छा नेता वह होता है, जो मूल्यों के साथ चलता है और युद्ध के बजाय शांति को चुनता है।

आजादी के समय सारे नेता आजादी के जश्न और उस शक्ति को संजोने में डूबे थे, उधर वह अहिंसा और सत्य का नायक नोआखाली की सड़कों पर भूख हड़ताल पर बैठा था। पहली बार मानवता के आदर्श को उन दंगों में उसने बुरी तरह लहूलुहान देखा था। गांधी को कुर्सी की लालसा नहीं थी और न ही चुनाव की चिंता। वह तो सिर्फ बंगाल, पंजाब और दिल्ली की गलियों में शांति और सद्भाव ढूंढ रहे थे। जरूरी है कि विश्व के अच्छे नेता हर उस स्थान पर जाएं, जहां बम और मिसाइलों से आम जनता, मासूम बच्चों, औरतों, युवाओं और वृद्धों की जान गई। वे उनके पास भी जाएं, जिन्हें युद्ध ने गरीबी और भुखमरी के बीच धकेल दिया।

इस विश्व को ऐसे नेतृत्व की जरूरत है, जो बता सके कि देश की रक्षा करना देशभक्ति तो होती ही है, देशवासियों की रक्षा करना भी अच्छे नेतृत्व की जिम्मेदारी होती है। भारत उस युद्ध की शांति को बरसों से ढूंढता रहा। युद्ध अंतिम विकल्प होता है किसी नेतृत्व का और अच्छा नेता देश को युद्ध में धकेलने के पहले कई बार सोचता है। भारत ने हमेशा दया और शांति को ही चुना है। पाकिस्तान, रूस, यूक्रेन, बांग्लादेश, इस्राइल, ईरान और अमेरिका को सोचना होगा कि इस पृथ्वी को बचाना है, तो कैसे? यह ट्रेड डील से नहीं होगा। होगा तो सिर्फ इस यकीन से कि मानवता से बड़ा कुछ नहीं होता। कवि चंडीदास कहते हैं, *'सबार उपरे मानुष सत्य, ताहार उपरे नाई'* यानी सबसे ऊपर सिर्फ मानवता का सत्य होता है, मानवता से बड़ा कुछ नहीं होता।

edit@amarujala.com

जीवन धारा

इमैनुएल कांट

मनुष्य का कर्तव्य है कि वह स्वयं को सुधारे, अपने मन को विकसित करे, और जब वह स्वयं को भटकता हुआ पाए, तो नैतिक नियमों को खुद पर लागू करे। शांति हम सबके हृदय से शुरू होती है।

शांति स्वप्न नहीं, लक्ष्य है

शांति कोई संयोग नहीं है, न ही यह केवल तलवारों का चुप हो जाना है। यह एक ऐसी व्यवस्था है, जो स्वतंत्रता, न्याय और नैतिकता पर आधारित है। मैंने सपना देखा है कि राष्ट्र एक संघ बनाएं, जहां कोई देश दूसरे पर आधिपत्य न जमाए। गणतांत्रिक शासन शांति की नींव है। यदि आप चाहते हैं कि युद्ध का अंत हो, तो प्रत्येक राष्ट्र को गणतांत्रिक होना चाहिए, क्योंकि जनता, जो युद्ध का दुख भोगती है, कभी इसे स्वेच्छा से नहीं चुनेगी। मेरे विचार में, व्यापार और आतिथ्य का अधिकार भी शांति को बढ़ावा देता है, क्योंकि जब लोग एक-दूसरे से जुड़ते हैं, तो वे युद्ध के बजाय सहयोग चुनते हैं। कोई भी गुप्त संधि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह युद्ध को जन्म देती है।

शांति केवल तभी संभव है, जब मनुष्य अपने कर्तव्यों को तर्क और नैतिकता के आधार पर निभाए। मनुष्य का कर्तव्य है कि वह स्वयं को सुधारे, अपने मन को विकसित करे, और जब वह स्वयं को भटकता हुआ पाए, तो नैतिक नियमों को अपने ऊपर लागू करे। शांति हम सबके हृदय से शुरू होती है। युद्ध की जड़ें अज्ञानता और स्वार्थ में हैं। यदि आप शांति चाहते हैं, तो अपने भीतर के अहंकार को हराओ। शांति कोई स्वप्न नहीं, बल्कि एक लक्ष्य है। एक ऐसी दुनिया बनाएं, जहां तर्क और नैतिकता का राज हो, जहां कोई भय न हो, केवल प्रेम और सहयोग हो। यह हमारा कर्तव्य है, क्योंकि शांति के बिना मानवता का कोई भविष्य नहीं। पृथ्वी पर शांति स्थापित करने के लिए, मनुष्यों को 'नए प्राणियों' के रूप में विकसित होना चाहिए।

जीवन में स्थायी शांति प्राप्त करने के लिए मानव चेतना में एक मौलिक बदलाव की आवश्यकता है। इसका तात्पर्य है कि हमारा वर्तमान दृष्टिकोण, जो अक्सर व्यक्तिगत या सीमित समूह हितों पर केंद्रित होता है, को एक अधिक समग्र दृष्टिकोण में विकसित होने की आवश्यकता है, जो सभी चीजों की परस्पर संबद्धता को पहचानता है और सामूहिक कल्याण को प्राथमिकता देता है। बिना विषय-वस्तु के विचार खोखले हैं, बिना अवधारणाओं के अंतर्ज्ञान अंधे हैं, समझ कुछ भी नहीं समझ सकती, इंद्रियां कुछ भी नहीं सोच सकतीं। केवल उनके मिलन से ही ज्ञान उत्पन्न हो सकता है। मनुष्य और उसकी नैतिक प्रगति की क्षमता के बिना, संपूर्ण वास्तविकता एक निर्जन स्थान, एक व्यर्थ चीज होगी, और उसका कोई अंतिम उद्देश्य नहीं होगा। शाश्वत शांति केवल मृत्यु के बाद ही मिलती है, लेकिन जब तक हम जीवित हैं, हमेशा आगे बढ़ते हैं। मनुष्य अपनी अज्ञानता और दूसरों पर निर्भरता से मुक्त होकर, अपनी समझ और तर्क का उपयोग करके, स्वतंत्र रूप से सोचने और कार्य करने की क्षमता प्राप्त करता है और यहीं से जीवन में शांति के बीज अंकुरित होते हैं। शांति जीवन का गीत है। मन की चुप्पी, प्रेम की भाषा और न्याय का मार्ग है।

खुद को सुधारते रहें

सूत्र

हमारे जीवन का एक ही कर्तव्य है कि जब तक हमारी सांस चल रही है, तब तक स्वयं को सुधारें, अपने भीतर के अहंकार को नष्ट करें। अपना 'ध्यान' स्वयं की शांति पर केंद्रित करें, जिससे आपके आसपास सब कुछ शांत और सुंदर हो जाएगा। जब भी स्वयं को भटकता हुआ पाएं, तो नैतिक नियमों को अपने ऊपर लागू करें।

दूसरा पहलू

बाबा विश्वनाथ की नगरी में वैज्ञानिक शोध से पता चलता है कि किस जीव के पूर्वजों की उत्पत्ति कहां से हुई थी।

डीएनए की लैब और पहचान का पावर हाउस

काशी में एक डीएनए की प्रयोगशाला है। दिन भर एक्स व वाय क्रोमोसोम्स में उलझते-सुलझते इस लैब में मौजूद वैज्ञानिक दुनिया वालों को उनके कई सौ साल पहले के पूर्वज खोज कर बताते हैं। काशी में बैठे लोगों का कौन-सा डीएनए उन्हें कश्मीरी पंडितों से जोड़ता है, और कैसे लद्दाख वाले जीन्स चीनी नहीं, भारतीय ज्यादा हैं, ऐसे तमाम सवालों के जवाब यहीं कुरेदे जाते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की ज्ञान लैब मेडिकल, क्रिमिनल और विवादों से जुड़े मसलों को डीएनए से पूर्वज पहचानकर सुलझाने में अदालतों और सरकारों की मदद करती है।

उपमिता वाजपेयी

बीएचयू की ज्ञान लैब मेडिकल, क्रिमिनल मसलों को सुलझाने में अदालतों और सरकारों की मदद करती है।

अंग्रेजों ने जो पढ़ाया और मुगलों ने जो दावा किया उसकी असलियत पता करने के लिए वैज्ञानिकों ने बकायदा दर्जन भर शोध किए हैं। आर्य भारतीय नहीं हैं, इस थ्योरी को पलट दिया। वैसे इन्हें हासिल तमगों में आरुषी हत्याकांड जैसे देश में चर्चित क्राइम, रामायण के समय की जनजातियों को श्रीलंका तक खोज लेना और कोविड में इम्युनिटी की कहानी बता देना सबसे ऊपर है। इस लैब में ही पता चला कि हमारे आपके पूर्वजों पर निर्भर करता है कि आपको कोविड होगा या नहीं, और होगा तो उसका कितना असर होगा। हार्ट अटैक किसे आएगा और 4.5 प्रतिशत भारतीयों में कार्डियक अरेस्ट का सात गुना ज्यादा खतरा है, ज्ञान लैब इसे भी पता लगा चुकी है। देश में इस तरह की पांच लैब हैं। अन्य लैब में औसतन दो से तीन, तो ज्ञान लैब में 12 से 15 शोधपत्र प्रकाशित होते हैं। ज्ञान लैब को सबसे ज्यादा ख्याति चार्ली चैप्लिन के भारतीय संबंध का पता लगाने पर मिली।

अंग्रेजों ने जो पढ़ाया व मुगलों ने जो दावा किया, उसकी असलियत पता करने के लिए वैज्ञानिकों ने बाकायदा कई शोध किए हैं। आर्य भारतीय नहीं हैं, इस थ्योरी को इसी प्रयोगशाला में शोध के जरिये पलट दिया गया।

सबसे विवादित शोध था रोहिंग्या और संथाल समुदाय का। बात चार साल पहले की है, संथाल समुदाय के शोध के बाद नक्सली वैज्ञानिकों को खोजते हुए ज्ञान लैब तक पहुंच गए थे। इन्सानों के अलावा सुअर, मछली, हिमालय के सुपर ह्यूमन यति और अमेरिकी भेड़िये के डीएनए पर भी यहां काम हो चुका है। यहीं पता चला कि घोड़ा भारत में 16 हजार वर्षों से है, तो भारत में एक भी डीएनए चंगेज खान के डीएनए का अंश नहीं है।

लैब में खास कुंडली भी तैयार होती है, जो शादी से पहले वर-वधू के स्वास्थ्य मामले बता सकती है। वैज्ञानिकों ने महाकुंभ के दौरान नागा साधुओं और कल्पवासियों के भी सैंपल जुटाए हैं। एक सैंपल लेने में चार से पांच हजार रुपये तक खर्च आता है। लैब के जीन्स-डीएनए वाले खजाने में 50 हजार साल पुराने सैंपल भी मौजूद हैं। लैब के प्रमुख हैं डॉ. ज्ञानेश्वर चौबे। पीएचडी कर रहे आठ शोधार्थी, दो पोस्ट डॉक्टरेट विद्यार्थी और चार लैब स्टाफ, पुरखों को पहचानने वाले इस पावर हाउस का हिस्सा हैं।

आंकड़े

तेल का आयात

भारत ने वित्त वर्ष 2025 में विभिन्न देशों से कच्चे तेल का आयात किया, जिनमें रूस से सबसे ज्यादा तेल मंगवाया गया।

देश	प्रतिशत
रूस	35%
इराक	19%
सऊदी अरब	14%
यूएई	10%
अमेरिका	5%

आंकड़े कच्चे तेल के आयात के, प्रतिशत में | स्रोत : MoC&I

आज से गुप्त नवरात्र शुरू हो रहे हैं। शृंगी ऋषि कहते हैं कि जो भी भक्त इन नवरात्रों के दौरान माता की पूजा-अर्चना करते हैं, उन पर मां की विशेष कृपा होती है।

गुप्त नवरात्र और मां की कृपा

एक बार शृंगी ऋषि प्रवचन दे रहे थे। श्रद्धालुओं में बैठी एक महिला ने ऋषि से प्रार्थना की कि उसका पति दुर्व्यसनों से घिरा रहता है। इस वजह से वह घर में पूजा-पाठ व दान-पुण्य नहीं कर पाती। महिला ने ऋषि से आग्रह किया कि आप ऐसा कोई उपाय बताएं, जिससे मैं मां दुर्गा की पूजा कर सकूं और मेरा पति सन्मार्ग पर चल पड़े। महिला का भक्ति-भाव देख शृंगी ऋषि प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, 'वासंतिक और शारदीय नवरात्र से तो जनमानस परिचित है, लेकिन इनके अतिरिक्त वर्ष में दो नवरात्रि और आती हैं, जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है।'

उन्होंने कहा कि प्रकट नवरात्रों में नौ देवियों की उपासना होती है, पर गुप्त नवरात्रों में दस महाविद्याओं की साधना की जाती है। इन नवरात्रों में प्रमुख देवी का नाम सर्वैश्वर्यकारिणी है। उन्होंने कहा, 'इन नवरात्रों के दौरान यदि कोई भक्त मां दुर्गा की साधना करता है, तो मां उसके जीवन को सफल बना देती हैं। लोभी, कामी, व्यसनी, पूजा-पाठ न कर सकने वाला भी यदि इस दौरान माता की साधना करता है, तो उस पर मां दुर्गा की विशेष कृपा होती है।'

अंतर्यात्रा
संकलित

शृंगी ऋषि के उपदेश के बाद महिला ने गुप्त नवरात्रों के दौरान माता की पूरे भक्ति-भाव से पूजा की, जिससे न केवल उसका पति सन्मार्ग पर चलने लगा, बल्कि उसका जीवन खुशहाली से भर गया। उल्लेखनीय है कि इस बार गुप्त नवरात्र आषाढ़ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा (26 जून से 4 जुलाई तक) से शुरू हो रहे हैं।

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 26 जून, 1975

श्रीमती गांधी की अपील स्वयं न सुनें प्रधान न्यायाधीश

श्रीमती गांधी की अपील स्वयं न सुनें

जय प्रकाश नारायण ने सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश से प्रधानमंत्री के चुनाव की अपील को सुनने वाली बेंच में आसन ग्रहण न करने का अनुरोध किया है। श्रीमती गांधी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उन्हें त्यागपत्र देना चाहिए।

भोजन की बर्बादी की चिंता कोई आज की नहीं

भोजन की बर्बादी की चिंता आदिकाल से चली आ रही है। महाभारत से लेकर बाइबिल और कुरान तक में इसका जिक्र है।

डॉ. विवेक एस अग्रवाल | आहार

संयुक्त राष्ट्र के आह्वान पर हर वर्ष खाद्य सुरक्षा दिवस के आयोजन समूचे विश्व में होते हैं और संकल्प किया जाता है कि भोजन की बर्बादी को रोकने के लिए न सिर्फ ठोस कदम उठाए जाएंगे, अपितु आमजन को प्रेरित कर शून्य अपशिष्ट की अवधारणा को हासिल किया जाएगा। सर्वप्रथम विचारणीय बिंदु यह है कि यदि किसी को भोजन कराना या अन्नदान परमार्थ की भावना है, तो किसी के मुख से निवाला छीनना क्या है? निश्चित रूप से वह अधर्म ही होगा, जब प्लेट में भोजन छोड़ा जाए। मानस में यह विचार उत्कीर्णित होना चाहिए कि थाली में छोड़ी गई खाद्य सामग्री सिर्फ जूठन न होकर कितनों के निवाले हैं, जो किसी का पेट भर सकते थे। यदि यह विचार हर इन्सान में दृढ़ता से समा जाए, तो फिर इस धरती पर कोई भी भूखा नहीं रहेगा।

दुर्भाग्यवश हम स्वयं से अतिरिक्त विचार ही नहीं रखते और मानते हैं कि मात्र हमारे संवेदनशील या उत्तरदायी होने से क्या प्रभाव पड़ेगा। यथार्थ यह है कि

हर कण महत्वपूर्ण होता है और कण-कण जुटकर किसी की थाली का बंदोबस्त होता है।

ऐसा नहीं है कि भोजन की बर्बादी को लेकर चिंता आज ही की जा रही है, अपितु यह विषय आदिकाल से विचारणीय रहा है। यदि हम कुरुक्षेत्र में लड़े गए महाभारत युद्ध का पुनरावलोकन करें, तो भोजन से जुड़ा एक रोचक प्रसंग मिलता है। युद्ध के दौरान भी खाद्य बर्बादी रोकने की बड़ी मिसाल कायम की गई थी। जैसा महाभारत में उद्धृत है कि जब उडुपी के राजा ने दोनों पक्षों की तरफ न रहकर अपने को तटस्थ रखने का निर्णय लिया, तो उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण से अपनी भूमिका के बारे में आदेश देने के लिए कहा। निर्णय हुआ कि युद्ध के दौरान भोजन की तमाम व्यवस्था उडुपी राजा द्वारा ही की जाएगी। उस वक्त अहम प्रश्न यह था कि कितने लोगों के लिए भोजन तैयार किया जाए, क्योंकि युद्ध में तो हर दिन कई लोग मृत्यु का ग्रास बन जाते थे। साथ ही, 'अन्न ही ब्रह्म है' अवधारणा के साथ एक कण भी बर्बाद नहीं होना चाहिए था।

इस संख्या की गणना और निर्धारण करने के लिए भगवान कृष्ण ने उपाय स्वरूप युद्ध के पूरे 18 दिनों तक मूंगफली खाने का निर्णय किया, यह उडुपी राजा के लिए गणना का माध्यम बना। उडुपी राजा द्वारा प्रतिदिन रात्रि में मूंगफली के छिलकों की गणना कर एक हजार से गुणा कर आगामी दिन संभावित मृत सैनिकों की संख्या का आकलन किया जाता था और उसी अनुरूप भोजन एवं पानी की व्यवस्था की जाती थी। परिणामस्वरूप, इस संपूर्ण युद्ध में जहां सभी सैनिकों के लिए, चाहे वे कौरव हों या पांडव, पर्याप्त मात्रा में भोजन एवं जल उपलब्ध रहा और भोजन का एक भी कण बर्बाद नहीं हुआ। यह इस तथ्य का द्योतक है कि हजारों वर्ष पूर्व महाभारत के युद्ध में भी भोजन को बचाने को कितनी महत्ता प्रदान की गई थी। संभवतया कुरुक्षेत्र में किए गए व्यवस्थित और उपयुक्त प्रबंधन के रहते ही उडुपी और व्यंजन पर्याय बन गए। लेकिन दुर्भाग्यवश, वर्तमान में सामान्य परिस्थितियों में भी स्थिर गणना होने के बावजूद भोजन की बर्बादी सामान्य प्रक्रिया हो गई है।

धर्म कोई भी हो, भोजन के अपव्यय के प्रति सभी एकमत हैं और बर्बादी की वर्जना को धार्मिक अवहेलना से संबद्ध करते हुए बचाव एवं संयमित उपयोग की सलाह दी गई है। सनातन धर्म जहां अन्न ही ब्रह्म के जरिये सीधे-सीधे अन्न को ईश्वर स्वरूप करार देता है, तो जैन मत अपरिग्रह के सिद्धांत से आवश्यकतानुसार उपभोग का उल्लेख करता है। सिख मत में भोजन आध्यात्मिक जीवन का हिस्सा है। जैसा कि गुरु अमरदास लिखते हैं, 'निर्माता ने सृष्टि बनाई; निर्माता इसे देखता है, और इसे सांस और पोषण के साथ आशीर्वाद देता है। अतः इसे बर्बाद करना अर्थात सृष्टि के निर्माता का अपमान करना है (एसजीजीएस, 1055)।'

इसी प्रकार इस्लाम में कुरान की आयतों और पैगंबर की शिक्षाओं में भी भोजन एवं खाद्यान्न बर्बादी के बारे में उल्लेख मिलता है। कुरान में 6:141 एवं 5:87 पर उपभोग की अति के दुष्परिणाम से आगाह करते हुए मौसम के अनुसार सेवन एवं उपज के प्रति कृतज्ञता का भाव रखने की सीख दी गई है। बाइबिल भी मानव को उत्तरदायी व्यवहार की शिक्षा देते हुए समस्त प्राकृतिक संसाधनों की देखभाल और संरक्षण का संदेश देती है। ईसाई धर्म के कुछ संप्रदायों में भोजन की बर्बादी को दूसरों के अधिकार छीनने के समकक्ष मानते हुए इस सम्मत जीवनशैली अपनाने पर जोर दिया है। सैद्धांतिक रूप से कोई भी भोजन की बर्बादी की न तो वकालत करता है, न ही कोई तर्क प्रस्तुत करता है, लेकिन व्यावहारिक रूप से आचरण पूर्णतया भिन्न होता है। खाद्य सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि 'मनसा वाचा कर्मणा यः समक्रीयते' की अनुपालना करते हुए हर प्रकार से अन्न को देवतुल्य मानते हुए इसके संरक्षण में प्रत्यक्ष भागीदार बनें।

शुभांशु का सफर

यह सुखद और स्वागतयोग्य कामयाबी है कि भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं। आज से करीब 41 साल पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा को यह कामयाबी हासिल हुई थी। राकेश शर्मा को जैसे हमेशा याद किया जाता है, वैसे ही शुभांशु शुक्ला भी अब हमारे इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गए हैं। यह एक ऐसा अभियान है, जिसकी प्रतीक्षा लोग महीनों से कर रहे थे। इस अभियान को इसलिए भी याद किया जाएगा कि इसके प्रक्षेपण की तिथि एकाधिक बार टली है। पहले यह मिशन 29 मई को रवाना होना था, बाद में 8 जून, फिर 10 जून, 11 जून, 19 जून और फिर 22 जून का समय तय किया गया। अब अंततः भारतीय समय के अनुसार, 25 जून को अभियान रवाना हुआ है। भारत की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने बुधवार को प्रसन्नता का इजहार करते हुए कहा है कि पूरा देश भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की सितारों की यात्रा से उत्साहित और गौरवान्वित है। भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में उत्सव का माहौल है और तमाम वैज्ञानिकों को शुभांशु के बहुमूल्य अनुभवों की प्रतीक्षा है।

प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा के समय अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना नहीं हुई थी, पर शुभांशु को अंतरिक्ष केंद्र पर रहने का मौका मिलेगा। ध्यान रखने की बात है कि यह अभियान दुनिया के आला वैज्ञानिक देशों के साथ भारत के समन्वय का भी प्रमाण है।

भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा को जैसे हमेशा याद किया जाता है, वैसे ही शुभांशु शुक्ला भी अब हमारे इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गए हैं।

राकेश शर्मा सोवियत संघ के सहयोग से अंतरिक्ष यात्रा पर गए थे और शुभांशु शुक्ला मुख्य रूप से अमेरिका के सहयोग से गए हैं। यह सीखने वाली बात है, ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में जहां से भी लाभ मिले, वहां से हमें समन्वय साधकर चलना चाहिए। बेहतर सहयोग का ही प्रमाण है कि भारत एक्सिओम-4 मिशन का हिस्सा है। वैज्ञानिक तालमेल की यह रणनीति भारत के मुफीद है। बहरहाल, इस अभियान में भारतीय अंतरिक्ष यात्री के अलावा, अमेरिका, पोलैंड और हंगरी के यात्री भी शामिल हैं। विज्ञान के मोर्चे पर यह एकजुटता बहुत जरूरी है। नासा और इसरो के बीच स्थायी साझेदारी बढ़नी चाहिए। अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित केनेडी स्पेस सेंटर से भारतीय मानक समय के अनुसार, दोपहर बारह बजकर एक मिनट पर यह अभियान रवाना हुआ और इसकी रवानगी को पूरी दुनिया में जगह-जगह देखा गया। इस बार यह भी खास है कि इस अभियान के प्रक्षेपण को देखने के लिए जगह-जगह इंतजाम किए गए थे। लखनऊ के सिटी मोंटेसरी स्कूल में आयोजित वॉच पार्टी में शुभांशु के माता-पिता इस ऐतिहासिक प्रक्षेपण को देखते हुए जिस तरह भावुक हुए, उससे बहुत से परिवारों, बच्चों और युवाओं को प्रेरणा मिलेगी। ये विजय के कुछ ऐसे पल होते हैं, जिनसे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कुछ खास करने की इच्छा मन में जगती है, जिससे तरक्की को बल मिलता है।

कोई संदेह नहीं कि अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत को अभी बहुत कुछ करना है। भारतीयों में यह क्षमता होनी चाहिए कि वे अकेले दम पर अंतरिक्ष में पहुंच सकें। चीन अंतरिक्ष के मामले में हमसे काफी आगे निकल चुका है। उसका अंतरिक्ष में अपना केंद्र भी है, वह पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। भारत को भी अपने प्रयोगों में तेजी लानी चाहिए। अंतरिक्ष की कक्षा में मानव सहित यान भेजने की क्षमता का विकास जल्दी होना चाहिए। चंद्रयान के अगले चरण पर भी हमारा पूरा ध्यान रहना जरूरी है। इसरो और देश को ज्यादा प्रतिभावान इंजीनियरों की जरूरत है। ऐसे में, इसरो की सेवा का आकर्षण बढ़ाना चाहिए।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 26 जून 1950

लोकतंत्र या हुल्लड़बाजी

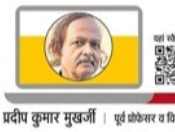

हम अपने देश में लोकतंत्री परम्पराओं का विकास करना चाहते हैं। हमने अपने राष्ट्र का लोकतंत्री विधान स्वीकार किया है। आज एक दल के हाथ में शासन की बागडोर है, इसलिए कि उसको जनता के बहुमत का समर्थन प्राप्त है। कल अगर जनता का बहुमत उसके विरुद्ध हो जाता है, वह सत्ता के स्थान से च्युत हो जायेगा और उसका स्थान दूसरा दल ले लेगा, जिसे उस बहुमत का विश्वास प्राप्त होगा। लोकतंत्र जनता के हाथ में यह अधिकार देता है, जिसका प्रयोग करके वह शासक, सत्ता को बदल सकती है। यह परिवर्तन शांतिपूर्वक होता है और उसमें बल-प्रयोग के लिए कोई स्थान नहीं होता। लोकतंत्र जनमत को बदलने का अवकाश देता है। लोगों को उसमें अपने विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता होती है। अवश्य ही इस स्वतंत्रता की एक मर्यादा होती है। ऐसे विचार तो प्रकट नहीं होने दिये जा सकते, जो हिंसा या बल-प्रयोग की प्रेरणा देते हों और न सार्वजनिक सदाचार की ही अवहेलना की जा सकती है। किन्तु इस मर्यादा के बावजूद लोगों को अपना मत प्रकट करने की लोकतंत्र में काफी स्वतंत्रता होती है। लोकतंत्र की सफलता के लिए यह जरूरी है कि लोगों में दूसरों के विचारों के प्रति सहिष्णुता हो। विरोधी विचारों को भी वे शांतिपूर्वक सुन सकें और उन पर शांत-चित्त से विचार करने की मनोवृत्ति रखें। विरोधी विचारों को मानना या न मानना लोगों की इच्छा पर निर्भर करता है। लोकतंत्र केवल इसी प्रकार सफलतापूर्वक चल सकता है।

हमें दुःख होता है, जब हम अपने देश के कुछ नौजवानों को लोकतंत्र के आधारभूत सिद्धांतों की खुले तौर पर अवहेलना करते देखते हैं। सहिष्णुता भारतीय सभ्यता की प्रधान विशेषता रही है। विरोधी विचारों को उदारतापूर्वक बर्दाश्त किया जाता रहा है। किन्तु क्षणिक आवेश में कुछ लोग भारतीय सभ्यता के इस सनातन पाठ को भूल जाते हैं। कलकत्ता में हाल में जो घटना हुई, वह शोचनीय है। कांग्रेस के महामंत्री श्री शंकर राय देव वहां एक सभा में भाषण दे रहे थे। वह उपस्थित जनता को समझा रहे थे कि कांग्रेस ने देश का विभाजन किन परिस्थितियों में स्वीकार किया। उनको आगे नहीं बोलने दिया गया। किसी ने मंच पर पत्थर फेंका।...क्या ये बंगाली नवयुवक जो सभा में हुल्लड़ मचा रहे थे, बंगाल की संस्कृति का प्रदर्शन कर रहे थे? निश्चय ही नहीं!

अंतरिक्ष में भारतीय हौसले की उड़ान

प्रदीप कुमार मुखर्जी | पूर्व प्रोफेसर व विज्ञान लेखक

उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद शुभांशु शुक्ला ने कहा, हम 41 साल बाद अंतरिक्ष में पहुंचे हैं। यह मेरी यात्रा की नहीं, बल्कि भारत के मानव अंतरिक्ष अभियान की शुरुआत है।

भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा के बाद अब शुभांशु शुक्ला हमेशा के लिए भारतीयों की स्मृति का हिस्सा बन गए हैं। ग्रुप कप्तान शुभांशु ने बुधवार को भारतीय समयानुसार दोपहर करीब 12 बजे फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस स्टेशन से अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र (आईएसएस) के लिए उड़ान भरी। याद कीजिए, 3 अप्रैल, 1984 का दिन, जब राकेश शर्मा सोयुज टी-11 यान की उड़ान से अंतरिक्ष में पहुंचे थे, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के इस सवाल का कि 'अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है?' उन्होंने जवाब दिया था- *सारे जहां से अच्छा।*

राकेश शर्मा और शुभांशु शुक्ला के अलावा एक अन्य भारतीय भी अंतरिक्ष में जा चुके हैं, जो हैं कप्तान गोपीचंद थोटाकुरा। वह पिछले साल एक पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष में गए थे। शुभांशु का यह मिशन कई मायनों में महत्वपूर्ण है। उन्होंने क्रू ड्रैगन 213 अंतरिक्षयान से उड़ान भरी। उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही अंतरिक्ष से अपने संदेश में उन्होंने कहा, हम 41 साल बाद वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं। यह एक अद्भुत सफर है।... यह महज मेरी अंतरिक्ष यात्रा की शुरुआत नहीं है, बल्कि यह भारत के मानव अंतरिक्ष अभियान की शुरुआत है।

वाकई, भारत द्वारा अपने दम पर यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने के लिहाज से इस अभियान को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने और 2040 तक चंद्रमा पर इंसानों को भेजने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। कहा जा रहा है कि भारत के मानव अभियान को शुभांशु की इस यात्रा से एक नई दिशा मिल सकेगी।

देखा जाए, तो भारत अंतरिक्ष विज्ञान में अपनी महती उपलब्धियों से विश्वभर में झंडे गाड़ चुका है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, यानी इसरो इस दिशा में लगातार सक्रिय है। वह तो देश-विदेश के उपग्रहों को प्रक्षेपित कर काफी समय से कमाई भी कर रहा है। चंद्रयान, मंगलयान और आदित्य मिशन के बाद इसरो अपने गगनयान मिशन को अंजाम देना चाहता है। यह मिशन तीन चरणों में होगा और आशा की जा रही है कि 2027 तक वह मानवयुक्त अंतरिक्ष यान भेजने में सफल हो सकेगा। इससे भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के फलक का स्वाभाविक विस्तार होगा।

इसरो की भविष्य के लिए कई अन्य योजनाएं भी हैं। इनमें शुक्र आदि ग्रहों से जुड़े अंतरिक्ष मिशन शामिल हैं। चंद्रयान-4 को भी इसरो द्वारा भविष्य में भेजने की योजना है। भारत खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की दिशा में कार्य कर ही रहा है, जिसके 2035 तक पूरी तरह से चालू होने की उम्मीद है। 52 टन वजनी इस अंतरिक्ष स्टेशन को पांच मॉड्यूलों में बनाया जाएगा, जिनमें से पहला मॉड्यूल 2028 में लॉन्च किया जाएगा। यह अंतरिक्ष स्टेशन लंबी अवधि के सूक्ष्म-गुरुत्व अनुसंधान, अंतरिक्षयात्री प्रशिक्षण और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा।

बहरहाल, एक्सिओम-4 मिशन काफी अहम इसलिए भी है, क्योंकि पहले इस अभियान को कभी मौसम की वजह से, तो कभी तकनीकी खराबी के कारण छह बार टाला जा चुका है। ऐसे में, पूरे देश की नजर इस पर बनी हुई है और अगर सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ, तो शुभांशु आज, यानी 26 जून को शाम साढ़े चार बजे आईएसएस से डॉकिंग करेंगे। वह इस मिशन के पायलट हैं। उनके साथ तीन अन्य अंतरिक्ष यात्री भी आईएसएस पहुंचे हैं। इनमें एक हैं, मिशन का नेतृत्व करने वाली नासा की पूर्व अंतरिक्षयात्री पैगी व्हिट्सन, जबकि दो अन्य हैं- पोलैंड के स्लावोज उज्नास्की-विस्नीव्स्की और हंगरी के टिबोर कापू। ये दोनों मिशन विशेषज्ञ हैं।

10 अक्तूबर, 1985 को लखनऊ के त्रिवेणीनगर में जन्मे शुभांशु शुक्ला बचपन से ही कुछ गंभीर प्रकृति के रहे हैं। उनमें कुछ अलग करने और बड़ा बनने की चाह हमेशा रही है। एक खास बात शुभांशु के अंदर यह भी है कि लक्ष्य पूरा होने तक वह कभी चैन से नहीं बैठते। यही कारण है कि 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी जाना बेहतर समझा। सन् 2006 में फ्लाइट पायलट के तौर पर शुभांशु भारतीय वायुसेना में शामिल हुए। मिग, सुखोई, डोर्नियर, जगुआर और हॉक्स जैसे लड़ाकू विमानों के साथ 2,000 से अधिक घंटे की उड़ान का अनुभव उन्होंने हासिल किया है।

एक्सिओम-4 मिशन के अलावा इसरो के गगनयान मिशन के लिए भी सन् 2019 में शुभांशु का चयन हो चुका है। गगनयान इसरो का मानव मिशन है, लेकिन अंतरिक्षयात्रियों को भेजने से पहले दो अन्य मिशनों को अंजाम देने की इसरो की योजना है। इनमें से पहले मिशन में खाली यान, जबकि दूसरे में रोबोटिक व्योममित्र को भेजे जाने की योजना बनाई गई है। जैसा कि शुभांशु ने अंतरिक्ष से दिए गए अपने संदेश में कहा है कि वर्तमान मिशन भारत के मानव मिशन कार्यक्रम की शुरुआत है। लिहाजा, गगनयान मिशन के लिए शुभांशु का आईएसएस में हासिल किया गया अनुभव निश्चित रूप से बड़ा काम आएगा।

एक्सिओम-4 मिशन इसरो, नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी (ईएसए) और एक्सिओम स्पेस का संयुक्त मिशन है। शुभांशु सहित चारों अंतरिक्षयात्री आईएसएस में 60 वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे, जिनमें से सात प्रयोग भारत से होंगे। एक प्रमुख प्रयोग में छह प्रकार के फसल बीजों पर अंतरिक्ष के प्रभाव की जांच की जाएगी। यह प्रयोग इस बात को समझने में मदद करेगा कि भविष्य के मिशनों के लिए अंतरिक्ष में फसलें कैसे उगाई जा सकती हैं? आईएसएस में ग्लूकोज और इंसुलिन पर भी विशेष अध्ययन किया जाएगा, जो भविष्य में मधुमेह के इलाज की दिशा को पूरी तरह से बदल सकता है। यह चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान होगा। सूक्ष्म शैवाल (माइक्रोएल्गी) की तीन प्रजातियों की वृद्धि, उपापचय व आनुवंशिकी का अध्ययन भी किया जाएगा, ताकि यह समझा जा सके कि माइक्रोएल्गी अंतरिक्ष में कैसे वृद्धि करते हैं? इसके अलावा छह फसल बीज-किस्मों का अध्ययन भी किया जाएगा। एक और पहलू पर भी आईएसएस में प्रयोग किया जाएगा, जो है अंतरिक्ष में कंप्यूटर स्क्रीन का उपयोग करने के शारीरिक और संज्ञानात्मक (कॉग्निटिव) प्रभावों के बारे में पता लगाना।

कोई दोराय नहीं कि शुभांशु का आईएसएस में 14 दिनों का यह अनुभव, खासकर इसरो के भावी गगनयान मिशन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण साबित होगा। यह मिशन वास्तव में भारत के मानव अभियान कार्यक्रम की शुरुआत है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

ईरान का संकट और भारत के लिए पैदा नए अवसर

एम एल मीना | प्रोफेसर, भू-राजनीति

इजरायल-ईरान के बीच सीजफायर होने से पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली है। दरअसल, ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद करने के मसौदे को अपनी संसद से पारित करवाने के बाद कतर व इराक स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डों पर जो जवाबी हमले किए, उससे यह अंदेशा गहरा गया था कि अब यह समुद्री मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। भारत के लिए यह संकट की स्थिति थी, क्योंकि अपनी ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा वह होर्मुज और मध्य-पश्चिम एशिया के समुद्री मार्ग से पूरा करता है। फिलहाल वह संकट टल गया है, पर पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में, सवाल यह नहीं है कि ऐसी किसी भी स्थिति में भारत तटस्थ रहे या नहीं, बल्कि यह है कि क्या भारत अपनी तटस्थता को सक्रिय और नेतृत्वकारी भूमिका में बदल सकता है?

भारत ने दशकों से गुटनिरपेक्षता और रणनीतिक स्वायत्तता की नीति अपना रखी है। यह नीति उसे ईरान जैसे देशों से मजबूत संबंध बनाए रखने की सुविधा देती है। चाहे चाबहार बंदरगाह का उपयोग हो, अंतरराष्ट्रीय नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर (आईएनएसटीसी) हो या मध्य एशिया तक पहुंच, इस रणनीति की बदौलत भारत अपने हित साधता रहा है। दूसरी ओर, उसने अमेरिका और इजरायल के साथ रक्षा, तकनीक, और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाया है। लेकिन हालिया घटनाओं ने स्पष्ट कर दिया है कि अमेरिका जैसा सहयोगी, जो संयुक्त राष्ट्र की मंजूरी के बिना ईरान पर हमला करता है, पूरी तरह भरोसेमंद नहीं है।

ईरान, अमेरिका और खाड़ी के देशों से भारत के अच्छे संबंध हैं। उसके लिए यह गुटनिरपेक्षता का नहीं, 'रणनीतिक नेतृत्व' की भूमिका निभाने का वक्त है।

ईरान के पास होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद करने की वास्तविक क्षमता है। चाहे बारूद बिछाना हो, मिसाइलों की तैनाती हो या छोटी युद्धक नौकाओं का इस्तेमाल करना हो, वह ऐसा कर सकता है। अगर उसने भविष्य में ऐसा किया, तो इससे न केवल भारत सहित पूरे दक्षिण एशिया, दक्षिण-पूर्वी एशिया, यूरोप या यूं कहें कि लगभग पूरे विश्व की ऊर्जा-आपूर्ति बाधित होगी, बल्कि वैश्विक व्यापार भी चरमरा सकता है। इस संकट ने भविष्य की चुनौतियों से हमें अवगत कराया है। तो केवल आपूर्ति का विविधीकरण या रणनीतिक भंडारण जैसे कदम ही काफी नहीं होंगे, बल्कि भारत को कुशल राजनयिक वास्तुकला और निर्णयों की आवश्यकता है।

भारतीय नौसेना द्वारा 'ऑपरेशन संकल्प' के जरिये होर्मुज के आसपास अपने वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। यह कार्रवाई रक्षा से अधिक रणनीतिक उपस्थिति के संकेत देती है। इस समय भारत के पास कुछ ऐसे अवसर उपलब्ध हैं, जिनके माध्यम से वह इस क्षेत्र में प्रमुख भूमिका में आ सकता है। जैसे, भारत को इस समय एक नया प्रस्ताव 'चाबहार स्थिरता पहल' लाना चाहिए। इसके तहत वह ईरान, ओमान और यूएई को एक साथ लाकर एक ऐसा राजनयिक तंत्र बना सकता है, जो ईरान को भरोसा दिलाए कि उसका कभी आर्थिक बहिष्कार नहीं होगा, अगर वह समुद्री मार्गों के आवागमन की सुरक्षा व स्वतंत्रता सुनिश्चित करे। भारत के तीनों ही पक्षों- ईरान, अमेरिका और खाड़ी के देशों से संतुलित संबंध हैं। यह उसके लिए गुटनिरपेक्षता का नहीं, 'रणनीतिक नेतृत्व' की भूमिका निभाने का समय है। भारत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि चाबहार पोर्ट से शुरू होकर पश्चिम एशिया व यूरोप तक जाने वाला 'इंडियन-मिडिल ईस्ट-यूरोपियन कॉरिडोर' (आईएमईसी) अब सपना नहीं, बल्कि प्राथमिकता बने।

भारत को समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में 'इंडो-गल्फ मैरीटाइम अवेयरनेस नेटवर्क' (आईजी-मैन) जैसी पहल करनी चाहिए। इसके जरिये वह अपने 'इंडियन ओशन डोमेन अवेयरनेस सेंटर' को खाड़ी के देशों से जोड़ सकता है। इससे ड्रोन निगरानी, डाटा साझा करना और समुद्री गतिविधियों का सामूहिक विश्लेषण संभव होगा, जो समुद्री मार्गों को सुरक्षित व भरोसेमंद बनाएगा। इस प्रकार की गतिविधियां भारत की वैश्विक छवि को संतुलित बनाती हैं।

भारत को अब 'स्थिरता का शिल्पकार' देश बनना चाहिए। अगर भारत एक ऐसे ढांचे की वकालत करे, जो समुद्री सुरक्षा, ऊर्जा आपूर्ति और क्षेत्रीय सहयोग को जोड़ता हो, तो वह वैश्विक अस्थिरता को अवसर में बदल सकता है।

(साथ में रवि दास)

मनसा वाचा कर्मणा

मुक्ति का दूसरा मार्ग नहीं

एकरूपता प्रकृति का एक बड़ा नियम है। एक बार जो घटित हुआ है, वह पुनः घटित हो सकता है। इसीलिए योग विद्या के आचार्यगण कहते हैं कि धर्म पूर्वकालीन अनुभवों पर केवल स्थापित ही नहीं है, वरन् इन अनुभवों से संपन्न हुए बिना कोई भी धार्मिक नहीं हो सकता। जिस विद्या द्वारा ये अनुभव प्राप्त होते हैं, उसका नाम है योग। धर्म के सत्यों का जब तक कोई अनुभव नहीं कर लेता, तब तक धर्म की बात करना वृथा है।

भगवान के नाम पर इतनी लड़ाई, विरोध और झगड़ा क्यों? भगवान के नाम पर जितना खून बहा है, उतना और किसी कारण से नहीं। ऐसा क्यों? इसीलिए कि कोई भी व्यक्ति मूल तक नहीं गया। सब लोग पूर्वजों के कुछ आचारों का अनुमोदन करके ही संतुष्ट थे। वे चाहते थे कि दूसरे भी वैसा ही करें। जिन्हें आत्मा की अनुभूति या ईश्वरीय साक्षात्कार न हुआ हो, उन्हें यह कहने का क्या अधिकार है कि आत्मा या ईश्वर है? यदि ईश्वर है, तो उसका साक्षात्कार करना होगा; यदि आत्मा नामक कोई चीज है, तो उसकी उपलब्धि करनी होगी। अन्यथा विश्वास न करना ही भला। ढोंगी होने से स्पष्टवादी नास्तिक होना अच्छा है।

आजकल के विद्वान कहलाने वाले मनुष्यों के मन का भाव यह है कि धर्म, दर्शन और परम पुरुष का अनुसंधान, यह सब निष्फल है; और दूसरी ओर, जो अर्द्धशिक्षित हैं, उनका मनोभाव ऐसा जान पड़ता है कि धर्म, दर्शन आदि की वास्तव में कोई बुनियाद नहीं; उनकी इतनी ही उपयोगिता है कि वे संसार के मंगल-साधन की बलशाली प्रेरक शक्तियां हैं। यदि लोगों का ईश्वर की सत्ता में विश्वास रहेगा, तो वे सत् और नीति-परायण बनेंगे और इसीलिए अच्छे नागरिक होंगे। जिनके ऐसे मनोभाव हैं, इसके लिए उनको दोष नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वे धर्म के संबंध में जो शिक्षा पाते हैं, वह केवल सारशून्य, अर्थहीन अनंत शब्द समष्टि पर विश्वास मात्र है। उन लोगों से शब्दों पर विश्वास करते रहने के लिए कहा जाता है; क्या ऐसा कोई कभी कर सकता है? यदि यह संभव होता, तो मानव प्रकृति पर मेरी तिल मात्र श्रद्धा न रहती। मनुष्य चाहता है सत्य!

मनुष्य सत्य का स्वयं अनुभव करना चाहता है; और जब वह सत्य का साक्षात्कार कर लेता है, वेद कहते हैं, 'तभी उसके सारे संदेह दूर होते हैं, सारा तमोजाल छिन्न-भिन्न हो जाता है।'

मनुष्य सत्य का स्वयं अनुभव करना चाहता है; और जब वह सत्य का साक्षात्कार कर लेता है, हृदय के अंतरतम में उसका अनुभव कर लेता है, वेद कहते हैं, 'तभी उसके सारे संदेह दूर होते हैं, सारा तमोजाल छिन्न-भिन्न हो जाता है और सारी वक्रता सीधी हो जाती है।... हे अमृत पुत्रो, सुनो, मैंने अज्ञान के अंधकार से आलोक में जाने का रास्ता पा लिया है। जो समस्त तम के पार है, उसको जानने पर ही वहां जाया जा सकता है, मुक्ति का और कोई दूसरा उपाय नहीं।'

स्वामी विवेकानंद

राजनाथ सिंह | केंद्रीय रक्षा मंत्री

जब भाषणों को संग्रहित कर पुस्तक बनाई जाती है, तो वे पुस्तकें एक युग की बौद्धिक धरोहर बन जाती हैं। वे अध्ययन के अलावा नीति-निर्माण और शोध में उपयोगी होने के साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक भी बनती हैं।

अमेरिका का बयान हमारे लिए शर्मनाक

अमेरिकी विदेश विभाग ने 'एडवाइजरी' जारी करते हुए कहा है कि भारत में बढ़ते अपराध, और विशेषकर बलात्कार की घटनाओं को देखते हुए अमेरिकी महिलाएं अकेले भारत की यात्रा न करें। यह खबर समूचे भारत को शर्मसार करने के साथ-साथ चिंता में डालने वाली भी है। इसका मतलब है, अमेरिकी सरकार की नजर में भारत में अपराधियों और बलात्कारियों पर लगाम नहीं है। केंद्र व राज्य सरकारों को चेत जाना चाहिए। उनको इस प्रकार की घटनाओं पर कड़ा संज्ञान लेना चाहिए। आज तो यही लगता कि अपराधियों और बलात्कारियों में कानून व सजा का कोई खौफ नहीं है। ऐसे मामलों में गुनहगारों को तय समय-सीमा के भीतर कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, मगर ऐसा होता नहीं है, इसलिए अपराधियों के हौसले बुलंद रहते हैं। सोचने और समझने वाली बात यह है कि जिस देश में नवरात्रि में माता का पूजन व कन्याओं की पूजा की जाती है, उस देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। ऐसे में, यह पूजन भी दिखावा बनकर रह गया है! अगर यही स्थिति बनी रही और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार में कमी नहीं आई, तो दूसरे देश के लोग भारत आने से पहले 100 बार सोचेंगे। यह हमारे देश की छवि के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। हमें भूलना नहीं चाहिए कि पर्यटकों का फायदा हमें भी होता है। वे न केवल व्यापार, व्यवसाय अथवा पर्यटन स्थलों पर लोगों की कमाई कराते हैं, बल्कि इससे भारत सरकार को बहुमूल्य विदेशी धन भी मिलता है। ऐसे में, अमेरिकी एडवाइजरी के बाद अगर पर्यटकों की आमद में कमी आती है, तो इसका हमें नुकसान हो सकता है। हमारी सरकारों को बलात्कार जैसे मामलों से निपटने के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए।

हेमा हरि उपाध्याय, टिप्पणीकार

अमेरिका द्वारा अपने नागरिकों को यह एडवाइजरी जारी की गई है कि भारत में महिला सैलानी अकेले यात्रा न करें। इस शर्मनाक सलाह पर भारत सरकार का कोई बयान सामने नहीं आया। आज विश्व मीडिया में उदयपुर की एक खबर सुर्खियों में है, जिसमें पुष्पराज नामक व्यक्ति एक फ्रांसीसी महिला को अपने फ्लैट पर ले गया और नशा देकर उसके साथ जबर्दस्ती की। समाचारों के अनुसार, मेडिकल जांच में उससे जिना (गैरकानूनी यौन संबंध बनाने) किए जाने की पुष्टि हुई है और आरोपी पुष्पराज फरार हो गया है। बिकनी में घूम रही महिलाओं को नजरंदाज करने वाले समाज में यह खबर कितनी भयावह लग रही होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। यह कैसे देश और समाज का निर्माण हो रहा है, एक बार हम खुद इसका जवाब तलाश लें।

प्रमोद पाहवा, राजनेता

अनुलोम-विलोम

अमेरिकी एडवाइजरी

पहले अपना घर तो संभाल ले ट्रंप प्रशासन

यह विडंबना ही है कि अमेरिका अपने यहां के अपराधों को तो नजरअंदाज कर देता है, जबकि दूसरे देशों में गैर-जरूरी दखलंदाजी करता रहता है। इसका ताजा उदाहरण है, उसकी 'ट्रैवेल एडवाइजरी।' नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, साल 2022 में भारत में बलात्कार के 31,000 मामले दर्ज किए गए, जबकि अमेरिका में उस वर्ष यह संख्या डेढ़ लाख से कुछ ही कम 1.41 लाख दर्ज की गई। इसका अर्थ है कि भारत में महिलाएं जितनी असुरक्षित हैं, उससे चार गुना उनको अमेरिका में खतरा है। फिर भी, ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी नागरिकों, विशेषकर अकेली महिलाओं को भारत-यात्रा को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी है। ऐसी सलाहों का भला क्या औचित्य है? बेशक, भारत में महिलाओं के साथ यौन अपराध होते हैं और कई मामले तो दर्ज भी नहीं हो पाते, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि किसी देश की छवि के साथ खेल खेला जाए। वह भी तब, जब अपनी चादर में कई छेद हों। ट्रंप प्रशासन यदि अपने यहां अपराध पर अंकुश लगाने के बाद ऐसा कोई बयान जारी करता, तो समझा जा सकता था। लेकिन ऐसी किसी कोशिश के बजाय अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने आनन-फानन में अमेरिकी महिलाओं को अकेले भारत की यात्रा न करने की सलाह दे डाली।

दरअसल, यह सारी खुन्नस इस वजह से है कि भारत वैश्विक मंचों पर तेजी से उभरा है। आज हमारे प्रधानमंत्री को पूरी दुनिया गौर से सुनती है। भारत के बाजार में उतरने के लिए विश्व भर की कंपनियां व्याकुल हैं। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम दुनिया भर में सस्ता और सफल है। यहां की अर्थव्यवस्था तेज गति से बढ़ रही है और वैश्विक मंदी की स्थिति में भी यह देश बुलंदी से खड़ा रहता है। ऐसी सूरत में, ट्रंप प्रशासन का झुंझलाना लाजिमी है, क्योंकि उसे लग रहा होगा कि बमुश्किल साढ़े सात दशक पहले आजाद हुआ देश आज इतना आगे कैसे बढ़ गया? यही कारण है कि ऐसी-ऐसी तिकड़में अपनाई जाती हैं कि भारत के बढ़ते कदम कुछ देर के लिए ही सही, रोके जा सकें। मगर ऐसे लोग या देश शायद नहीं जानते कि भारत ऐसी मुश्किलों से नहीं घबराता। वह चुनौतियों को स्वीकार करने और उनका समाधान करने को उत्सुक रहता है। इसलिए, यदि आज भारत के खिलाफ एडवाइजरी जारी भी की गई है, तो उसका बहुत ज्यादा असर पर्यटन उद्योग पर नहीं पड़ेगा। भारत अपने अतिथि को देवता के तुल्य मानता है, इसलिए उम्मीद यही है कि अमेरिका जल्द ही मुंह की खाएगा और अपनी यह एडवाइजरी खुद वापस ले लेगा।

महिमा सिंह, टिप्पणीकार

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 18 अंक 111

सीपीटीपीपी में शामिल होने पर हो विचार

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने दुनिया के बाकी देशों के विरुद्ध छेड़ी गई कारोबारी जंग में 90 दिन का जो 'स्थगन' लागू किया था, उसकी अवधि आगामी 8 जुलाई को समाप्त हो जाएगी। माना जा रहा है कि उन्होंने जो जवाबी शुल्क लागू किए थे वे उस दिन दोबारा प्रभावी हो जाएंगे। अमेरिकी प्रशासन ने वादा किया था कि उसके पहले कुछ व्यापार समझौते पूरे कर लिए जाएंगे और कई अवसरों पर कहा गया कि 90 अलग-अलग वार्ताएं चल भी रही हैं। परंतु अब तक केवल यूनाइटेड किंगडम के साथ ही समझौता हो सका है। भारत समेत अन्य देशों के साथ उसकी बातचीत सही ढंग से चलने के कोई संकेत नहीं हैं। चाहे जो भी हो ट्रंप द्वारा लागू किया गया 10 फीसदी का बुनियादी शुल्क बरकरार रहेगा। यह शुल्क यूनाइटेड किंगडम के साथ हुए समझौते का भी हिस्सा है। इस शुल्क ने अमेरिकी प्रशासन को मजबूती प्रदान की है क्योंकि इसकी बदौलत अरबों डॉलर का राजस्व आया है जो कर कटौती योजनाओं की भरपाई में मदद कर रहा है। मुद्रास्फीति पर भी इसका बहुत अधिक असर नहीं हुआ है। ट्रंप ने वैश्विक व्यापार को जो नुकसान पहुंचाया फिलहाल पश्चिम एशिया में व्याप्त अव्यवस्था के चलते वह चिंता का मुख्य विषय नहीं है लेकिन हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। बहुत जल्द भारत और शेष विश्व को अधिक विभाजित व्यापार व्यवस्था का सामना करना पड़ेगा।

इन हालात में भारत के लिए आगे की राह एकदम स्पष्ट है: उसे अमेरिका के साथ ऐसे समझौते का प्रयास जारी रखना होगा जो उसकी प्रतिस्पर्धी बढ़त में इजाफा करे। इसके साथ ही उसे व्यापार के अनुकूल दूसरे देशों के साथ ही अन्य व्यापार समझौतों पर भी हस्ताक्षर करना होगा। सरकार पहले ऐसे समझौतों को लेकर शंकालु नजर आती थी लेकिन हाल के दिनों में उसने विभिन्न समझौतों को लेकर सकारात्मक इच्छा जताई है। बीते वर्षों में ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात तथा यूनाइटेड किंगडम आदि देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों तथा व्यापक आर्थिक साझेदारियों पर हस्ताक्षर किए गए। परंतु साफ कहा जाए तो ये समझौते इतने बड़े नहीं हैं कि अमेरिका द्वारा फैलाई जा रही अव्यवस्था की भरपाई कर सकें। ऐसे में सबसे पहले यह जरूरी है कि यूरोपीय संघ के साथ चल रही मौजूदा वार्ता को प्रधानमंत्री द्वारा तय समयसीमा में यानी वर्ष के अंत तक पूरा कर लिया जाए। किसी भी अन्य समझौते से अधिक इस समझौते में साझा समृद्धि की गुंजाइश है।

परंतु मूल्य श्रृंखलाओं में शामिल होने के लिए भारत को अपने पूर्व के विनिर्माण केंद्रों पर भी विचार करना होगा। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री ने हाल ही में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों यानी आसियान देशों को चीन की 'बी टीम' कहा है। ऐसे बयान प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। तथ्य यह है कि आसियान देशों तथा चीन को छोड़कर अन्य एशियाई देशों के साथ एकीकरण जरूरी है तभी भारत अपने विनिर्माण में सुधार कर पाएगा और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बन पाएगा। आर्थिक नजरिये से इसका मतलब यह हुआ कि हमें क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी यानी आरसेप जैसे बड़े समझौतों में शामिल होना चाहिए। परंतु चूंकि चीन आरसेप का हिस्सा है, इसलिए शायद इसे राजनीतिक दृष्टि से तब तक व्यवहार्य न माना जाए जब तक कि उसके साथ रिश्ते सुधर नहीं जाते। हालांकि प्रशांत पार साझेदारी के लिए व्यापक एवं प्रगतिशील समझौते यानी सीपीटीपीपी को लेकर तो यह आपत्ति भी नहीं बनती। भारत को इसमें शामिल होने का आवेदन करना चाहिए। इसमें शामिल होने से जापान और कोरिया जैसे बड़े निवेशकों को भारतीय बाजार के साथ जोड़ने में मदद मिलेगी। इससे घरेलू नियामकीय सुधारों के लिए भी स्पष्ट खाका तैयार करने में मदद मिलेगी ताकि भारतीय नियमन को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाया जा सके और निर्यात को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके। इस प्रक्रिया में समय लग सकता है लेकिन वैश्विक व्यापार ढांचे में व्याप्त अनिश्चितता और अव्यवस्था को देखते हुए यह महत्त्वपूर्ण है। ऐसा करके ही भारत एक खास दिशा को लेकर अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित कर सकता है।

महान नेतृत्व की क्या हो असली पहचान

असल बात है अहंकार से ऊपर उठना। अहं और क्रोध ही सब कुछ नहीं हैं। वे नेतृत्व की इकलौती राह भी नहीं हैं। ईरान-इजरायल संघर्ष के संदर्भ बता रहे हैं अजय शाह

हममें से अधिकांश लोग सरकारों को लेकर एक हल्के संशय के शिकार रहते हैं। हम सत्ता प्रतिष्ठान से उम्मीद करते हैं कि वह गर्व और राष्ट्रवाद के मिश्रण के साथ काम करेगा। ऐसे में यकीनन हम सोचते हैं कि ईरान की सरकार जवाबी कार्रवाई करेगी और वह इजरायल की सैन्य शक्ति का मुकाबला करने का प्रयास करेगी। वह परमाणु हथियार बनाने के प्रयत्न भी जारी रखेगी।

ऐसा करके हम सत्ता प्रतिष्ठान के हितों की पुष्टि कर देते हैं किंतु जनता के हितों का मामला रह जाता है। राजनीति विज्ञान और अंतरराष्ट्रीय संबंधों की एक अनिवार्य अंतर्दृष्टि यह है कि मुख्य पक्ष और प्रतिनिधि के बीच विशिष्ट अंतर होता है। यानी जनता के हितों और सत्ता के हितों में अंतर होता है। खामेनेई की सत्ता जिस प्रकार गर्व और राष्ट्रवाद की तलाश में है उसने ईरान के लोगों के लिए तबाही के हालात बना दिए हैं। ईरान के लिए सही रणनीति यह है कि वह अगले 50 सालों तक एक सामान्य देश बन जाए। वह जनता के विरुद्ध राज्य की हिंसा से दूरी बना ले, समाज और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए काम करे, एक सामान्य देश बनने की कोशिश करे और दुनिया के अन्य देशों के साथ सहज रिश्ते कायम करे। इससे उसे एक महान देश के रूप में उभरने में मदद मिलेगी जो जनता के हित में होगा। महान नेता वे होते हैं जो अपनी छवि, सरकार की स्थिरता, विचारधारा आदि के संकीर्ण विचारों से ऊपर निकलकर ऐसे काम करें जो जनता के हित में हों। इतिहास में ऐसे तमाम उदाहरण मौजूद हैं।

कांग्रेस नेतृत्व के लिए यह आसान होता कि वह 1947 में ब्रिटिशों के प्रति शत्रुता का व्यवहार रखती। उस समय अधिकांश औपनिवेशिक देशों का स्वतंत्रता के बाद यही रुख था। परंतु समझदारी दिखाते हुए कांग्रेस नेतृत्व ने ब्रिटिशों के साथ सौहार्दपूर्ण रिश्ते कायम रखे और हिंसा का इस्तेमाल नहीं होने दिया। यहां नाराज जनता के गुस्से को संतुष्ट करने के बजाय भारत के निर्माण को तवज्जो दी गई जो उदारता का प्रतीक था।

चार्ल्स द गाल फ्रांस में 1958 में इस वादे के साथ सत्ता में आए कि अल्जीरिया को फ्रांसीसी उपनिवेश बना रहने दिया जाएगा। परंतु उन्हें यह समझ में आ गया कि यह फ्रांस के लिए नुकसानदेह है। उन्होंने 1962 में अल्जीरिया की आजादी को स्वीकार कर लिया हालांकि व्यक्तिगत रूप से उन्हें इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। यह भी नाराज जनता को खुश करने के बजाय फ्रांस के निर्माण के उदात्त भाव का उदाहरण था।

एफ डब्ल्यू डी क्लार्क को दक्षिण अफ्रीका की रंगभेदी नीति विरासत में मिली थी। वह चाहते तो क्रोध की राजनीति और दुनिया को नकारने की राजनीति जारी रख सकते थे। परंतु उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया था कि यथास्थिति उनके देश की जनता के लिए कितनी मुश्किलें ला रही थी। उन्होंने 1990 में नेल्सन मंडेला को जेल से रिहा कर दिया और 1994 में लोकतांत्रिक परिवर्तन होने दिया तथा प्रभावी ढंग से स्वयं को तथा अपनी पार्टी को सत्ता से बाहर जाने दिया।

यह भी अपने जनाधार को खुश करने के बजाय दक्षिण अफ्रीका के निर्माण का उदात्त भाव था। मिखाइल गोर्बाचेव भी ऐसे ही एक नायक हैं जिन्होंने रूस के सामान्य देश बनने की संभावनाएं तैयार कीं जबकि वह चाहते तो पश्चिम की बराबरी की होड़ करते हुए सत्ता में बने रहते। अनवर सादात ने भी 1977 में इजरायल के साथ शांति कायम करने के क्रम में समूचे अरब क्षेत्र के नेता का अपना कद कुर्बान कर दिया। इजरायल में इत्जियाक राबिन ने यासर अराफात के साथ बातचीत की और कथित गर्व का रास्ता त्यागकर 1993 में ओस्लो समझौता किया। इसके बदले में उन्हें क्या मिला? सादात की 1981 में और राबिन की 1995 में हत्या कर दी गई। ये हत्याएं उनके ही देशों में मौजूद दक्षिण-पंथियों ने की।

तंग श्याओ फिंग ने माओ की जगह ली और वह चाहते तो और माओवाद जारी रख सकते थे। पश्चिम के प्रति नफरत, रणनीतिक स्वायत्तता और घरेलू कुलीनों के प्रति घृणा के मिश्रण के साथ वह माओवाद के गौरव को आगे बढ़ा सकते थे लेकिन इसके बजाय उन्होंने नारा चुना, 'अपनी ताकत को छिपाओ और सही समय की प्रतीक्षा करो'। उन्होंने पश्चिम से संपर्क बनाया, कुलीनों के उभार का समर्थन करते हुए नारे दिए 'अमीर बनना गौरव की बात है' और 'पहले कुछ लोगों को अमीर बनने दो।' यह भी नाराज प्रशंसकों का मन रखने के बजाय चीन के निर्माण के भाव से संचालित था।

ये तमाम उदाहरण बताते हैं कि कैसे महान नेताओं ने जनता के हितों का ध्यान रखा अपनी सत्ता का नहीं। उन्होंने एक सामान्य देश बनाने के क्रम में गर्व को जाने दिया, उन्होंने कम हिंसा वाला माहौल बनाया और ऐसी स्थितियां निर्मित कीं जहां 50 साल तक टिकाऊ आर्थिक वृद्धि हासिल हो सके।

यकीनन ऐसे नाकाम नेता भी रहे हैं जिन्होंने गर्व और राष्ट्रवाद पर जोर दिया और अपने जनाधार को खुश करने की कोशिश की। लियोपोल्डो गैल्टियेरी ने 1982 में फॉकलैंड द्वीपों पर हमला किया ताकि घरेलू औपनिवेशिक विरोध की भावना को भुनाया जा सके। इसके चलते 1983 में उनकी सत्ता का ही पतन हो गया। नासिर भी खामेनेई की तरह ही टकराव पसंद करते थे। उन्हें 1967 में छह दिवसीय युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था। रॉबर्ट मुगाबे ने जिंबाब्वे में एक (लोकप्रिय!) हिंसक भूमि सुधार कार्यक्रम का नेतृत्व किया जिसने कृषि उत्पादन को ध्वस्त कर दिया और महंगाई बहुत अधिक बढ़ गई। मूखर्तापूर्ण गौरव का स्वर्ण पदक व्लादिमिर पुतिन को जाता है जिन्होंने रूस के एक सामान्य देश बनने की संभावना को ही समाप्त कर दिया, जबकि वह यूरोप के स्तर का एक गुणवत्तापूर्ण लोकतांत्रिक देश तथा यूरोपीय संघ और उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) का सदस्य भी बन सकता था।

यह सही है कि ऐसे नेता होते हैं परंतु हमें नेतृत्व के ऐसे गुणों का सामान्यीकरण नहीं करना चाहिए। हमें इस नतीजे पर नहीं पहुंच जाना चाहिए कि केवल गौरवबोध ही काम करता है। नेतृत्व का सार इस बात में निहित है कि ऐसे काम किए जाएं जो सरकार के नहीं जनता के हित में हों।

खामेनेई की सत्ता ईरान के हालात को गर्व वाले नजरिये से देख सकती है। वह यह सोच सकती है कि ईरान के लोगों को जवाब देना चाहिए और परमाणु बम बनाना चाहिए। लेकिन यह ईरान के लोगों के लिए अच्छी रणनीति नहीं है। ऐसी कोई वजह नहीं है कि ईरान सरकार परमाणु बनाने की कीमत अपनी जनता की शांति और समृद्धि के रूप में चुकाए। ईरान को इजरायल या सुन्नी बहुल अरब देशों से शायद ही कोई खतरा है। उसे परमाणु हथियारों की आवश्यकता नहीं है। यहां बात केवल ईरान पर शासन कर रहे एक छोटे से समूह के अहं की है। पुरुषवादी अहं या सम्मान महत्त्वपूर्ण नहीं है। महत्त्वपूर्ण है ईरान को एक सामान्य देश बनाकर शांति और समृद्धि के हालात निर्मित करना।

(लेखक एक्सकेडीआर फोरम में शोधकर्ता हैं)

डंपिंग रोधी शुल्क से फायदे कम नुकसान ज्यादा

पिछले कई वर्षों से भारत सहित दुनिया के कई देश चीन से आयातित सस्ते सामान से अपने स्थानीय उद्योगों को होने वाले नुकसान को लेकर चिंतित रहे हैं। अमेरिका और चीन के बीच जारी व्यापार युद्ध के कारण हाल में यह चिंता और बढ़ गई है। 16 जून तक अमेरिका ने चीन के आयात पर प्रभावी शुल्क बढ़ाकर 55 फीसदी कर दिया है।

अमेरिका को निर्यात होने वाली वस्तुओं पर मोटा शुल्क लगने के बाद चिंता बढ़ गई है कि चीन अपने सामान दूसरे बाजारों में खपाना शुरू कर देगा। इसके जवाब में भारत जैसे कई देश अपने स्थानीय उद्योगों के हित सुरक्षित रखने के लिए डंपिंग-रोधी शुल्क (एडीडी) का इस्तेमाल कर रहे हैं।

भारत दुनिया में डंपिंग-रोधी शुल्कों का सबसे अधिक इस्तेमाल करने वाला देश बन गया है। यह न केवल चीन बल्कि दूसरे देशों के खिलाफ भी एडीडी का इस्तेमाल कर रहा है। सस्ते सामान देसी बाजार में आना चिंता का कारण जरूर है मगर भारत जिस तरह बड़े पैमाने पर एडीडी का इस्तेमाल कर रहा है उससे नई समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। इसे देखते हुए नीति निर्धारकों को एडीडी का इस्तेमाल सावधानी और पूरी सतर्कता के साथ करना चाहिए।

अंतरराष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग तब होती है जब कोई देश अपना सामान विदेशी बाजारों में उचित बाजार मूल्य से कम पर बेचना शुरू कर देता है। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) सीधे तौर पर डंपिंग को अनुचित नहीं मानता है मगर स्थानीय उद्योग को 'बड़ा नुकसान' पहुंचने की स्थिति में ही यह देशों को डंपिंग रोधी शुल्क लगाने की इजाजत देता है।

चीन डंपिंग रोधी शुल्क के निशाने पर सबसे अधिक रहा है। 2001 में डब्ल्यूटीओ में इसके शामिल होने के बाद डंपिंग रोधी मामलों को लेकर जितनी जांच शुरू हुई है उनमें 25 फीसदी मामलों में चीन लिप्त है। दूसरी तरफ, भारत कुछ उन विकासशील देशों में शामिल है जिन्होंने लंबे समय से एडीडी लगाने के मामले में कोई कोताही नहीं बरती है। वर्ष 1995 से 2023 तक भारत ने 1,100 डंपिंग-रोधी मामलों की जांच शुरू की (अमेरिका और यूरोपीय संघ से भी अधिक) और इनमें न केवल चीन बल्कि यूरोपीय संघ, स्विट्जरलैंड, दक्षिण कोरिया, जापान सभी को निशाना बनाया गया है। वर्ष 2024 में भारत ने व्यापारिक संतुलन बहाल रखने के लिए 47 जांच की शुरुआत की जिनमें 37 चीन के उत्पादों जैसे एल्युमीनियम फॉयल, वैक्यूम फ्लास्क और इस्पात से संबंधित थे।

कुछ मामलों में एडीडी स्थानीय उद्योगों को सुरक्षित रखने में मदद कर सकते हैं मगर उनके इस्तेमाल के साथ कुछ खामियां भी जुड़ी हैं। सबसे पहले तो एडीडी लगाने से स्थानीय उद्योगों के लिए लागत बढ़ सकती है जिससे उनकी प्रतिस्पर्द्धी क्षमता पर प्रतिकूल असर होगा। मार्च 2024 में भारत ने चीन और हॉन्ग कॉन्ग से आयातित प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (पीसीबी) पर 30 फीसदी एडीडी लगा दिया था। इससे आईटी हार्डवेयर विनिर्माता कंपनियों के लिए उत्पादन लागत 1-4 फीसदी तक बढ़ गई। इनमें से कई कंपनियां सरकार की उत्पादन संबंधी प्रोत्साहन (पीएलआई) का हिस्सा थीं। मगर बढ़ी लागत से उनके मुनाफे और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्द्धा करने की उनकी क्षमता को नुकसान पहुंचा। इससे विनिर्माण और निर्यात बढ़ाने के लिए शुरू पीएलआई योजना के उद्देश्य भी प्रभावित हुए। घरेलू पीसीबी आपूर्तिकर्ता गुणवत्ता से जुड़े मुद्दों के कारण पेश चुनौतियों का मुकाबला नहीं कर पाए जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स एवं लाइटिंग कंपनियों को ऊंची लागत का वहन करना पड़ा या उन्हें उपभोक्ताओं पर इसका बोझ डालना पड़ा।

राजेश्वरी सेनगुप्ता और निहारिका यादव

दूसरी बात, एडीडी सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) की सेहत पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। एमएसएमई पहले ही नियमों के अनुपालन के बोझ से परेशान चल रहे हैं। बड़ी कंपनियां तो रियायतों के लिए सरकार पर दबाव भी डाल सकती हैं मगर एसएमएमई के पास ऊंची लागत वहन करने या कारोबार बंद करने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं बचता है। जब भारत ने 2017 में बांग्लादेश और नेपाल से जूट रेशों और परिधान के आयात पर एडीडी लगा दिया तो भारतीय जूट मिलों को तत्काल फायदा मिला मगर इस कदम से छोटे पैकेजिंग एवं परिधान कारोबारों को नुकसान पहुंचा। इनमें केवल एक संयंत्र से काम करने वाली कई इकाइयों को बढ़ी उत्पादन लागत से जूझना पड़ा।

तीसरी बात, एडीडी वृहद राष्ट्रीय नीति उद्देश्यों के साथ टकराव भी उत्पन्न कर सकते हैं। भारत ने 2024 में स्थानीय उत्पादकों को चीन से आयातित सोलर ग्लास की मार से बचाने के लिए उस पर एडीडी लगा दिया। इससे सोलर फोटोवोल्टिक (पीवी) मॉड्यूल के दाम 10-12 फीसदी तक बढ़ गए। इसका नतीजा यह हुआ कि परियोजना लागत 7-8 फीसदी बढ़ गई जिससे विनिर्माताओं (डेवलपर) को अनुबंधों पर दोबारा बातचीत करनी पड़ी और बड़ी परियोजनाएं टालनी पड़ीं। इससे स्वच्छ ऊर्जा की तरफ कदम बढ़ाने की भारत की गति पर भी प्रतिकूल असर हुआ। एडीडी लगाने से सौर ऊर्जा महंगी हो गई और इसमें (सौर ऊर्जा) निवेशकों की दिलचस्पी कम हो गई और अक्षय ऊर्जा उत्पादन का राष्ट्रीय लक्ष्य प्राप्त करने की राह मुश्किल हो गई।

सार यह है कि बार-बार एडीडी लगाने से कारोबार एवं व्यवसायों के लिए अनिश्चितता बढ़ती है और उन्हें दीर्घ अवधि की योजना तैयार करने में परेशानी पेश आती है। पिछले पांच वर्षों के दौरान भारत ने 418 उत्पादों (जिनमें ज्यादातर रसायन क्षेत्र में थे) के खिलाफ 133 डंपिंग-रोधी कदम उठाए हैं। जो कंपनियां कच्चे माल के स्रोत के रूप में इन रसायनों पर निर्भर रहती हैं उन पर अचानक शुल्क लगने की तलवार लटकी रहती हैं। इसका नतीजा कीमतों में उतार-चढ़ाव और आपूर्ति तंत्र में बाधा के रूप में सामने आता है। यह भी सच है कि चीन का अनुचित व्यापार व्यवहार चिंता का वास्तविक कारण बना हुआ है और डंपिंग के कुछ खास उदाहरण स्थानीय कारोबारियों को नुकसान की स्थिति में डाल देते हैं।

अब प्रश्न यह है कि भारत को क्या करना चाहिए? भारत के नीति निर्धारकों को एडीडी का इस्तेमाल सावधानीपूर्वक करना चाहिए और तभी करना चाहिए जब ऐसा करने की ठोस वजह एवं सबूत उपलब्ध हों। इस बात का ठोस प्रमाण होना जरूरी है कि विदेशी सामान उचित मूल्य से नीचे भारतीय बाजार में बेचे जा रहे हैं जिससे उन उद्योगों को गंभीर नुकसान पहुंच रहा है जहां भारत तुलनात्मक रूप से मजबूत स्थिति में है। संबंधित क्षेत्रों पर लागत-लाभ का विश्लेषण भी किया जाना चाहिए। 'आर्थिक हित परीक्षण' इसका एक उपयोगी तरीका हो सकता है जिसका इस्तेमाल ब्रिटेन करता है। 'आर्थिक हित परीक्षण' के जरिये उत्पादकों, उपभोक्ताओं और डाउनस्ट्रीम (परिवहन एवं वितरण) कंपनियों की आवश्यकताओं में संतुलन साधने और भारत को श्रेष्ठ वैश्विक व्यवहारों से जोड़ने में मदद मिलेगी। इससे कुछ बड़ी कंपनियों को आयात रोकने के लिए एडीडी का बेजा इस्तेमाल करने से भी रोका जा सकेगा। पिछले तीन वर्षों के दौरान एडीडी से जुड़े एक तिहाई मामले ऐसे थे जो इक्की-दुक्की घरेलू कंपनियों की शिकायतों पर आधारित थे। यह इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि कभी-कभी एक-दो कंपनियों का दबदबा बरकरार रखने के लिए भी एडीडी इस्तेमाल में लाए जाते हैं। दुनिया सहित भारत में भी संरक्षणवाद तेजी से बढ़ रहा है और इसे देखते हुए एडीडी को इसका जरिया बनने से रोका जाना चाहिए। नीति निर्धारकों को उन सुधारों पर ध्यान देना चाहिए जो स्थानीय कंपनियों में प्रतिस्पर्द्धा करने की क्षमता बढ़ाते हैं। इन सुधारों में बेहतर बुनियादी ढांचा, सरल नियम और कारक बाजार (फैक्टर मार्केट) में बदलाव शामिल हैं। विनिर्माण को ताकत देने और व्यापार से लाभान्वित होने के लिए भारत को वैश्विक आपूर्ति व्यवस्था का हिस्सा बनना चाहिए न कि उससे दूरी बनानी चाहिए। इसके लिए एडीडी जैसे उपायों का सावधानी और सूझबूझ के साथ इस्तेमाल करना चाहिए।

(राजेश्वरी सेनगुप्ता आईजीआईडीआर, मुंबई में अर्थशास्त्र की सहायक प्राध्यापक और निहारिका यादव द एशिया ग्रुप में सहायक हैं।)

आपका पक्ष

नशीले पदार्थों के प्रति संगठित होकर खड़ा हो समाज

हर वर्ष 26 जून को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य समाज खासकर युवाओं को नशे के घातक प्रभावों से जागरूक करना और उनके जीवन को नशामुक्त बनाना है। आज नशीली दवाओं की तस्करी एक वैश्विक समस्या बन चुकी है, जिसे धन के लालची लोगों और संगठित अपराधों का समर्थन मिल रहा है। तस्कर युवाओं को पहले मुफ्त में नशा देकर इसकी लत लगाते हैं और फिर उन्हें अवैध गतिविधियों में धकेल देते हैं। इससे न केवल उनकी सेहत पर असर पड़ता है और भविष्य तबाह होता है, बल्कि उनके परिवार और समाज भी प्रभावित होते हैं। नशे की गिरफ्त में आए युवा अपराध, आत्महत्या, मानसिक विकार और सामाजिक बहिष्कार का शिकार हो जाते हैं। भारत में नशीले पदार्थों की रोकथाम के लिए सख्त कानून

नशीली दवाओं की तस्करी आज एक वैश्विक समस्या बन चुकी है और इसे संगठित अपराधों का समर्थन मिल रहा है

मौजूद हैं, फिर भी सीमापार तस्करी, ड्रोन व अन्य गुप्त तरीकों से नशे की आपूर्ति होती रहती है। पंजाब, महाराष्ट्र और उत्तर-पूर्वी राज्यों में यह समस्या विशेष रूप से गंभीर है। इस संकट से लड़ने के लिए केवल कानून ही नहीं, बल्कि सामाजिक जागरूकता, पारिवारिक सहयोग और शैक्षिक संस्थानों की सक्रिय भूमिका भी आवश्यक है। स्कूलों और कॉलेजों में नशा विरोधी अभियान चलाए जाने चाहिए और युवाओं को खेल, संगीत व रचनात्मक गतिविधियों की ओर प्रेरित करना चाहिए। यदि समाज संगठित होकर इस बुराई के विरुद्ध खड़ा हो जाए, तो हम आने वाली पीढ़ियों को एक स्वस्थ, सुरक्षित और उज्ज्वल भविष्य दे सकते हैं। केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर नशे के खिलाफ सही मायने में जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, जिसमें सही मायने में युवाओं और किशोरों को नशे के दुष्परिणाम के प्रति सचेत किया जा सके। सरकारें आज भी अभियान चला रही हैं मगर उसके नतीजे ज्यादा सफल नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए, सरकार को इस बारे में नए तरीके से सोचने की जरूरत है, जिससे नशे के दुष्परिणामों से युवाओं और किशोरों को सचेत किया जा सके।

सुभाष बुड़ावन वाला, रतलाम

बस्तियों से दूर होने चाहिए हवाई अड्डे

अहमदाबाद में धरती से बहुत कम ऊंचाई पर हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हुआ। धरती या विमान के अंदर से रिमोट कंट्रोल द्वारा सॉफ्टवेयर या यांत्रिक गड़बड़ी की आशंका हो सकती है। अतः विमान के अंदर रिमोट कंट्रोल्ड सिग्नलों को निष्क्रिय करने की व्यवस्था जरूरी है। बस्तियां एयरपोर्ट से दूर हों। टेक ऑफ उस दिशा में करें जिधर बस्तियां दूर हो और टेक ऑफ के बाद विमान आवश्यक दिशा में मुड़कर जा सकते हैं। एयरपोर्ट की निकटस्थ इमारतों का ऊपरी हिस्सा ऐसा हो, जो ऊपर से विमान गिरने की स्थिति में नीचे वाली मंजिलों को सुरक्षित रखे। एयरपोर्ट के निकटस्थ रहवासी क्षेत्रों और अन्य संवेदनशील इन्फ्रास्ट्रक्चर के पास अग्निशमन केंद्र व अस्पताल आदि होने चाहिए।

ललित दुबे, रतलाम, मध्य प्रदेश

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

नीदरलैंड के हेग में आयोजित उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) के सम्मेलन में शामिल 32 देशों के नेता। इस दौरान विभिन्न मसलों पर चर्चा की गई और कहा गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के दबाव के बाद नाटो नेता रक्षा खर्च में भारी वृद्धि पर सहमत हुए।

आपातकाल की याद

लोकतंत्र पर धब्बा

आपातकाल की याद भारतीय लोकतंत्र पर लगे धब्बे के रूप में सामने आती है। लोकतंत्र एक शक्तिशाली, पर संवेदनशील राजनीतिक व्यवस्था है। इसे सचमुच प्रभावी बनाने के लिए इसे पालने-पोसने और इसकी संस्थाओं को मजबूत बनाने की जरूरत होती है। भारत को 25 जून, 1975 को स्वेच्छारिता के थोड़े समय का सामना करना पड़ा था। यह तिथि भारत की स्मृति में ऐसे क्षण के रूप में है, जब तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के इशारे पर आपातकाल घोषित कर दिया था। पचास साल बाद भी उस रात की काली छाया अब भी राष्ट्र की लोकतांत्रिक चेतना पर प्रहार करती है। इसी दिन प्रधानमंत्री ने राष्ट्रव्यापी आपातकाल लगा कर नागरिक स्वतंत्रताओं को स्थगित कर दिया था, राजनीतिक विरोधियों को जेल में बंद कर दिया था तथा प्रेस पर सेंसरशिप थोप दी थी। इसके बाद अगले 21 महीने तक संविधान में अंतर्निहित लोकतांत्रिक मूल्यों पर गंभीर प्रहार किए गए। इस काले अध्याय को याद करने का उद्देश्य उन लोगों की भावना का सम्मान करना है जिन्होंने इसका विरोध किया था। केन्द्र सरकार ने हर साल 25 जून को 'संविधान हत्या दिवस' के रूप में याद करने का निर्णय किया है क्योंकि इसी दिन संविधान के शब्दों और आत्मा पर प्रहार किया गया था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक बयान में कहा है कि ये यादें एक चेतावनी के रूप में सामने आएंगी कि भारत के संविधान को कुचलने पर क्या होता है। आपातकाल का समय हमें अत्यन्त कठोर रूप से याद दिलाता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थायें बहुत संवेदनशील तथा क्षणभंगुर होती हैं और सत्ता पर नियंत्रण एवं संतुलन समाप्त करने से वे बहुत कमजोर हो जाती हैं। उस समय नागरिकों के मूलाधिकारों की गारंटी करने वाला संविधान एक सुविधाजनक वस्तु बन गया था।

लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मानी जाने वाली प्रेस को आपातकाल ने झकझोर दिया था। जजों पर दबाव डाला गया था, आलोचकों को जेल में बंद कर दिया गया था तथा आम नागरिक भय के माहौल में रह रहे थे। उस समय मत-भिन्नता को विश्वासघात का जाने लगा था तथा अधिकारी पर बाल उठाने पर जेल जाने का खतरा था। इसके बावजूद इस अंधेरे समय में प्रतिरोध की ज्वाला लगातार जलती रही। विपक्षी नेताओं, छात्रों, एक्टिविस्टों, पत्रकारों तथा असंख्य आम भारतीय नागरिक इसके खिलाफ मजबूती से खड़े रहे। गिरफ्तारियों, उत्पीड़न और राज्य की निगरानी के बावजूद उन्होंने अपनी आवाज बंद करना स्वीकार नहीं किया। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनके अखंड विश्वास तथा साहस के कारण आखिरकार सामान्य स्थिति बहाल हुई। 1977 में चुनाव होने पर भारत की जनता ने एक असाधारण फैसला दिया। उन्होंने सत्तारूढ़ दल को सत्ता से उखाड़ फेंका तथा लोकतांत्रिक आदर्शों में अपने विश्वास की पुनः पुष्टि की। लोकसभा ने अपने प्रस्ताव में आपातकाल की निन्दा करते हुए इसे भारतीय इतिहास का 'काला अध्याय' बताया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने लोकतंत्र बहाली के लिए संघर्ष करने वाले लोगों की शक्ति और दृढ़ता की प्रशंसा की है। उन्होंने देश को याद दिलाया है कि ऐसी सतर्कता केवल एक समय का काम नहीं, बल्कि निरंतर लागू रहने वाला कर्तव्य है। आपातकाल को याद करना केवल एक कड़वे क्षण को याद करना नहीं, बल्कि यह प्रतिबद्धता भी है कि हम इसे कभी नहीं भूलेंगे। यह याद दिलाता है कि लोकतंत्र अपने आप आगे नहीं बढ़ता है। इसके लिए प्रयास, जागरूकता तथा सर्वोपरि रूप से मौन रहना सुरक्षित होने पर भी बोलने के साहस की आवश्यकता होती है।

आपातकाल के 50 साल बीतने तथा 'संविधान हत्या दिवस' के अवसर पर हमें प्रतीकात्मक स्मृति से आगे बढ़ते हुए इसे लोकतांत्रिक संस्थानों की रक्षा की सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि तथा समाज में संवाद एवं खुलेपन को प्रोत्साहन के रूप में देखना चाहए। हमें समाज के सभी वर्गों में समानता एवं सद्भावना तथा विविधता के प्रति सम्मान बढ़ाने के प्रयास करने चाहिए। आपातकाल के अंधकारमय दिनों को याद कर हम प्रकाश को सुरक्षा देते हैं।

आपातकालः चंद्रशेखर की जेल डायरी

कांग्रेस में चंद्रशेखर अकेले ऐसे व्यक्ति थे, जो पार्टी की सबसे महत्वपूर्ण व निर्णायक समिति के चुने गए सदस्य थे। उन्हें इंदिरा जी ने आधी रात को गिरफ्तार करवाया। उस चंद्रशेखर को समझने के लिए उनकी 'जेल डायरी' सबसे प्रामाणिक स्रोत है।

हरिवंश
(लेखक, राज्यसभा के उपसभापति हैं)

यह आपातकाल की पचासवीं वर्षगांठ है। कांग्रेस में चंद्रशेखर अकेले ऐसे व्यक्ति थे, जो पार्टी की सबसे महत्वपूर्ण व निर्णायक समिति (कांग्रेस वर्किंग कमिटी) के चुने गए सदस्य थे। उन्हें इंदिरा जी ने आधी रात को गिरफ्तार करवाया। उस चंद्रशेखर को समझने के लिए उनकी 'जेल डायरी' सबसे प्रामाणिक स्रोत है। आपातकाल में मुल्क में केवल दो ही नेता 'तन्हाई' में रखे गए। चंद्रशेखर और जॉर्ज फर्नांडिस। चंद्रशेखर का स्वाभिमान व व्यक्तित्व अनूठा था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें रोहतक (हरियाणा) ले जाया गया। वहां के एक बड़े नेता (शायद मुख्यमंत्री बंसी लाल, जो चंद्रशेखर के शुभचिंतक और मित्र थे) ने कलेक्टर को निर्देश दिया कि स्वास्थ्य के आधार पर चंद्रशेखर को अस्पताल में भर्ती करवाया जाए। कलेक्टर ने उनसे मुलाकात की। डॉक्टर ने बार-बार कहा कि वे अस्वस्थ हैं, लेकिन चंद्रशेखर ने हर बार दो टूक जवाब दिया, 'मैं बिल्कुल ठीक हूं।' कलेक्टर ने अलग ले जा कर समझाने की कोशिश की। जेल की हालत ठीक नहीं, आप वहां कैसे रहेंगे? चंद्रशेखर का जवाब उनके व्यक्तित्व को दर्शाता है। कहा, वह मेरे हितैषी हैं, उनके स्नेह के लिए धन्यवाद। बाहर निकलूंगा तो मित्रता निभाएंगे। कुछ दिनों बाद अचानक रात में उन्हें पटियाला जेल भेज दिया गया।

चंद्रशेखर, रोहतक जेल में बंद थे। सुल्तान सिंह और जिलाधिकारी उनसे मिलने आए। कुछ सहूलियत देने की बात की। वह लिखते (27 जून, 1975) हैं, 'व्यक्तिगत आवश्यकताओं और सुविधाओं की बात चलायी। मैंने अस्वीकार कर दिया, पर मुझे अच्छा लगा। कम-से-कम इन्होंने खबर तो ली। कितने लोग हैं, जिनके लिए अब कदाचित् मेरा अस्तित्व ही नहीं है। मेरी बात छोड़ दें, घरवालों के साथ भी साधारण शिष्टाचार निभाना आवश्यक नहीं समझते। कितनी निकटता थी, पर कितने क्षुद्र हो सकते हैं ये लोग। उसमें कहे जानेवाले सभ्य और शिष्ट लोगों से अधिक संवेदनशीलता है, ममत्व है। अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को समझने की क्षमता है। यह सब उनकी डायरी में दर्ज है। भाषा, भाव, ज्ञान, बौद्धिक गहराई व लेखनशैली के लिहाज से 'जेल डायरी साहित्य' में यह श्रेष्ठ डायरियों में से एक है। चंद्रशेखर अपनी चीजों को सहेज कर रखने में बेहद लापरवाह थे। न व्यवस्था थी। इसी लिए उनसे जुड़े, उस दौर के दस्तावेज अब कम ही बचे हैं। न अखबारों की कतरनें ही हैं। वह करीब 19 महीने जेल में रहे।

आपातकाल हटा। तब पहली बार यह डायरी छपी। 1977 में। इसका विमोचन बड़ी सादगी से हुआ। इसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई मौजूद थे। बताते हैं, भवानीप्रसाद मिश्र और अज्ञेय जैसे साहित्यकारों ने इसकी भाषा-शैली और भाव की मुक्तकंठ प्रशंसा की। यह डायरी भारतीय राजनीति और नेताओं की असलियत समझने की साहित्यिक निधि है। पहले संस्करण की प्रतियां, सीमित थीं। 1986 में चंद्रशेखर से डायरी के पुनर्प्रकाशन की बात की। चंद्रशेखर ने मूल पांडुलिपि का जेरोक्स उपलब्ध कराया। हमने संपादित किया। 'कवि जी' (चंद्रशेखर के पुराने आत्मीय मित्र) को छपवाने का जिम्मा सौंपा गया। किन्हीं कारणों से काम योजनानुसार पूरा न हो सका। फिर भी, जो संस्करण छपा, उसका लोकार्पण हुआ। नामवर सिंह ने विमोचन किया। सादे समारोह में। अंतत दो खंडों में चंद्रशेखर के 75वर्ष पूरे होने पर यह छपी। 'मेरी जेल डायरी' नाम से। राजकमल प्रकाशन से। 2002 में। 1975 में आधी रात को आपातकाल लगने की घोषणा हुई। जेपी की गिरफ्तारी की सूचना मिली। चंद्रशेखर ने पूछताछ की। जेपी की गिरफ्तारी का कारण जानना चाहा। वह लिखते (26 जून, 1975) हैं, 'एक ही सवाल मन में उठता रहा। क्या हो रहा है? क्या करूं? कुछ राह नजर नहीं आती।' थाने में ही एक पुलिस अधिकारी ने बताया, आपके खिलाफ भी वारंट है। एक अधिकारी ने अलग ले जाकर कहा कि आपके लिए संदेश है। एक टेलिफोन नंबर दिया। बात कर लीजिए। उन्होंने वहीं से फोन किया। विजय संघवी (उस दौर के बड़े पत्रकार), तब थाने में ही मौजूद थे। उन्होंने अपनी किताब में भी इसका जिक्र किया है। लिखा है, 'मैंने दूर से देखा, चंद्रशेखर ने फोन पटक दिया और जेल चले गए।'

दो प्रामाणिक स्रोतों या किताबों में ये सूचनाएं मौजूद हैं। इंदिरा जी के मामले में राजनारायण जी के वकील रहे व बाद में लोकदल के सांसद जे.पी. गोयल ने तथ्यों के हवाले से इसे लिखा है। अपनी किताब, 'सेविंग इंडिया फ्रॉम इंदिरा: अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इमरजेंसी' में। दूसरी ओर फोन पर मैडम गांधी खुद थीं। उन्होंने चंद्रशेखर से कहा कि आप इसका (इमरजेंसी का) समर्थन करिए। कल आपको उप प्रधानमंत्री बनाएंगे। कैबिनेट में शामिल करेंगे। विजय संघवी ने भी इसे अपनी किताब, 'द कांग्रेस – इंदिरा टू सोनिया गांधी' में दर्ज किया है।

चंद्रशेखर को वारंट पा कर संतोष हुआ। पहले वह दुविधा में थे। लेकिन परिस्थितियों ने उन्हें रास्ता दिखाया। उन्होंने लिखा (26 जून, 1975), 'जो कुछ हो रहा था, उसका साथ देना मेरे लिए असंभव था। कैसे कोई कह दे कि भारत का भविष्य एक व्यक्ति पर निर्भर है। इतनी चाटुकारिता, इतनी दासता अपने से संभव नहीं।' खुद चुनी हुई, इस गिरफ्तारी ने उन्हें मानसिक राहत दी। लेकिन आजादी छीनने का दर्द भी था। वह लिखते (26 जून, 1975) हैं, 'लोगों से मिलना, उनकी सुनना, उन्हें सुनाना—यह सब बंद हो गया। बेचैनी हुई। ऐसा लगा, जैसे कुछ लोग अनिश्चित काल के लिए बिछड़ गए।'

वे लिखते (13 अक्तूबर, 1975) हैं कि एक दिन उनसे मिलने आए एक जेल कर्मचारी ने कहा, 'किसी गलतफहमी के कारण मुझे गिरफ्तार कर लिया गया है, किसी ने चुगली की होगी। इंदिरा जी को समझ में बात आ जायेगी और मैं जल्द ही इस जेल से चला जाऊंगा। बड़े विश्वास के साथ वह यह बात कहता था। किसी संत का चेला है, उस संत ने इसे कहा था कि इंदिरा जी पुराने जन्म की कोई रानी हैं, बड़ा तप किया था उन्होंने, उन्हें कोई हिला नहीं सकता। मैं उसकी बात चुपचाप सुनता रहता था। आज वह अचानक मुझसे उलझ गया, कहने लगा कि मैं क्यों यहां पड़ा हूं? बाहर क्यों नहीं जाता? यहां रहकर क्या करता हूं? बाहर हजारों लोगों की मदद कर सकता था और इंदिरा जी को भी समझा सकता था मैंने कहा कि जेल में पड़े रहना किसे अच्छा लगता है, पर मैं क्या कर सकता हूं। क्या तुम चाहते हो कि मैं जेल में भेजे जाने के कारण इंदिरा जी से हाथ जोड़कर फरियाद करूं कि मुझे वे रिहा कर दें। फिर वह बोल उठा, नहीं।' जे.पी. गोयल ने एक और घटना का जिक्र किया है। अपनी किताब, 'सेविंग इंडिया फ्रॉम इंदिरा – अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इमरजेंसी' में। आपातकाल के दौरान सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा गांधी के खिलाफ याचिका थी। वकील वी.एम. तारकुंडे ने गोयल से कहा कि चंद्रशेखर से जेल में जा कर बात करें। वह कांग्रेस वर्किंग कमेटी के निर्वाचित सदस्य थे। अगर वह हेबियस कॉर्पस याचिका दायर करते, तो सुनवाई की गुंजाइश बनती। गोयल जेल में मिले। चंद्रशेखर ने साफ इनकार किया। बोले, 'यह मेरा नैतिक संघर्ष है। मैं अदालती लड़ाई नहीं लड़ूंगा।' यह थी उनकी सैद्धांतिक प्रतिबद्धता। डायरी में वह लिखते (23 अप्रैल, 1976) हैं, 'ब्रह्मानंद और शांति पटेल ने मुकदमा दायर करने की बात की। लेकिन मुझे यह उचित नहीं लगा। इस मुकदमेबाजी से क्या हासिल होगा?'

10-12 महीने बाद इंदिरा जी के यहां से चंद्रशेखर के पास पटियाला जेल में दूत भेजे गए। चंद्रशेखर से जेल में आकर मिले। उनकी 'जेल डायरी' में यह दर्ज है। एक दिन पहले अधिकारियों ने बताया कि कोई मिलने आएगा। नाम नहीं बताया। अगले दिन जेल में चहल-पहल थी। दिल्ली से दूत आया। चंद्रशेखर ने जलपान के बाद बात शुरू की। कलेक्टर ने एकांत की व्यवस्था की। पर, चंद्रशेखर ने कहा, 'कोई जरूरत नहीं। हम टहलते हुए बात करेंगे।' दूत ने संदेश दिया। मैडम गांधी, कम्युनिस्टों से परेशान थीं। कुछ नया करना चाहती थीं। चंद्रशेखर का सहयोग चाहती थीं। जवाब में चंद्रशेखर ने दो टूक कहा, 'मैं कम्युनिस्ट विरोधी नहीं हूं। मतभेद हैं, पर उनकी मदद नहीं कर सकता।' दूत ने पूछा, 'फिर जेल से आपकी रिहाई का क्या होगा?' चंद्रशेखर का जवाब था, मैं पूरी जिंदगी जेल में काटने को तैयार हूं।

कुलदीप नैयर की आत्मकथा में भी यह प्रसंग है। जेल से छूटने के कुछ महीनों बाद नैयर, कमलनाथ से मिलने गये। तब कमलनाथ, 'इंडियन एक्सप्रेस' बोर्ड में रखे गए थे। आपातकाल में। वह, संजय गांधी के अत्यंत विश्वस्त थे। नैयर की कमलनाथ से मुलाकात हुई। 1976 के अंतिम दौर में। पूछा कब चुनाव कराने जा रहे हैं? कमलनाथ ने बताया कि चंद्रशेखर से बात करने के लिए दूत भेजा गया है। 'मैडम गांधी' के करीबी। वह कई बार चंद्रशेखर से मिले। पर, चंद्रशेखर अपने जवाब पर अडिग।

कुछ महीनों बाद चंद्रशेखर दिल्ली लाए गए। नजरबंद कर के। अभी जेल से रिहाई नहीं हुई थी। तबतक अधिकतर नेता, जेल से रिहा हो चुके थे। फिर दिल्ली में जसवंत मेहता (गुजरात के गृहमंत्री) श्रीमती गांधी के दूत बन कर मिले। चार बार। एक बार मैडम गांधी से मिल, तो लीजिए। इंदिरा गांधी मिलना चाहती थीं। इस सिलसिले में चंद्रशेखर अपनी डायरी (04 जनवरी, 1977) में लिखते हैं, 'यदि मुझे प्रधानमंत्री से कोई बात करनी होगी, तो जेल से बाहर होने के बाद ही करूंगा। मैं इतना अवश्य पूछना चाहता हूं कि यह सब रोष किस बात पर?' उनकी यह स्पष्टता उनकी वैचारिक दृढ़ता को दिखाती है।

चंद्रशेखर जेल की तन्हाई में क्या सोचते थे, इसकी झलक (14 मार्च, 1976) को मिलती है। 'आज यह सोचता रहा कि मैंने क्या खोया और क्या पाया? यदि जो हो रहा है, उसको समर्थन देता, तो आत्मग्लानि के अतिरिक्त और क्या मिलना था। यदि उससे बचना था, तो आज जिस स्थिति में हूं, उससे अधिक सम्मानजनक और क्या हो सकता था? पर, चंद्रशेखर को जेल क्यों हुआ? वह अपनी गिरफ्तारी का कारण भी बताते (13 मार्च, 1976) हैं, 'सही बात तो यह है कि मैंने उस वक्तव्य में अपना नाम जोड़ना स्वीकार नहीं किया, जिसमें कांग्रेस के सम्मानित सदस्यों ने कहा था कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व के अतिरिक्त भारत के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है।' चंद्रशेखर ने इसे स्वीकार नहीं किया। आगे वह लिखते हैं, 'अगर मैं वह सब करता, तो आज जो कर रहा हूं, वह कैसे संभव होता?' उनके मित्रों ने बार-बार आग्रह किया कि वह, इंदिरा जी से मिल लें। उनके ऊपर दबाव बनाए जा रहे थे। पर, वह नहीं मिलें। उन्होंने इसका कारण अपनी जेल डायरी में बताया (13 मार्च, 1976) है, 'यदि मैं उनसे मिल लेता और समर्थन में सब कुछ करने को तैयार हो जाता, तो मैं भी समाजवादी और देशभक्त कांग्रेसियों की श्रेणी में सम्मिलित हो जाता। ऐसा नहीं किया तो अब प्रतिक्रियावादी और राष्ट्रद्रोही लोगों के साथ जोड़ दिया गया। यदि उस समय मैं किसी दबाव या कमजोरी में वह सब कर भी देता, तो आज जो हो रहा है, उसे कर पाना कहाँ तक संभव था?'

चंद्रशेखर ने ताउम्र सिद्धांतों, विचारों व मूल्यों की राजनीति की। आपातकाल में उन्होंने आत्मसम्मान चुना। जेल की तन्हाई को गले लगाया। प्रलोभनों को ठुकराया। उनकी डायरी उनकी वैचारिक दृढ़ता का आईना है। वह लिखते हैं, 'राजनीतिक विवाद चलेगा। लेकिन कीचड़ उछालने से क्या लाभ? जेल ने मुझे सोचने का अवसर दिया।

मध्यस्थता के श्रेय पर विवाद

कल्याणी शंकर
(लेखिका, वरिष्ठ पत्रकार हैं)

भारत-पाकिस्तान युद्धविराम में अमेरिका की संलिप्तता विवादास्पद है। यह ट्रंप के बड़बोले बयानों तथा भारत द्वारा ऐतिहासिक रूप से बाहरी मध्यस्थता अस्वीकार करने के बीच फंसी है। पिछले महीने पहलगाम में भयानक आतंकी नरसंहार के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में युद्धविराम कराने में संयुक्त राज्य अमेरिका की भूमिका लगातार चर्चा में बनी हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि 'मैंने युद्ध रुकवाया'। उनका कहना था कि उन्होंने यह कदम दोनों देशों की नाभिकीय क्षमताओं और उनके बीच युद्ध का विस्तार होने पर नाभिकीय युद्ध छिड़ने की आशंका से उठाया था। इसके उलट भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जोर दिया कि भारत ने कभी युद्धविराम करवाने में बाहरी सहायता की मांग नहीं की। उन्होंने जोर देकर कहा कि युद्धविराम भारतीय और पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों के बीच सीधी बातचीत का परिणाम था। उल्लेखनीय है कि भारत ने पहलगाम नरसंहार के बाद 'आपरेशन सिंदूर' शुरू कर पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को नष्ट किया तथा पाकिस्तान की सैनिक प्रतिक्रिया के जवाब में उसके कई सैनिक ठिकानों को निशाना बना कर उसे केवल 22 घंटों में ही घुटनों पर ला दिया। इससे पाकिस्तान ने युद्धविराम की प्रार्थना की और भारत ने उसे स्वीकार कर लिया। हालिया महीनों में राष्ट्रपति ट्रंप तथा प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इन बयानों पर पुनः जोर दिया है। इसके परिणामस्वरूप यह व्याख्या का सवाल बन गया है कि कौन सही बात कह रहा है क्योंकि दोनों पक्षों ने अपने दावों के समर्थन में अनेक प्रमाण दिए हैं। इसे देखते हुए तीसरे पक्ष की मध्यस्थता से इनकार करने वाले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बयान के बावजूद असहमति बनी हुई है। ट्रंप लगातार इस बात की पैरवी कर रहे हैं कि भारत-पाकिस्तान के बीच युद्धविराम में संयुक्त राज्य अमेरिका की भूमिका है। इस सप्ताह मोदी ने ट्रंप से फोन वार्ता के दौरान जोर दिया कि युद्धविराम दोनों देशों की सेनाओं के बीच चर्चा का परिणाम था और इसमें अमेरिकी मध्यस्थता की कोई भूमिका नहीं थी। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने एक प्रेस वक्तव्य में ट्रंप-मोदी फोन वार्ता के बारे में जानकारी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों की प्रशंसा की कि वे युद्धविराम पर सहमत हुए। इस सारे प्रकरण को देखते हुए अमेरिका की संलिप्तता अनिश्चितता के दायरे में आती है। ट्रंप की घोषणा के लगभग तीस मिनट बाद भारत के विदेश सचिव ने बताया कि पाकिस्तान के सैनिक कार्रवाई महानिदेशक ने अपने भारतीय समकक्ष से संपर्क किया था। वे सभी फायरिंग तथा सैनिक कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए, पर खासतौर से इसमें अमेरिका का कोई उल्लेख नहीं था। इस बीच पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ़ ने उनके नेतृत्व तथा युद्धविराम में सुविधा प्रदान करने के लिए ट्रंप का आभार व्यक्त किया। इस सप्ताह पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्डमार्शल आसिम मुनीर के साथ व्हाइट हाउस में लंच आयोजित करते हुए ट्रंप ने फिर दावा किया कि यह लंच 'उनको युद्ध जारी न रखने के लिए धन्यवाद' के रूप में था और इसमें उनके देश के साथ संभावित अमेरिकी व्यापार समझौते पर चर्चा की गई थी। उन्होंने यह दावा भी किया कि उन्होंने व्यापार समझौते का प्रयोग भारतीय उप-महाद्वीप में संभावित नाभिकीय टकराव रोकने के लिए किया था। ट्रंप ने पिछले महीने रिपोर्टरों को बताया था, 'मैंने कहा कि आओ हम तुम्हारे साथ काफी व्यापार करने जा रहे हैं। इसे रोको। इसे रोको। यदि तुम इसे रोकते हो तो हम व्यापार करेंगे। यदि तुम इसे नहीं रोकते हो तो हम कोई व्यापार नहीं करेंगे।' इस प्रकार ट्रंप ने दोनों पक्षों को एक 'गाजर' दिखाई थी। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने जनरल मुनीर के साथ बैठक से क्या हासिल किया तो उनका जवाब था, 'जनरल मुनीर पाकिस्तानी पक्ष से टकराव रोकने में अत्यधिक प्रभावशाली थे, जबकि मोदी ने इसे भारतीय पक्ष की ओर से रोका।'

इस प्रकार तटस्थ दृष्टिकोण से देखने से स्पष्ट होता है कि व्हाइट हाउस में जनरल मुनीर को लंच देने के बहाने हुई बैठक ने अमेरिका-पाकिस्तान संबंधों को काफी गति दी है। डोनाल्ड ट्रंप और उनके पूर्ववर्ती अमेरिकन राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल में अमेरिका-पाकिस्तान संबंधों को काफी धक्का लगा था। अमेरिकी प्रशासन इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए भारत को अपने पक्ष में रखना चाहते थे। आश्चर्यजनक रूप से पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने व्हाइट हाउस में अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच करने के बाद ट्रंप को दोनों देशों के बीच युद्धविराम कराने और शांति स्थापित करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार देने का नामांकन का प्रस्ताव किया। बाद में पाकिस्तान ने आधिकारिक रूप से इस बारे में नोबेल पुरस्कार देने वाली समिति को पत्र भी लिखा। शनिवार सवेरे ट्रंप द्वारा युद्धविराम घोषणा करने के थोड़ी देर बाद अमेरिकी विदेश सचिव माइक पोंपियो ने संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा मध्यस्थता प्रयासों के विस्तृत विवरण साझा किए। उन्होंने ट्वीट किया कि वे भारत और पाकिस्तान के वरिष्ठ अधिकारियों के संपर्क में थे जिनमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी शामिल थे। उन्होंने घोषणा की कि दोनों सरकारों ने तत्काल युद्धविराम पर सहमति जताई और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तटस्थ स्थल पर सहमति जताई। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर मध्यस्थता का प्रस्ताव भारत के लिए बहुत संवेदनशील है। भारत ने पूरी स्पष्टता व कठोरता के साथ पड़ोसी देशों के साथ अपने विवादों में किसी तीसरे पक्ष की संलिप्तता से लंबे समय से इनकार किया है। उल्लेखनीय है कि ट्रंप ने पिछले राष्ट्रपति कार्यकाल में भी जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर दोनों देशों में मध्यस्थता का प्रस्ताव किया था जिसे नई दिल्ली ने अस्वीकार कर दिया था। नई दिल्ली को इस बात से परेशानी है कि ट्रंप के ट्वीट अक्सर भारत और पाकिस्तान को समान स्तर पर रख कर दोनों को जोड़ देते हैं। नई दिल्ली पश्चिमी देशों के नेताओं को भारत और पाकिस्तान की एकसाथ यात्रा के लिए भी हतोत्साहित करती रही है। नई दिल्ली किसी तीसरे पक्ष की सुविधा प्रदान करने वाली भूमिका से भी इनकार करती है क्योंकि उसके अपने पड़ोसी देशों व खासकर पाकिस्तान से विवादों के दीर्घकालीन ऐतिहासिक कारण हैं। भारत लंबे समय से भारत-पाकिस्तान संबंधों व खासकर जम्मू कश्मीर संबंधी मुद्दों पर बाहरी मध्यस्थता का विरोध करता रहा है। उसका यह विश्वास है कि इन संबंधों को केवल द्विपक्षीय वार्ताओं से सुलझाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा अन्य भाजपा नेताओं ने हाल में बार-बार दुहराया है कि अब पाकिस्तान से केवल पाक-अधिकृत कश्मीर से उसका अवैध कब्जा समाप्त करने पर ही बातचीत होगी। भारत ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने पर किसी वार्ता से इनकार किया है और राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने पिछले राष्ट्रपति कार्यकाल में इसे भारतीय संविधान के दायरे में उसके अधिकार के रूप में स्वीकार किया था।

इस बीच नई दिल्ली ने कनाडा में हालिया जी-7 सम्मेलन से काफी लाभ पाने का प्रयास किया है। इसमें जी-20 देशों का आह्वान किया गया था कि वे पाकिस्तान को हालिया टकराव के कारण अलग-थलग करें जो 10 मई को युद्धविराम के बाद समाप्त हो गया है। भारतीय अधिकारियों को राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा भारत और पाकिस्तान को संतुलित समर्थन देने से निराशा हुई। इसके साथ ही भारत को उम्मीद थी कि ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच कालगेरी में बैठक से अमेरिका के साथ व्यापार समझौते में सुविधा होगी।

आप की बात

अंध-विरोध की प्रवृत्ति

लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। लेकिन जब इसका उपयोग राजनीतिक स्वार्थ साधने और राष्ट्रहित को नुकसान पहुंचाने के लिए हो तो यह अराजकता बन जाती है। कांग्रेस सहित अनेक विपक्षी दल केंद्र सरकार के हर निर्णय का अंध-विरोध करने लगे हैंए चाहे वह निर्णय देशहित में ही क्यों न हो। विदेश नीति जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भी सस्ती राजनीति की प्रवृत्ति बढ़ी है। इससे न केवल देश की वैश्विक छवि को ठेस पहुंचती है, बल्कि पाकिस्तान जैसे शत्रु देश विपक्ष के बयानों को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत के खिलाफ हथियार बनाते हैं। आपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद विपक्ष को एकजुट होकर सरकार का समर्थन करना चाहिए था, लेकिन इसके स्वागत पर अनावश्यक बयानबाज़ी और अमेरिका को श्रेय दिए जाने पर विवाद से देश की स्थिति कमजोर दिखती है। पहलगाम जैसे आतंकी हमले के समय विपक्ष की सरकार के साथ खड़े होने की भावना हर समय बनी रहनी चाहिए। समय आ गया है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का दुरुपयोग रोकने के लिए सख्त कानूनी कदम उठाए जाएं। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि जो भी बोलें, तथ्यों के आधार पर बोलें और देशहित को सर्वोपरि रखें। आज़ादी के साथ जिम्मेदारी जरूरी है।

सुभाष बुड़ावन वाला, रतलाम

भारत का सांस्कृतिक नेतृत्व

वैश्विक मंच पर जहां शक्तिशाली राष्ट्र अपनी सैन्य शक्तिए बाजार और रणनीतिक गठबंधनों के सहारे दुनिया को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं भारत एक मौलिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण के साथ विश्व नेतृत्व की नई परिभाषा प्रस्तुत कर रहा है। यह नेतृत्व न केवल भौगोलिक सीमाओं से परे, बल्कि मानवीय मूल्यों, सभ्यता और करुणा पर आधारित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने जी-20 जैसे वैश्विक मंच को युद्ध और व्यापार की बहस से निकाल कर वसुधैव कुटुम्बकम के विचार तक पहुंचाया। यह भारत की गहरी सांस्कृतिक चेतना और सह-अस्तित्व की भावना का विस्तार है। आलोचक इसे राजनीतिक प्रचार कह सकते हैं, किंतु भारत की भूमिका अफ्रीका से लेकर यूरोप और एशिया तक स्पष्ट रूप से मानवीय सहायता और संकट प्रबंधन में दिखाई देती है। भारत ने कभी अपने सांस्कृतिक मूल्यों को सौदेबाजी का औजार नहीं बनाया। यह पश्चिम की वह प्रवृत्ति है जो लोकतंत्र और मानवाधिकार की बात कर युद्ध थोपती रही है। भारत का दृष्टिकोण सहयोग और संवाद का है, न कि वर्चस्व और लाभ का। विश्व को आज ऐसी शक्तियों की आवश्यकता हैए जो स्वार्थ के बजाय सबके कल्याण को प्राथमिकता दें।

– अवनीश कुमार गुप्ता, आजमगढ़

विवाह समारोह का विरोध

जेफ़ बेजोस और लॉरेन सांचेज़ के तीन दिवसीय वेनिस विवाह समारोह को लेकर इटली के लोग बहुत नाराज हैं। उन्हें तो खुश होना चाहिए की उनके देश, उनके शहर और उनके इलाके में दुनिया के नामी गिरामी लोग पधार रहे हैं। पिछले कई दिनों से इसके विरोध में लोग धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्हें ओवर-टूरिज्म, शहर की घटती आबादी और इस बात की चिंता है कि यह आयोजन धनी व्यक्तियों द्वारा वेनिस के शोषण का प्रतीक है। कार्यकर्ताओं का तर्क है कि 200 मेहमानों के आने की उम्मीद वाले भव्य विवाह समारोह ने पर्यटन से जुड़ी मौजूदा समस्याओं को और बढ़ा दिया है और स्थानीय निवासियों की जरूरतों की अनदेखी की जा रही है। वेनिस ओवर-टूरिज्म के प्रभावों से जूझ रहा है जिसमें सड़कों पर भीड़भाड़, सार्वजनिक सेवाओं पर दबाव और निवासियों के जीवन की गुणवत्ता में गिरावट शामिल है। प्रदर्शनकारी वेनिस को धनी व्यक्तियों के लिए एक शोकेस या स्टेज के रूप में पेश करने का विरोध कर रहे हैं। स्थानीय लोग शादी के कारण होने वाली रसद संबंधी व अन्य व्यवधानों के बारे में चिंतित हैं जिसमें सार्वजनिक स्थानों को बंद करना और आयोजन के लिए शहर के कुछ हिस्सों का निजीकरण करना शामिल है।

– जंग बहादुर सिंह, जमशेदपुर

ट्रंप की भूमिका

ईरान और इजरायल के बीच लंबे समय से चल रहे तनाव ने हाल के सप्ताहों में युद्ध का विकराल रूप धारण कर लिया था। इसने क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालने के साथ वैश्विक शांति और अर्थव्यवस्था पर भी गंभीर असर डालने की आशंका पैदा कर दी थी। तेल के दामों में उछाल, व्यापार मार्गों की असुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर असर ने पूरी दुनिया को चिंतित कर दिया था। ऐसे में अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने अप्रत्याशित भूमिका निभाई। उनकी मध्यस्थता से दोनों देशों के बीच सीजफायर पर सहमति बनी है। यह निस्संदेह पूरी मानवता के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। इस संघर्षविराम से उम्मीद जगी है कि कूटनीतिक प्रयासों और संवाद के जरिए जटिल समस्याओं का समाधान संभव है। युद्ध कभी भी किसी समस्या का स्थायी हल नहीं होता है। अब आवश्यकता इस बात की है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय इस शांति प्रयास को आगे बढ़ाए और स्थायी समाधान की दिशा में ठोस पहल करे। इस संघर्ष से सबक लेना जरूरी है कि समय रहते कूटनीतिक संवाद को प्राथमिकता दी जाए वरना पूरी दुनिया इसकी भारी कीमत चुका सकती है।

– विभूति बुपक्या, खाचरौद

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से responsemail.hindipioneer@gmail.com पर भी भेज सकते हैं।

दैनिक जागरण

स्वप्नों की पूर्ति के लिए प्रयास भी करने पड़ते हैं

आपातकाल के सबक

सत्ता और पद के मोह में इंदिरा गांधी की ओर से देश पर आपातकाल थोपने, विरोधियों के खिलाफ दमनचक्र चलाने और नौकरशाही को अपने हिसाब से काम करने के लिए विवश करने के घोर अलोकतांत्रिक फैसले के 50 वर्ष पूरे होने पर देश में विभिन्न आयोजन हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने भी आपातकाल के काले दिनों को याद किया। आज अनेक ऐसे नेता सक्रिय हैं, जिन्होंने 50 साल पहले आपातकाल के उत्पीड़न का सामना किया था। यह आश्चर्यजनक है कि आज कांग्रेस को आपातकाल के समय इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली केंद्रीय सत्ता एवं कांग्रेस की राज्य सरकारों के दमनकारी रवैये का स्मरण किया जाना सहन नहीं हो रहा है। आपातकाल को लेकर जो कुछ कहा गया, उसका जवाब देते हुए कांग्रेस ने यह समझाया कि मोदी का शासन अघोषित आपातकाल है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश की मानें तो आज लोकतंत्र पर पांच गुना अधिक हमले हो रहे हैं। क्या इंदिरा गांधी के आपातकाल पर उनके ऐसे ही विचार तब थे, जब वह कांग्रेस में नहीं थे? इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि अपने निर्वाचन पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रतिकूल फैसले और पीएम पद छोड़ने से बचने के लिए ही इंदिरा गांधी ने आपातकाल थोपकर भारतीय लोकतंत्र को शर्मसार किया था। आपातकाल की सजा उन्हें 1977 के आम चुनाव में भोगनी पड़ी। कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। सत्ता में आई जनता पार्टी का शासन अधिक नहीं चला और इंदिरा गांधी 1980 में फिर से सत्ता में आ गईं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आपातकाल को भुला दिया जाए।

आपातकाल में इंदिरा गांधी ने मनमाने तरीके से शासन करने के अलावा परिवारवाद को भी आगे बढ़ाया। दमनचक्र चलाने और न्यायपालिका पर दबाव बनाने में उनके बेटे संजय गांधी की विशेष भूमिका थी। वह तो संविधान बदलने का इरादा रखते थे। यह विडंबना ही है कि जिन नेताओं ने आपातकाल का डटकर विरोध किया, उनके वंशज और उनकी ओर से गठित कई दल आज कांग्रेस के साथ हैं। इस पर हैरानी नहीं कि इनमें से अधिकांश गांधी परिवार की तरह परिवारवाद की राजनीति को न केवल आगे बढ़ा रहे, बल्कि उसे सही भी ठहरा रहे हैं। इस पर आश्चर्य नहीं कि अपने विचित्र रवैये के कारण ही कांग्रेस उत्तर भारत में खास तौर पर कमजोर हो रही है। अपने पराभव के लिए वह स्वयं जिम्मेदार है, लेकिन भारतीय लोकतंत्र के लिए उसका कमजोर होना शुभ संकेत नहीं। वंशवादी गांधी परिवार पर आश्रित कांग्रेस शायद ही अपनी रीति-नीति सुधारे, पर उन प्रवृत्तियों से सभी को सावधान रहना चाहिए, जिनका परिचय आपातकाल में इंदिरा गांधी और उनके सहयोगियों ने दिया था। सभी को यह भी ध्यान रहे तो अच्छा कि अभी भारत को एक आदर्श लोकतांत्रिक देश बनना शेष है।

आचरण की शुचिता का प्रश्न

अभी बबीना के भाजपा विधायक राजीव सिंह पारीछा समर्थकों द्वारा वंदेभारत एक्सप्रेस में सीट को लेकर यात्री संग मारपीट का मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था कि उत्तर प्रदेश के एक अन्य विधायक समर्थकों का उत्पात सामने आ गया। बांदा के भाजपा विधायक प्रकाश द्विवेदी से जुड़े लोगों ने उनकी उपस्थिति में एसडीएम के चालक से मारपीट की है। प्रकरण यह है कि बांदा के पैगंबरपुर के पास ओवरलोडेड ट्रकों और डंपरों आदि की जांच कर रहे एसडीएम और विधायक के बीच तीखी नोकझोंक हुई। विधायक समर्थकों ने एसडीएम को घेरते हुए चालक के साथ मारपीट की। विवाद की वजह ओवरलोडेड मौरंग लदे ट्रक छुड़ाने को बताया जा रहा है। यह अनैतिक कदम है। अच्छी बात है कि पार्टी ने बबीना विधायक से आरोपों पर उनका स्पष्टीकरण मांगा है। यह जताया है कि इंटरनेट मीडिया एवं अन्य स्रोतों पर फैली सूचना से पार्टी की छवि आहत हुई है। ट्रेन के सफर में किसी प्रकार का विवाद उभरा भी था तो विधायक, समर्थकों को जुटाने की जगह रेल प्रशासन से शिकायत करते। आचरण की शुचिता सार्वजनिक जीवन में महत्वपूर्ण है। जो जनप्रतिनिधि हैं वे पार्टी और समाज के "सत्यं-शिवं-सुंदरम्" के प्रति भी उत्तरदायी हैं। अपने आचरण से वे कौन सा उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। पार्टी और प्रशासन दोनों स्तर से जांच और दोषी होने पर संदेशात्मक कार्रवाई भी जरूर हो।

> जो जनप्रतिनिधि हैं उनको पार्टी और समाज के "सत्यं-शिवं-सुंदरम्" के प्रति भी उत्तरदायी होना चाहिए

ट्रंप से अब और सावधान हो जाए भारत

दिव्य कुमार सोती

इजरायल-ईरान युद्ध के समय ट्रंप के आसिम मुनीर से मिलने और फिर इस युद्ध में कूदने के कारण भारत की चिंता बढ़नी चाहिए

अवधेश राजपूत

कुछ दिनों के भीषण युद्ध के बाद इजरायल और ईरान के बीच संघर्ष विराम हो गया। कहना मुश्किल है कि यह संघर्ष विराम कितने समय तक टिकेगा? ईरान पर हमला बोलते समय इजरायल ने यह कहा था कि उसका उद्देश्य ईरानी परमाणु कार्यक्रम को समाप्त करना है। उसे कुछ आरंभिक सफलता भी हासिल हुई। उसके अचानक हमले में ईरान के कई शीर्ष सैन्य कमांडर और परमाणु विज्ञानी मारे गए। शुरुआती सफलता के बीच इजरायल ने कहना शुरू कर दिया कि हमले के पीछे उसके उद्देश्य बड़े हैं और एक उद्देश्य ईरान में सत्ता परिवर्तन का भी है। ईरान की सत्ता उन कट्टर मजहबी नेताओं के कब्जे में है, जो हमास-हिजबुल्ला का साथ देते हैं। इजरायल के समर्थन में अमेरिका के कई ताकतवर नवरूढ़िवादी सांसदों की आवाज भी उठने लगी। शुरुआत में अमेरिका इस लड़ाई में कूदने से हिचक रहा था, पर ईरान की जवाबी कार्रवाई से घिरे इजरायल की मदद के लिए आखिरकार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी वायु सेना को ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले के आदेश देने ही पड़े। इसके बावजूद ईरानी परमाणु कार्यक्रम के पूरी तरह ध्वस्त होने को लेकर संदेह है। वैसे भी ईरान की मिसाइल क्षमता आशा से कहीं अधिक निकली। युद्ध लंबा खिंचने पर इजरायल में कहीं अधिक बर्बादी हो सकती थी। इसी कारण ट्रंप ने आनन-फानन युद्ध विराम का एलान भी कर दिया और वह भी अपने व्यापक लक्ष्यों की पूर्ति के बिना, क्योंकि न तो ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह नष्ट हो पाया और न ही वहां सत्ता परिवर्तन के कोई आसार दिख रहे। हालांकि इसका यह अर्थ नहीं कि इजरायल और ट्रंप के मागा (मेक अमेरिका ग्रेट अगेन) खेमे ने यह योजना सदा के लिए छोड़ दी है। सही मौका देखकर इसे फिर से क्रियान्वित करने का प्रयास होगा।

वैसे तो अमेरिका को 'फिर से महान बनाने के अभियान' में लगे ट्रंप ईरान में सत्ता परिवर्तन के लिए किसी युद्ध में नहीं उलझना चाहते, परंतु उसके इरादों को देखते हुए भारत को सतर्क होना होगा। भारत को सामरिक दृष्टिकोण से भी इस युद्ध के निहितार्थ समझने की जरूरत है। इजरायल-ईरान युद्ध के दौरान व्हाइट हाउस में ट्रंप की ओर पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर की आवभगत का एक गहरा अर्थ है। जब मुनीर व्हाइट हाउस में थे, उसी समय अमेरिकी मदद से सत्तासीन बांग्लादेश की भारत विरोधी मोहम्मद यूनुस सरकार के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी वाशिंगटन में अमेरिकी अधिकारियों से मिल रहे थे। दरअसल ट्रंप की मागा योजना के अंतर्गत अमेरिका का नए सिरे से जो उद्योगीकरण प्रस्तावित है, वह बिना चीन और रूस के पर कतरे और भारत को तंग किए बिना संभव नहीं है। इस योजना को सिरे चढ़ाना उतना आसान नहीं है, क्योंकि भूमंडलीकरण के नाम पर अमेरिका ने ही अधिक मुनाफा कमाने के फेर में अपनी कंपनियों को चीन, वियतनाम जैसे देशों में स्थापित कराया। अब जब तक इन देशों में अमेरिकी कंपनियों के लिए उत्पादन के मोर्चे पर चुनौतियां नहीं दिखतीं, तब तक उनकी स्वदेश वापसी मुश्किल है। फिर भी अपनी योजना को लेकर अमेरिकी नवरूढ़िवादियों और ट्रंप के कथित युद्धविरोधी मागा खेमे में एक राय है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए दो तरीके चुने गए हैं।

पहला तरीका है ट्रेड और टैरिफ नीति के जरिये रूस, चीन के साथ-साथ भारत का भी आर्थिक संकट बढ़ाना। दूसरा तरीका है कट्टरपंथी इस्लामिक शक्तियों का अपने हित में इस्तेमाल करना। ट्रंप के चीनी वस्तुओं पर लगाए गए भारी टैरिफ के चलते चीन का अमेरिका को निर्यात काफी घटा है। यदि यह सिलसिला लंबे समय तक चला और चीन ने अपने निर्यात के लिए नए बाजार नहीं तलाशे तो वहां बड़ा औद्योगिक और सामाजिक संकट खड़ा हो सकता है। भारत चीन के विरुद्ध एक तरह से अमेरिका का सामरिक साझेदार है, पर ट्रंप मात्र इतने से संतुष्ट नहीं। उन्हें भारत के रूप में एक लोकतांत्रिक मित्र राष्ट्र नहीं, बल्कि उनके हिसाब से चलने वाला देश चाहिए। भारत के अमेरिका के बताए रास्ते पर चलने से इन्कार करने के बाद अब यह अमेरिका के एजेंडे में नहीं दिखता कि उसकी मदद से भारत चीन जैसी आर्थिक शक्ति बनकर खड़ा हो। यह अच्छा हुआ कि भारत ने साफ कर दिया कि उसे अमेरिका से व्यापार समझौते की जल्दी नहीं।

ट्रंप ने हाल में यह भी कहा था कि भारत एक बड़ा देश है और वह अपने मसले खुद देख लेगा। ध्यान रहे एक अमेरिकी सीनेटर रूसी तेल खरीदने के चलते भारत पर 500 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने की वकालत कर चुके हैं। पाकिस्तान को शह देते ट्रंप भी भारत-पाकिस्तान सीजफायर के मुद्दे को भी जब तब व्यापार से जोड़ते रहते हैं। इसके पीछे उनका भारत के लिए यही संदेश है कि अगर टैरिफ जैसे मुद्दों पर भारत ने अमेरिका की बात नहीं मानी तो उसे पाकिस्तान के मोर्चे पर और दिक्कतें झेलनी पड़ेंगी। यदि बांग्लादेश में भी अमेरिका लगातार इस्लामिक कट्टरपंथियों को बढ़ावा दे रहा है तो भारत को परेशान करने के लिए ही। इन परिस्थितियों में रूसी विदेश मंत्री द्वारा प्रस्तावित रूस, चीन और भारत का त्रिकोण अब प्रासंगिक लगता है। चीन भी अब इसे लेकर सजग हो रहा है। भारत और चीन के रिश्तों में बर्फ पिघलती देखी जा सकती है। हाल में शंघाई सहयोग संगठन के मंच पर भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी की मुलाकात के बाद आए चीनी विदेश मंत्रालय के बयान में उल्लेख हुआ कि दोनों देश एक-दूसरे के प्रतिद्वंद्वी न होकर साझेदार हैं। जहां अमेरिकी टैरिफ के चलते चीन को एक बड़े बाजार की आवश्यकता है, वहीं भारत को त्वरित औद्योगिक विकास के लिए सस्ते कलपुर्जों की। दोनों देश एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। इसके बावजूद भारत को अपने सुरक्षा हितों के मामले में चीन को लेकर निरंतर सजग रहते हुए आगे बढ़ना होगा, क्योंकि सीमा विवाद जैसे मुद्दों पर पूर्व में चीन से बार-बार धोखा मिल चुका है। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि चीन के साथ आर्थिक साझेदारी भारत के औद्योगिक विकास में सहायक हो और वह चीन पर निर्भरता का कारण न बने।

(लेखक काउंसिल आफ स्ट्रैटेजिक अफेयर्स से संबद्ध सामरिक विश्लेषक हैं)
response@jagran.com

उच्च शिक्षा में कुछ अच्छा होता हुआ

प्रणय कुमार

क्यूएस जैसी रैंकिंग्स को हमें लक्ष्य नहीं, दर्पण की तरह देखना चाहिए और अन्य शिक्षा संस्थानों पर भी ध्यान देना चाहिए

नवाचार को प्रोत्साहन से मिलते अच्छे परिणाम। फाइल

ईरान-इजरायल युद्ध के बीच शिक्षा क्षेत्र में भारत की एक उपलब्धि दबकर सी रह गई। क्यूएस (क्वाक्वेरेली साइमंड्स) वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग-2026 में भारत ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। इस वर्ष इसमें 106 देशों के कुल 1,501 शिक्षा संस्थानों को स्थान मिला, जिनमें 112 संस्थान पहली बार सम्मिलित हुए हैं। भारत के 54 संस्थानों को इस प्रतिष्ठित सूची में स्थान मिला, जो अब तक का रिकार्ड है। यह संख्या भारत को न केवल जर्मनी (48) और जापान (47) जैसे देशों से आगे ले जाती है, बल्कि इसे अमेरिका, ब्रिटेन और चीन के बाद चौथा सर्वाधिक प्रतिनिधित्व वाला देश भी बना देती है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2014 में भारत के केवल 11 संस्थान इस सूची में थे। यानी पिछले एक दशक में भारत ने लगभग पांच गुना वृद्धि दर्ज की है। इस वृद्धि में न केवल कई आइआइटी, भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु, दिल्ली विश्वविद्यालय, अन्ना विश्वविद्यालय, जेएनयू जैसे पारंपरिक एवं सरकारी संस्थानों-विश्वविद्यालयों ने योगदान दिया है, बल्कि कई निजी विश्वविद्यालयों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। आठ भारतीय शिक्षा संस्थान पहली बार इस सूची में शामिल हुए हैं। यह भारतीय उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बढ़ती भागीदारी का एक संकेत भी है। इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का यह वक्तव्य प्रासंगिक प्रतीत होता है, 'क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स हमारी शिक्षा व्यवस्था के लिए शानदार खबर लेकर आई है। हमारी सरकार भारत के युवाओं के लाभ के लिए शोध और नवाचार के इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।'

क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग उच्च शिक्षा की दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित और व्यापक रूप से संदर्भित रैंकिंग्स में से एक मानी जाती है। इसके अंतर्गत शिक्षा संस्थानों का मूल्यांकन नौ संकेतकों के आधार पर किया जाता है, जिनमें शैक्षणिक प्रतिष्ठा, नियोक्ता प्रतिष्ठा, फैकल्टी-छात्र अनुपात, छात्र अनुपात, रोजगार परिणाम, अंतरराष्ट्रीय शोध नेटवर्क जैसे मानक शामिल हैं। उच्च शिक्षा में हुए हालिया सुधारों के पीछे कई महत्वपूर्ण कदम रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की संस्तुतियों का व्यवस्थित क्रियान्वयन, शोध, अनुसंधान और नवाचार को निरंतर प्रोत्साहन तथा वैश्विक साझेदारियों और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने की दिशा में गंभीर पहल की गई है। साथ ही हर स्तर पर तकनीकी दक्षता और व्यावसायिक कौशल को बढ़ावा दिया गया है। शिक्षा और उद्योग जगत के बीच की खाई पाटने, प्रवेश, फैकल्टी और विषय चयन की प्रक्रिया को अधिक लचीला बनाने, विश्वविद्यालय परिसरों में विविधता और समावेशन की भावना को प्रोत्साहित करने और रोजगारोन्मुखी शिक्षा को सुदृढ़ करने जैसे कई निर्णायक कदम उठाए गए हैं।

शिक्षा के मोर्चे पर हो रहे व्यापक प्रयासों का ही परिणाम है कि आज भारत के आठ संस्थान प्रति फैकल्टी उद्धरण श्रेणी में विश्व के शीर्ष 100 संस्थानों में शामिल हो चुके हैं। इस मानदंड पर भारत ने अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों को भी पीछे छोड़ दिया है। इसी प्रकार नियोक्ता प्रतिष्ठा के मापदंड पर हमारे पांच विश्वविद्यालय वैश्विक शीर्ष 100 में स्थान पाने में सफल हुए हैं, जो उद्योग जगत में भारतीय स्नातकों के प्रति बढ़ते भरोसे का संकेत है।

शैक्षणिक प्रतिष्ठा के क्षेत्र में भी आइआइटी, दिल्ली, बंबई और मद्रास जैसे संस्थानों ने अपनी फैकल्टी और वैश्विक शैक्षणिक साझेदारियों के चलते उच्च रेटिंग अर्जित की है। हालांकि इसी वर्ष जोड़े गए अंतरराष्ट्रीय छात्र विविधता जैसे संकेतकों में भारतीय विश्वविद्यालयों-संस्थानों को अपेक्षित रैंक नहीं मिली, जिसका समग्र रैंकिंग पर भी कुछ प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। स्पष्ट है कि उच्च शिक्षा पर और अधिक ध्यान देना होगा और इसकी कोशिश करनी होगी कि अन्य शिक्षा संस्थानों और विशेष रूप से राज्य विश्वविद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधरे।

क्यूएस या अन्य किसी भी वैश्विक रेटिंग एजेंसी को भी यह समझना होगा कि देश विशेष की परिस्थितियां भिन्न-भिन्न होती हैं। भारत जैसे देश की तुलना पश्चिमी देशों से नहीं हो सकती। भारत में इतनी विविधता है कि हमारे विश्वविद्यालय एवं अन्य शिक्षा संस्थान विविधता के उत्सव-स्थल हैं। निःसंदेह यह उपलब्धि प्रेरणास्पद है, परंतु हमें यह भी स्वीकारना होगा कि यह सफलता अभी मुख्यतः आइआइटी, कतिपय केंद्रीय विश्वविद्यालयों और चुनिंदा संस्थानों तक ही सीमित है। देश के अधिकांश विश्वविद्यालय अभी भी सीमित फंडिंग, कमतर शोध उत्पादन, सुयोग्य अध्यापकों की कमी, अधुनातन प्रयोगशालाओं की अनुपलब्धता, नवाचार के प्रति उदासीनता, अल्प अंतरराष्ट्रीय सहयोग एवं साझेदारी जैसी चुनौतियों से जूझ रहे हैं। वस्तुतः क्यूएस या किसी भी रैंकिंग्स को हमें लक्ष्य नहीं, दर्पण की तरह देखना चाहिए, जो हमें आत्मनिरीक्षण का भी संदेश देता है। वास्तविक उत्कृष्टता तो रैंकिंग्स से परे जाकर भारत के स्व को विस्मृत किए बिना शिक्षा का वैश्विक प्रतिमान गढ़ने एवं माडल खड़ा करने में है।

(लेखक शिक्षाविद् हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

श्रेष्ठ आचरण

धर्म का सार तत्व यही है कि जो आपको बुरा लगता है वह काम आप दूसरों के लिए भी न करें। वेदों की ऋचाएं, पौराणिक आख्यान, शास्त्रीय ग्रंथों का संदेश है कि मन भर ज्ञान से तोला भर आचरण श्रेष्ठ होता है। हालांकि यह भाव भी पारिवारिक संस्कारों तथा आसपास के परिवेश पर निर्भर है। प्रायः घरों में माता-पिता दैनिक जीवन में झूठ, छल-प्रपंच का उपयोग अपने हित-साधन के लिए करते हैं। घर के छोटे लोग न चाहते हुए भी उन्हीं तौर-तरीकों को अपनाने लगते हैं।

अपने हित के लिए बोले गए एक असत्य-वचन से कई दिनों की पूजा-उपासना, यज्ञ-अनुष्ठान के लाभ उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं, जैसे बड़े परिश्रम से घड़े में एकत्र किए गए जल में कोई एक छेद कर दे तो पूरा जल बह जाता है। हम मंदिरों में जाते हैं। वहां प्रसाद मिलता है। बड़े जतन से उसे घर लाते हैं। इस उद्देश्य से सबको देते हैं कि उससे ईश्वरीय अनुकंपा मिलेगी, पर सदाचार, सुसंस्कारों की बातें पढ़कर और सुनकर हम उन्हें ऐसे नजरअंदाज कर देते हैं कि जैसे ये सब हमारे लिए नहीं, औरों के लिए हैं। प्रायः लोग जीवन और समय को कोसते नजर आते हैं। भगवान को दोष देते दिखते हैं। जबकि हम और हमारे लोग सुखी, तो यह हमारी विधिक जीवनशैली और दुखी हैं, तो वह भी हम हमारी गलत जीवनशैली की देन है। सुख है तो वह भी हमारा और दुख है तो वह भी हमारा ही अर्जित किया हुआ है। सदाचार का जीवन जिएंगे तो सम्मानित और धोखा, झूठ-फरेब का रास्ता अपनाएंगे तो अपमानित होना ही पड़ेगा। बबूल का पेड़ लगाएंगे तो उससे कांटे ही मिलेंगे, आम नहीं। ठगी और तीन-तिकड़म की आयु लंबी नहीं होती। उसे एक न एक दिन परास्त होना पड़ता है। नकारात्मक जीवन जीने वाले व्यक्ति को जो पीड़ा होती है, उसे वही जान सकता है।

सलिल पांडेय

पारिस्थितिकी तंत्र को नया जीवन

रंजना मिश्रा

> ग्रीन इंडिया मिशन न केवल हमारे जंगलों को जीवनदान देगा, बल्कि हमारी हवा को स्वच्छ करेगा, पानी को भी संरक्षित करेगा

केंद्र सरकार ने अपने एक दशक पुराने 'ग्रीन इंडिया मिशन' को संशोधित करते हुए इसका दूसरा संस्करण जारी किया है। यह केवल पेड़ गिनने की पुरानी परिपाटी से आगे बढ़कर देश के संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्रों को समग्र रूप से पुनर्जीवित करने का एक महत्वाकांक्षी खाका प्रस्तुत करता है। वर्ष 2014 में जब ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत हुई थी, तब इसका मुख्य उद्देश्य वन आवरण को बढ़ाना और उसकी गुणवत्ता में सुधार करना था। अनुभव ने सिखाया कि भारत की भौगोलिक और पारिस्थितिकी विविधता में 'एक नीति सब पर लागू' का सिद्धांत पूरी तरह कारगर नहीं है। हिमालय की नाजुक ढलानों पर पेड़ लगाने की चुनौती, तटीय क्षेत्रों के मैंग्रोव वनों की जरूरतें और अरावली जैसी शुष्क पहाड़ियों को हरा-भरा करने की तकनीकें एक जैसी नहीं हो सकतीं। इसके अलावा भारत ने 2030 तक 2.6 करोड़ हेक्टेयर बंजर भूमि को पुनर्स्थापित करने और 2.5 से तीन अरब टन कार्बन डाइआक्साइड के बराबर अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाने का जो अंतरराष्ट्रीय लक्ष्य तय किया है, उसे पाने के लिए एक अधिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण की तत्काल आवश्यकता थी।

अब ध्यान केवल पौधों की संख्या पर नहीं, बल्कि पूरे इकोसिस्टम के स्वास्थ्य पर होगा। इसके तहत चार प्रमुख संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष बल दिया गया है। अरावली पर्वतमाला, जिसे मरुस्थलीकरण के खिलाफ भारत की 'हरी दीवार' माना जाता है, यहां केवल पौधारोपण नहीं होगा, बल्कि जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण, स्थानीय कंटीली झाड़ियों और घास का विकास तथा मिट्टी की नमी को लौटाने पर काम किया जाएगा। पश्चिमी घाट, जैव-विविधता के इस हाटस्पाट में खनन, अतिक्रमण और अनियंत्रित विकास से बिगड़े पारिस्थितिकी संतुलन को बहाल करना प्राथमिकता होगी। हिमालयी क्षेत्र में ढलानों को स्थिर करने वाले पौधों और घासों को लगाने पर जोर दिया जाएगा। तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा करने वाले और सुनामी जैसी आपदाओं में ढाल का काम करने वाले मैंग्रोव वनों का संरक्षण और विस्तार हरित भारत मिशन 2.0 का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। सरकार का मानना है कि यह मिशन बिना जन-भागीदारी के सफल नहीं हो सकता। इसलिए संयुक्त वन प्रबंधन समितियों और स्थानीय ग्राम सभाओं को पहले से अधिक अधिकार और संसाधन दिए जाएंगे। योजना के तहत स्थानीय युवाओं को 'वन-प्रहरी' या 'पारिस्थितिकी-योद्धा' के रूप में प्रशिक्षित कर रोजगार के अवसर भी पैदा किए जाएंगे।

बेशक यह संशोधित मिशन आशाजनक है, लेकिन राज्यों और केंद्र के बीच बेहतर समन्वय, धन का समय पर आवंटन, लगाए गए पौधों की उच्च जीवन-दर सुनिश्चित करना और वन भूमि पर बढ़ते अतिक्रमण और अवैध कटाई को रोकना सबसे बड़ी चुनौतियां होंगी।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

स्थिर विदेश नीति पर जोर

'आपसी बैर बढ़ाने वाली राजनीति' शीर्षक से लिखे आलेख में राजीव सचान ने स्पष्ट किया है कि विदेश नीति का संबंध किसी विशेष राजनीतिक दल से नहीं, बल्कि देश के हित से होता है। हमारे देश में विदेश नीति पर राजनीति की पुरानी परंपरा रही है। उदाहरण के लिए, भाजपा और अन्य दलों ने विपक्ष में रहते हुए परमाणु उत्तरदायित्व विधेयक के कुछ प्रविधानों का विरोध किया था। इसके परिणामस्वरूप, संशोधन के कारण विदेशी कंपनियों ने भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्र में निवेश करने में रुचि नहीं दिखाई। अब भाजपा की केंद्र सरकार इस कानून में संशोधन करना चाहती है, जिसके चलते कांग्रेस भाजपा पर यू-टर्न का आरोप लगा रही है। इस संदर्भ में यह आवश्यक है कि विदेश नीति के मामलों में सदैव एक राय बने। इजरायल और ईरान जैसे देश भारत के करीबी मित्र हैं और दोनों से हमारे रिश्ते देश के हित में हैं। ऐसे में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के अनुरूप भारत खुलकर ईरान का समर्थन नहीं कर सकता। अस्थिरता भरे माहौल में किसी का खुलकर समर्थन करना विदेश नीति के लिहाज से उचित नहीं है। इससे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर देश का हित प्रभावित होता है। भारत एक जिम्मेदार राष्ट्र है। रूस-यूक्रेन, इजरायल-हमास, आपरेशन सिंदूर और ईरान-इजरायल संघर्ष में स्थिर नीति अपनाने के कारण हमारा मान बढ़ा है। यह स्थिर नीति केवल सरकार की नहीं, बल्कि देश की है। इसे सत्ता और विपक्ष दोनों को समझने की आवश्यकता है। यदि हम अपने देश के हितों की रक्षा करना चाहते हैं, तो हमें राजनीतिक मतभेदों को भुलाकर एकजुट होकर काम करना होगा। राजीव सचान का आलेख बताता है कि विदेश नीति को राजनीतिक विवादों से ऊपर उठाकर देखना चाहिए।

मुकेश कुमार मनन, पटना

भारत का अंतरिक्ष में बढ़ता परचम

भारत के लिए 25 जून, 2025 का दिन ऐतिहासिक बन गया, जब भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला एक्सिओम-4 मिशन के तहत अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की ओर रवाना हुए। 1984 में राकेश शर्मा के बाद यह पहली बार है जब कोई भारतीय अंतरिक्ष यात्री इस तरह के मिशन का हिस्सा बना है। शुभांशु का "मेरे कंधे पर तिरंगा है... जय हिंद, जय भारत" कहना हर भारतीय के दिल को गर्व से भर देता है। एक्सिओम-4 एक निजी अंतरिक्ष मिशन है, जो नासा और स्पेस एक्स के सहयोग से संचालित हो रहा है। इस मिशन की सफलता भारत के बढ़ते अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं को नई दिशा देती है। शुभांशु ने यह स्पष्ट किया कि यह मिशन केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि भारत के मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम की नई शुरुआत है। उनका संदेश प्रत्येक भारतीय में एक नई प्रेरणा और आत्मविश्वास भरता है। आज जब फिल्में बनाने में ही 10-10 करोड़ रुपये खर्च किए जाते हैं, तब देश के अंतरिक्ष मिशनों पर व्यय को लेकर आलोचना नहीं होनी चाहिए। यह निवेश भारत की वैज्ञानिक, तकनीकी और राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को अंतरिक्ष में मजबूत करता है। यह मिशन युवा पीढ़ी को विज्ञान और अंतरिक्ष क्षेत्र में करियर बनाने के लिए भी प्रेरित करेगा। यह मिशन साबित करता है कि अगर सही दिशा, संसाधन और संकल्प हो तो भारत की प्रतिभा अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा सकती है। अब वक्त है मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाकर इसे और ऊंचाई देने का।

ऋषि सुभाष वृंदावन वाला, रतलाम, मप्र

संस्कारों की जननी शिक्षा

एक अनपढ़ व्यक्ति भी संस्कारी व्यक्ति हो सकता है और अनेकों पढ़े-लिखे व्यक्ति संस्कारहीन देखे जाते हैं। शिक्षा से व्यक्ति डाक्टर, अध्यापक, इंजीनियर तो बन जाता है, पर धीर-वीर, कर्तव्य-परायण, धार्मिक, साहसी, सेवाशील आदि वह संस्कारों से ही बन पाता है। यों तो संस्कारों का क्षेत्र बहुत व्यापक है। माता-पिता द्वारा, मुख्यतः माता द्वारा जो संस्कार पड़ जाते हैं, वे जीवन भर अमिट और कारगर होते हैं और मृत्यु पर्यंत व्यक्ति का साथ देते हैं। माता-पिता द्वारा दिए गए संस्कार ही व्यक्ति को जीवन की दिशा देते हैं।

कांतिलाल मांडोत, नई दिल्ली

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मैल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: response@jagran.com

संस्थापक- स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक- संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए; नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।
****

2.7 लाख टन रेयर अर्थ मैटेरियल का उत्पादन किया चीन ने वर्ष 2024 में, जो वैश्विक उत्पादन का लगभग दो-तिहाई हिस्सा था। विश्व के कुल रेयर अर्थ मैटेरियल माइनिंग में 70 प्रतिशत और रिफाइनिंग व प्रोसेसिंग में 85 प्रतिशत हिस्सेदारी चीन की है।

विक्रांत निर्मला सिंह
शोधार्थी, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राउरकेला

रेयर अर्थ मैटेरियल

वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के लिए बढ़ता खतरा

वर्तमान दुनिया की तकनीकी नींव माने जाने वाले 'रेयर अर्थ मैटेरियल' को लेकर चीन ने हाल ही में एक ऐसा कदम उठाया है, जिसने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को पूरी तरह से झकझोर दिया है। वस्तुतः चीन पर निर्भर देशों को अब सात प्रमुख रेयर अर्थ खनिजों के आयात के लिए विशेष लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। सर्वविदित है कि चीन का इन वस्तुओं पर एकाधिकार है। लिहाजा इन दुर्लभ धातुओं की आपूर्ति पर प्रतिबंध का निर्णय केवल आर्थिक चिंता नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए यह एक गंभीर प्रश्न बन गया है

प्रतीकात्मक

तकनीक पर निर्भर या आधारित आज की दुनिया 'रेयर अर्थ मैटेरियल' यानी दुर्लभ धातुओं के बिना अधूरी है। रेयर अर्थ धातुएं जैसे डिस्प्रोसियम, टर्बियम, नीओडिमियम, लैंथेनम और सेरियम का इस्तेमाल आज इलेक्ट्रानिक उपकरणों, स्मार्टफोन, पवन टरबाइन, इलेक्ट्रिक गाड़ियों और मिसाइल टेक्नोलाजी तक में इस्तेमाल होती हैं। ऐसे में चीन द्वारा इनके व्यापार के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के कदम ने न केवल पूरी दुनिया को चौंका दिया है, बल्कि इस धारणा को भी तोड़ दिया है कि वह वैश्विक व्यवस्था से अलग-थलग होता जा रहा है। एक झटके में, चीन ने इन धातुओं की आपूर्ति को हथियार बनाकर पूरी दुनिया को उनकी सप्लाई पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दिया। आज यह वैश्विक चर्चा का विषय बन गया है कि रेयर अर्थ मैटेरियल के लिए चीन पर इतनी निर्भरता क्यों है।

'रेयर अर्थ मैटेरियल' पर चीन के सप्लाई चेन नियंत्रण को समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि इन धातुओं पर उसका वर्चस्व कैसे बना। असल में ये दुर्लभ धातुएं केवल चीन में ही नहीं पाई जातीं, लेकिन इनकी माइनिंग और प्रोसेसिंग एक कठिन और खर्चीला काम है। चीन ने लंबे समय से इस क्षेत्र में निवेश, नवाचार और पूंजी के दम पर ऐसी बढ़त बना ली है कि चाहकर भी दुनिया अगले एक दशक तक बिना चीन के कुछ नहीं कर सकती। चीन दुनिया की कुल रेयर अर्थ मैटेरियल माइनिंग में लगभग 70 प्रतिशत और रिफाइनिंग तथा प्रोसेसिंग में 85 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखता है। दुनिया का कोई देश इस स्थिति के करीब भी नहीं है। उदाहरण के तौर पर, वर्ष 2024 में चीन ने दो लाख 70 हजार टन रेयर अर्थ मैटेरियल का उत्पादन किया, जो वैश्विक उत्पादन का लगभग दो-तिहाई हिस्सा था।

चीन के इस एकाधिकार के पीछे दो प्रमुख कारण हैं। पहला, चीन ने 1986 से 2020 के बीच दुनियाभर की रेयर अर्थ खदानों में रणनीतिक निवेश किया है। दक्षिण अफ्रीका और म्यांमार जैसे क्षेत्रों की कई खदानों पर उसका नियंत्रण है। दूसरा, चीन ने रेयर अर्थ मैटेरियल की प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग तकनीक को दुनिया के साथ कभी भी साझा नहीं किया। चीन भविष्य की आवश्यकताओं को भली-भांति समझता था और उसने प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग के लिए अन्य देशों को अपने ऊपर निर्भर बनाए रखा।

भारत में रेयर अर्थ मैटेरियल : भारत दुर्लभ खनिजों के मामले में एक समृद्ध देश है। हमारे पास लगभग 69 लाख मीट्रिक टन रेयर अर्थ खनिजों का भंडार है, जो हमारे देश को दुनिया के शीर्ष पांच देशों में शामिल करता है। देश में रेयर अर्थ तत्वों के प्रमुख स्रोत विशेष रूप से मोनाजाइट के रूप में मिलते हैं। मोनाजाइट एक प्रकार की खनिज रेत है, जिसमें थोरियम सहित कई दुर्लभ तत्व मौजूद होते हैं। अनुमान है कि विश्व के कुल तटीय बालू खनिज भंडार का 35 प्रतिशत भारत के पास है। यह खनिज मुख्य रूप से भारत के समुद्री तटों पर पाया जाता है, जैसे आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल।

लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि इतने बड़े भंडार होने के बावजूद भारत का रेयर अर्थ उत्पादन काफी सीमित है। वर्ष 2024 में भारत ने केवल 2,900 मीट्रिक टन का उत्पादन किया। इसके अलावा, एक बड़ी चुनौती देश के आटोमोबाइल और इलेक्ट्रानिक्स उद्योगों की स्थायी चुंबकों की जरूरत से जुड़ी है। भारत में फिलहाल रेयर अर्थ से स्थायी चुंबक बनाने का कोई भी कारखाना मौजूद नहीं है। इसी कारण आटोमोबाइल और इलेक्ट्रानिक्स क्षेत्र की लगभग सभी आवश्यकताएं आयात के माध्यम से पूरी की जा रही हैं। भारत के पास विशाल भंडार तो हैं, लेकिन प्रसंस्करण और उत्पादन क्षमता के अभाव में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में उसकी भूमिका अब भी सीमित बनी हुई है।

भारत की तैयारी : भारत ने इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए हाल के वर्षों में कई नीतिगत पहलें की हैं। सबसे पहले, वर्ष 2023 में महत्वपूर्ण खनिजों की पहली राष्ट्रीय सूची जारी की गई, जिसमें भारत ने 30 खनिजों को ''क्रिटिकल मिनरल'' घोषित किया। इसके बाद, सरकार ने खनन और खनिज नीति में व्यापक बदलाव करते हुए वर्ष 2023 में खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम में संशोधन किया। इस संशोधन के अंतर्गत अब निजी क्षेत्र को भी रेयर अर्थ तत्वों की खोज और खनन में भागीदारी की अनुमति दी गई है। दशकों तक यह क्षेत्र एटमिक एनर्जी एक्ट के अंतर्गत केवल सरकारी नियंत्रण में था। सरकार ने अब उच्च मूल्य वाले उत्पादों की मूल्य श्रृंखला विकसित करने के उद्देश्य से वित्तीय प्रोत्साहन योजनाएं भी तैयार की हैं। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत अब दुर्लभ खनिजों पर आधारित घटकों और स्थायी चुंबकों के देश में निर्माण को प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव है। सरकार लगभग पांच हजार करोड़ रुपये के बजट के साथ इस नई योजना की रूपरेखा पर कार्य कर रही है, जिसका उद्देश्य रेयर अर्थ धातुओं और उनसे बनने वाले मैग्नेट का स्वदेशी उत्पादन बढ़ाना है। अप्रैल 2025 में सरकार ने एक व्यापक पहल के रूप में 'राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन' को भी स्वीकृति प्रदान की है। इस मिशन के लिए 16,300 करोड़ रुपये का बजटीय प्रविधान किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य देश में महत्वपूर्ण खनिजों की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला का विकास करना है, जिसमें खोज, खनन, प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण जैसे सभी चरण शामिल हैं।

भारत रेयर अर्थ तत्वों की आपूर्ति में चीन पर निर्भरता कम करने के लिए ठोस रणनीति अपना रहा है। सबसे पहले, सरकार ने घरेलू संसाधनों को देश में ही उपयोग करने की नीति पर जोर दिया है। इसी के तहत सरकारी उपक्रम आइआरईएल को जापान को किए जा रहे निर्यात को रोकने का निर्देश दिया गया, ताकि संसाधन देश के भीतर ही प्रसंस्करण और उपयोग के लिए उपलब्ध रहें। इसके साथ ही भारत दुर्लभ स्थायी चुंबकों का आपात भंडार तैयार कर रहा है और घरेलू उत्पादन को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए 'मेड-इन-इंडिया' मैग्नेट पर लागत सहायता योजना पर काम कर रहा है। भारत की एक महत्वपूर्ण तैयारी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गठजोड़ और समन्वय को मजबूत करने की दिशा में भी है। वर्ष 2023 में भारत, अमेरिका की अगुवाई में गठित मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप का 14वां सदस्य बना। इस साझेदारी का उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों की एक सुरक्षित, विश्वसनीय और विविध आपूर्ति श्रृंखला विकसित करना है, जिसमें आस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान जैसे देश आपसी सहयोग से कार्य कर रहे हैं। भारत इस पहल में शामिल होने वाला पहला विकासशील देश है।

क्वाड बन सकता है एक बड़ा वैकल्पिक स्रोत

चतुर्भुज सुरक्षा संवाद यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलाग (क्वाड) मंच आज दुनिया का ऐसा फोरम है जो रेयर अर्थ मैटेरियल के क्षेत्र में चीन को वास्तविक चुनौती देने की क्षमता रखता है। हाल के वर्षों में भारत, अमेरिका, आस्ट्रेलिया और जापान के बीच खनिज सहयोग लगातार बढ़ा है। ऐसे में यह मंच एक नई और सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखला स्थापित कर सकता है। वर्तमान में आस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत के पास रेयर अर्थ सहित अन्य महत्वपूर्ण खनिजों के विशाल भंडार मौजूद हैं, वहीं जापान के पास उन्नत तकनीक और निवेश की मजबूत क्षमता है। यदि अमेरिका, भारत और आस्ट्रेलिया मिलकर खनिजों की आपूर्ति सुनिश्चित करें और जापान वित्तीय तथा तकनीकी सहयोग प्रदान करे, तो वैश्विक आपूर्ति तंत्र की दिशा बदल सकती है। इस दिशा में भारत की भूमिका निर्णायक है, बशर्ते वह उत्पादन, रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग के लिए एक सक्षम केंद्र के रूप में विकसित हो। भारत न केवल कच्चे माल के स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण है, बल्कि सस्ता और कुशल उत्पादन भी उसकी सबसे बड़ी ताकत है। इस सहयोग से न केवल क्वाड देश, बल्कि पूरा इंडो-पैसिफिक क्षेत्र चीन पर अपनी निर्भरता को धीरे-धीरे कम कर सकता है।

वर्तमान घटनाक्रम ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि भविष्य की वैश्विक राजनीति केवल तेल और गैस के इर्द-गिर्द नहीं घूमेगी, बल्कि दुर्लभ धातुओं की आपूर्ति और नियंत्रण भी प्रभावशाली मुद्दे होंगे। आज चीन की रेयर अर्थ मैटेरियल पर दशकों से बनी मोनोपाली को तोड़ना आसान नहीं है, लेकिन यह असंभव भी नहीं है। इसके लिए वैश्विक स्तर पर समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है। सबसे पहले, उन देशों को जिनके पास रेयर अर्थ खनिजों का भंडार है, जैसे आस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत, ब्राजील और वियतनाम, उन्हें अपने खनन और प्रसंस्करण ढांचे को मजबूत करना होगा। इसके लिए सार्वजनिक और निजी निवेश, तकनीकी सहयोग और नीति समर्थन की जरूरत होगी। दूसरा, प्रसंस्करण संयंत्रों को केवल चीन तक सीमित रखने के बजाय अन्य देशों में भी विकसित करना होगा, ताकि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में विविधता लाई जा सके।

तीसरा, पुराने इलेक्ट्रानिक वस्तुओं और मशीनों से रेयर अर्थ तत्वों का पुनर्चक्रण बढ़ाना एक सस्ता एवं पर्यावरण-सम्मत विकल्प हो सकता है, जिस पर जापान और यूरोप पहले ही काम कर रहे हैं। इसके अलावा, तकनीकी शोध और नवाचार के जरिये वैकल्पिक सामग्रियों या नई तकनीकों को विकसित करना भी जरूरी है, ताकि लंबे समय में इन तत्वों पर निर्भरता कम हो सके। अंतरराष्ट्रीय मंचों जैसे मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप और क्वाड के माध्यम से साझा निवेश, ज्ञान-विनिमय और रणनीतिक भंडारण की योजनाएं बनाकर सहयोगी देश चीन से दबाव कम कर सकते हैं। यदि ये कदम योजनाबद्ध ढंग से उठाए जाएं, तो दुनिया एक स्थिर, पारदर्शी और चीन के वर्चस्व से मुक्त आपूर्ति व्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ सकती है।

(विक्रांत निर्मला सिंह)

खरी-खरी

देवी कोरोना

राजेंद्र कुमार सिंह

जब से यह पता चला कि कोरोना नाम की एक निष्पक्ष देवी मृत्यु लोक में पैर पसारकर एक बार फिर से आम जनता को निगल रही है, तब से बड़े-बड़े पैसे वाले लोग भी हैरान हैं। एक बार फिर से हर जगह खौफ व डर का माहौल बनना शुरू हो गया है। जब यह आती है तो पैसे वाले लोग भी डरकर बचने के कुछ न कुछ उपायों के बारे में सोचने लगते हैं। क्योंकि उसकी नजर में सभी समान हैं। वह स्पष्ट नीति अपना कर अपना प्रतीति करा जाती है। उसकी नजर में सब पर एक समान काम करती है। वह आग और पानी की तरह किसी के साथ भेदभाव नहीं रखती, अपने प्रभाव से सब पर दबाव बनकर चलती है। और जो बेखौफ होकर स्वांग रचकर ऐंठ कर चलने वाले अपने अहं में चूर होकर अनर्गल प्रलाप अलापते हैं, उनका वहम शीघ्र ही तोड़ देती है। क्योंकि जब यह आती है इसका वेग काफी तेज होता है। आंधी तूफान भी उसके सामने कुछ नहीं। इसके आगमन मात्र से ही यह सारी अर्थव्यवस्था तहस नहस हो जाती है।

नया रिश्ता जहां जोड़ने की बात होती है, उसे भी यह पेंडिंग में डाल देती है। शादी-विवाह का पुनीत कार्य थम जाता है। इसमें बचाव की भावना अधिक और एक दूसरे के सटाव का भाव दूर हटाव की भावना कायम हो जाता है। इसलिए आदमी और औरत एक साथ आ नहीं सकते हैं। शादी का मामला तो पेंडिंग में पड़ जाता है जिसमें मानवीय प्रोडक्शन पर आंच आना स्वाभाविक है। इसलिए इस दुरुह काल में मानवीय प्रोडक्शन बंद हो जाता है। इसके आने से आबादी भी कुछ हद तक कंट्रोल होती है। लेकिन इसकी एक बड़ी खामी यह है कि अर्थव्यवस्था को बीच मझधार में रोक देती है।

कोरोना के आने से दवा उद्योग व डाक्टरी धंधा कभी मंदा नहीं रहता बल्कि उल्टा कालाबाजारी का गोरखधंधा शुरू हो जाता है। कहीं आने जाने पर प्रतिबंध लग जाता है, क्योंकि आने जाने से कोरोना वायरस एक दूसरे के यहां जाकर अपना बाजार तैयार करके तहलका मचा सकता है। अतः कोरोना देवी के आगमन से सब कुछ अस्त-व्यस्त हो जाता है। बस अपनी तरफ से संभलकर रहना पड़ता है। मैं तो बचकर हूं, आप भी बचकर रहिए।

पोस्ट

समाजवाद उस पोलियो की तरह है जो तब दोबारा दस्तक देने लगता है, जब लोग यह भूल जाते है कि पिछली बार इसने कितना नुकसान पहुंचाया था।
गैरी कास्पारोव@Kasparov63

भारत का यह कहना कि वह चाबहार बंदरगाह को अपनी सुविधा के अनुरूप इस्तेमाल करेगा, वाशिंगटन को एकदम सटीक संदेश है।
दिव्या जैन@DivaJain2

सोचिए कि 50 साल पहले एक अखबार को अपने संपादकीय में यह लिखना पड़ा कि आलू-बैंगन की सब्जी कैसे बनाएं, क्योंकि हर समाचार-विचार की जांच सरकारी बाबू करने में लगे हुए थे। आज के दौर की तुलना उस भयावह दौर से नहीं हो सकती। आज तो कुछ भी बोल सकते हैं।
अनुरंजन झा@anuranjanj

वंदे भारत एक्सप्रेस में सीट को लेकर भाजपा विधायक के समर्थकों का उत्पात असल में सत्ता के अहंकार का निर्लज्ज प्रदर्शन है। उम्मीद है भाजपा इस विधायक पर कड़ी कार्रवाई करेगी, लेकिन क्या भाजपा ऐसा कोई कदम उठा पाएगी जो कड़ा संदेश दे सके?
प्रियंका चतुर्वेदी@priyankac19

जागरण जनमत — कल का परिणाम

क्या ईरान और इजरायल के बीच सैन्य टकराव खत्म समझा जाए?

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल
क्या सीबीएसई द्वारा दसवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा दो बार कराने का फैसला सही है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

शुभमंगल हो यात्रा पूरा हो अभियान,
है शुभांशु पर कर रहा देश आज अभिमान।
देश आज अभिमान गया है अपना बंदा,
गाड़ेगा अब जाय वहां भारत का झंडा।
अंतरिक्ष में आप करेंगे वह गुत्थी हल,
जिससे हो कल्याण और सबका शुभमंगल!
- ओमप्रकाश तिवारी

धनंजय प्रताप सिंह
राज्य ब्यूरो प्रमुख, मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश डायरी

जनता के मुद्दों से भटकती कांग्रेस

कमल नाथ सरकार के 15 महीने के कार्यकाल को छोड़ दें, तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस लगभग दो दशक से सत्ता से बाहर है, लेकिन बतौर विपक्ष जनता से करीबी, जनहित के मुद्दों पर अब तक उसकी सक्रियता दिखाई नहीं देती। मुश्किल यह भी है कि उन मुद्दों पर आगे बढ़ जाती है, जिसकी प्रासंगिकता प्रभावशील नहीं होती। इसका ताजा उदाहरण बुधवार को सामने आया, जब भाजपा 'आपातकाल के 50 वर्ष' पर कांग्रेस पर पूरी तरह हमलावर थी, वहीं कांग्रेस के नेता ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में बाबा साहब आंबेडकर की मूर्ति लगाने की मांग के समर्थन में वहां उपवास कर रहे थे।

केवल आपातकाल के मुद्दे पर सीमित रहने वाली भाजपा को बाबा साहब के बहाने कांग्रेस पर हमला करने का एक और बड़ा मुद्दा हाथ लग गया। मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने बाबा साहब आंबेडकर के प्रति कांग्रेस के रवैये को लेकर इंटरनेट मीडिया पर अपना बयान जारी किया। कांग्रेस को उन्होंने न केवल आंबेडकर विरोधी ठहराया, बल्कि इतिहास में दर्ज कांग्रेस के आंबेडकर विरोधी एक-एक पन्ने को खोल कर रख दिया। जैसा कि राजनीतिक चलन है, कांग्रेस को भी जवाब देना था, लेकिन आपातकाल, संविधान और उसके बाद आंबेडकर के मुद्दे पर कमजोर तैयारी के चलते कांग्रेस बचाव ही करती दिखी।

वस्तुतः मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित अनेक वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में ग्वालियर में उपवास का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस ने ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में डा. भीमराव आंबेडकर की मूर्ति की स्थापना की मांग का समर्थन किया। इस मांग के समर्थन को लेकर कांग्रेस ने शायद गलत दिन का चुनाव कर लिया। 25 जून, 1975 की रात तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने देश में आपातकाल लागू किया था, जिसे लोकतंत्र और संविधान पर सबसे बड़ा आघात माना गया है। ऐसे अवसर पर कांग्रेस के नेता संविधान और बाबा साहब आंबेडकर की बात करें, तो स्थिति उनके अनुकूल होना कैसे संभव हो सकता है? कांग्रेस मध्य प्रदेश में विपक्ष की भूमिका में है और उसे गरीब, किसान, युवा, व्यापारी, महिलाओं के मुद्दों के साथ सुरक्षा, आर्थिक प्रगति जैसे विषयों पर आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन इन मुद्दों पर कांग्रेस कभी न सड़क पर दिखाई देती है, और न सदन में। पिछले दो दशक में विधानसभा की कार्यवाही देखें, तो कांग्रेस के विरोध पर जनता का भी ध्यान नहीं जाता। वह इसे राजनीतिक कर्मकांड और परंपरा मान चुकी है।

ग्वालियर हाई कोर्ट परिसर में आंबेडकर की मूर्ति लगाने की मांग के समर्थन में धरनारत कांग्रेस नेता। फाइल

जीतू पटवारी के प्रदेश कांग्रेस की कमान संभालने के बाद अब तक कोई सफल धरना, प्रदर्शन, सत्याग्रह आदि नहीं हो सके हैं। इसे लेकर संगठन के बाहर भी आम जनता में उनके नेतृत्व पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। कांग्रेस ने लाड़ली बहना योजना को लेकर सवाल किया, जिसे सरकार ने दीपावली से प्रत्येक हितग्राही को डेढ़ हजार रुपये देने की घोषणा से बेअसर कर दिया। मूंग और उड़द के समर्थन मूल्य पर खरीदी पर भी सरकार ने बड़ा निर्णय लेकर कांग्रेस के हाथ से मुद्दा छीन लिया। बेरोजगारी के बड़े मुद्दे को कांग्रेस हाथ नहीं लगाती, जबकि सरकार सरकारी के अलावा निवेश के माध्यम से निजी क्षेत्र में भी लाखों नौकरियां देने का वादा कर रही है। कांग्रेस अभी संगठन की मजबूती और सरकार से मुकाबले के दोनों मोर्चों पर एक साथ जूझ रही है। ऐसे में उसके पास उन मुद्दों का लगातार अभाव दिख रहा है, जो उसे धीरे-धीरे मजबूत होने के साथ प्रभावशाली बनाए।

कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश उन चुनिंदा राज्यों में शुमार है, जहां वह प्रभावशाली विपक्ष के रूप में मौजूद है, लेकिन आपसी कलह, गुटबाजी और नई-पुरानी पीढ़ियों की खींचतान में यह अपना असर दिखने में कहीं पीछे रह जा रही है। ऐसी स्थितियों ने कांग्रेस के हाथों से उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे मजबूत राज्य छीन लिए थे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को अपनी जड़ें और गहरी रखते हुए इसे मजबूत भी करना होगा। इन दिनों जीतू पटवारी कांग्रेस को मजबूत करने के साथ युवाओं को मौका देने पर जोर दे रहे हैं। राहुल गांधी ने भी विगत दिनों भोपाल आकर लंगड़े, बूढ़े और बारात के घोड़ों के रूप में अनुपयोगी रह गए नेताओं की तुलना करके उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने के संकेत दिए थे।

हालांकि अभी दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह के अलावा किसी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन किसी युवा नेता को मौका मिला हो यह भी दिखाई नहीं देता। कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावितों की संख्या मध्य प्रदेश में अच्छी खासी है, जिसे लगभग 38 प्रतिशत वोट बैंक के रूप में हर विधानसभा चुनाव में देखा जाता है। अपनी विचारधारा के साथ चलते हुए कांग्रेस यदि जनता के मुद्दों को गहराई से समझ कर सरकार से सीधा मोर्चा लेती है, तो आने वाले दिनों में न केवल पार्टी पुनर्जीवित हो उठेगी, बल्कि अपना लंबा वनवास खत्म करने का भी सपना साकार कर सकेगी।

हिमाचल प्रदेश डायरी

शिक्षा जगत और मुख्यमंत्री की स्कूल सभा

नवनीत शर्मा
राज्य संपादक, हिमाचल प्रदेश

शिक्षा मंत्रालय की ओर से जिला स्तरीय परफार्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जारी होने से दो दिन पहले की बात है। यह बादलों से घिरी एक पर्वतीय सुबह थी, जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कुल्लू जिले के एक दूरस्थ क्षेत्र बागा सराहन के सरकारी स्कूल की सहमी हुई प्रार्थना सभा में पहुंच गए। उन्होंने पूछा कि देश के राष्ट्रपति कौन हैं। दस जमा दो स्कूल था। बड़े बच्चों में से एक ने हिम्मत के साथ जवाब दिया, 'नरेन्द्र मोदी!' मुख्यमंत्री ने यही प्रश्न साथ खड़े, प्राथमिक स्कूल के बच्चों से पूछा तो उनमें से, कदकाठी में भी बहुत छुटकी सी मुनिया ने कहा, 'श्रीमती द्रौपदी मुर्मु।' बाद में कुछ उच्चों ने देश की राजधानी शिमला को बताया, कुछ ने नई दिल्ली। कुल मिलाकर प्राथमिक स्कूल के अध्यापक को शाबाशी मिली और वरिष्ठ माध्यमिक वर्ग के कार्यवाहक प्रधानाचार्य को यह नसीहत कि बच्चों को सामान्य ज्ञान भी सिखाएं।

अब इस बात पर कई मत आए कि यह संवाद सार्वजनिक रूप से होना चाहिए था या नहीं। यह वीडियो बनना चाहिए था या नहीं। कुछ ने कहा कि मुख्यमंत्री ने हिमाचल के शिक्षा मंत्री के प्रयासों की पोल खोल दी। कुछ ने इसे शिक्षा के प्रति गंभीरता का प्रमाण कहा। जितने लोग, उतने मत। सब स्वतंत्र हैं। हालांकि अधिसंख्य का मत यह था कि यह अभ्यास बहुत अच्छा है। क्योंकि इसमें रत्ती भर संदेह नहीं है कि विद्यार्थियों का सामान्य ज्ञान उत्तम होना ही चाहिए। उससे तीन दिन पहले ही हिमाचल के शिक्षा विभाग ने एक बैठक कर यह निर्णय किया था कि जिन स्कूलों का वार्षिक परीक्षा परिणाम 25 प्रतिशत से कम आया है, वहां के संबंधित अध्यापक, मुख्य अध्यापक या प्रधानाचार्य को दंडित किया जाए।

कुल्लू जिले में सराहन स्कूल की प्रार्थना सभा में पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। फाइल

अब केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की रपट बताती है कि 2022-2023 में कांगड़ा को छोड़ प्रदेश के सब जिले प्रचेष्ट-2 में स्थान बना पाए हैं। प्रचेष्ट का क्रम उत्कृष्ट, उत्तम-1 और उत्तम-2 के बाद आता है। यानी कुल मानकों में जो 41 से 50 प्रतिशत के बीच रहे हैं। कांगड़ा प्रचेष्ट-1 में 51 से 60 प्रतिशत के बीच था। वर्ष 2023-2024 में जनजातीय जिलों किन्नौर और लाहुल-स्पीति को छोड़ सब जिले सुधार करते हुए प्रचेष्ट-1 में आ गए। निश्चित रूप से शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने अपने पूर्ववर्ती की तरह एक बार भी नहीं कहा कि शिक्षा विभाग तो स्थानांतरणों का विभाग है, कृपया मुझे बदल दें। उन्होंने कई अच्छे निर्णय किए हैं, जिनमें युक्तीकरण सबसे ऊपर है। युक्तीकरण के विरोध के राजनीतिक कारण बेशक हों, लेकिन यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि जिस सराहन स्कूल में कार्यवाहक प्रधानाचार्य 'जी सर' कह कर मुख्यमंत्री की बात सुन रहे थे, यह नहीं कह सके कि स्कूल में प्रधानाचार्य समेत नौ पद रिक्त हैं।

आखिर ऐसी क्या राजनीतिक विवशता होती है कि प्रदेश के कई जिला शिक्षा प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक ही प्रवक्ताओं का काम कर रहे हैं? ऐसा क्यों हो कि उप निदेशक और निदेशक कार्यालयों में ऐसे लोगों की भीड़ है, जिनकी वास्तविक आवश्यकता स्कूलों में है? एक प्रशासक मित्र के पास महिला आई और बोली कि हमें कोई सुन नहीं रहा है। रोते हुए कहा कि वह एकल नारी हैं और नौकरी नहीं मिल रही। अब कहीं चपरासी की नौकरी निकली है। दसवीं तक शिक्षा पाई है, 48 प्रतिशत अंक हैं। प्रशासक मित्र ने कहा कि चलिए, कह देते हैं। संबंधित कार्यालय में पता किया तो पाया कि वहां जो आवेदन आए हैं, उनमें एक 99 प्रतिशत अंकों वाला भी है। एक पीएचडीधारक भी है जो चपरासी बनना चाहता है। हम इतने वर्षों में हिमाचल प्रदेश को यहां ले आए हैं।

खैर, मुख्यमंत्री ने जब सराहन स्कूल में बच्चों से पूछा कि क्या बनना चाहते हो तो अधिसंख्य ने जवाब में कहा - सैनिक! जब मुख्यमंत्री ने पूछा कि मंत्री या मुख्यमंत्री बनना चाहोगे तो किसी ने रुचि नहीं दिखाई। बच्चे यह नहीं कह पाए कि मंत्री क्यों नहीं बनना चाहते। यह तो बच्चे मन के सच्चे ही बता सकते हैं कि क्यों का जवाब न देकर उन्होंने राजनीतिकों का मान रखा या कोई अन्य कारण था। हां, यह अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री ने मोबाइल फोन प्रयोग न करने की नसीहत दी। क्योंकि बच्चे मोबाइल फोन से बचेंगे तो कुछ सोच पाएंगे और जंक फूड से बचेंगे तो फौजी बन पाएंगे।

अच्छा यह है कि अब शिक्षा बोर्ड की कारगुजारी पर भी ध्यान जाएगा। होना तो यह चाहिए कि स्वास्थ्य विभाग का अर्थ केवल डाक्टर और उनकी मांगें या स्थानांतरण न होकर केवल स्वास्थ्य हो। साथ ही शिक्षा विभाग का अर्थ शिक्षक संघों की राजनीति या स्थानांतरण नहीं, केवल शिक्षा हो। इस बीच अच्छा लगा कि सरकारी स्कूलों की प्रार्थना सभा में समाचार पढ़ना अनिवार्य किया गया है। पहले भी यह अभ्यास था, परंतु अब यह सबके लिए है।

****